>

Title : General discussion on the Budget (General) for 2008-2009 (Discussion Not Concluded).

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, यूपीए सरकार का यह आखिरी बजट है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभी सदस्य शांत रहिए। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति जी, यूपीए सरकार का यह आखिरी बजट है और 4 साल पहले उन्होंने जो-जो वायदे किये थे, उन सारे वायदों को पूरा करने का यह आखिरी अवसर है।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि चिदम्बरम साहब ने आंकड़ों के हेरफेर में और कुछ लोक-लुभावनी बातें करके बजट के असली चेहरे को छिपाने की कोशिश की है। मेरा यह आरोप है कि यह बजट इंफ्लेशनरी है, भीषण महंगाई बढ़ाने वाला है, एंटी-डैवलपमेंट बजट है, एंटी-प्रोडक्टिव है। यह प्रगति विरोधी और विकास विरोधी बजट है और भीषण महंगाई बढ़ाने वाला बजट है।

वित्त मंत्री जी ने दावा किया है कि वे फिसकल डैफिसिट और रेवेन्यू डैफिसिट को 1 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत पर ले आए हैं और पहले से उन्होंने इसे कम किया है। सभापति जी, यदि आप आंकड़ों को देखें, तो उन्होंने 1 प्रतिशत रेवेन्यू डैफिसिट को कम करके बताया है कि उसका कुल घाटा 55,184 करोड़ का है और जीडीपी इस हिसाब से 55 लाख 18 हजार 400 करोड़ रुपये होती है। उसमें से 1,33,287 करोड़ रुपया फिसकल डैफिसिट में रखा गया है जिसे यह कहा गया कि यह 2.3 प्रतिशत के करीब आता है।

सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब उन्होने 60 हजार करोड़ रुपया किसानों का ऋण के रूप में माफ किया है तो वह बजट घाटा कहां गया? उन्होंने कहा था कि वह और प्रधानमंत्री इस बारे में सदन को बतायेंगे। यह फिसकल डैफिसिट में आना चाहिये था। अगर 60 हजार करोड़ रुपया घाटा आता है तो कुल कितना फिसकल डैफिसिट बनता है, उसका अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। परन्तु, यह छल पहली बार नहीं किया जा रहा है। 60 हजार करोड़ रुपये के घाटे को बाद में बांड्स में डाल कर रखा जायेगा। जब किसानों के ऊपर बोलने का अवसर आयेगा, तो मैं उसका उल्लेख करूंगा। इसी तरह 1 लाख 22 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ऑयल सब्सिडी में किया गया है जिसे घाटे में नहीं दिखाया गया है, ये उस पैसे को बांड्ज में डालेंगे या दूसरे तरीके से बैंकों पर डाल देंगे या तेल कम्पनियों के बांड्स में लगाकर कुल फिसकल डैफिसिट 1 लाख 82 हजार करोड़ रुपया और हो जायेगा। अगर यह धन इसमें शामिल किया जायेगा तो कुल फिसकल डैफिसिट 5.7 प्रतिशत की दर से एक लाख 33 हजार 287 करोड़ रुपये के बजाय यह 3 लाख 15 हजार 287 करोड़ रुपया हो जायेगा। इसके अलावा छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट आनी है जिसे 2006 से लागू किया जाना है। कर्मचारियों के ऐरियर्स होंगे। यह इसलिये कि पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें 1996 से लागू की गई थीं। अगर यह सब खर्चे डालें तो मेरा वित्त मंत्री पर आरोप है कि जितना उन्होंने ग्रोथ रेट 8.7 प्रतिशत दिखाया है., उससे ज्यादा फिसकल डैफिसिट बनता है। अब जितना ज्यादा फिसकल डैफिसिट होगा तो महंगाई बढ़ेगी। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। मैं इस महंगाई के बारे में भी जिक्र करना चाहता हूं.।

सभापति महोदय, सी एंड ए.जी. ने इस बात को बहुत जोर से उठाने की कोशिश काफ - "Is PC underplaying Government fiscal deficit?" इस गवर्नमेंट के वित्त मंत्री जानबूझकर फिसकल डैफिसिट में फजिंग करके आंकड़ों को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आडिटर जनरल ने इस बात को कहा है कि जहां फिसकल डैफिसिट कम होने की बात कही गई है, वह कम नहीं बल्कि और ज्यादा हो गई है। इसलिये मैंने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है। इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, जब बाजार में ज्यादा पैसा आयेगा, मुद्रास्फीति की दर कितनी बढ़ेगी, उसका आप अनुमान लगा सकते हैं।

सभापति जी, वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारे यहां ग्रोथ रेट 8.7 प्रतिशत होगा और क्रेडिट लेने की कोशिश की गई है परन्तु यह ग्रोथ रेट किस के पास है? आज हिन्दुस्तान में आयकर देने वाले कितने हैं - दो करोड़, तीन करोड़। इससे और कम हो जायेंगे। यहां एक लाख 50 हजार की इनकम से नीचे हैं तो बाकी जो लोग बचते हैं, अगर मान लिया जाये कि दो करोड़ किसानों को लाभ होगा तो शेष 25 करोड़ परिवारों की क्या स्थिति होगी?उनके लिये इस बजट में क्या है? केवल भीषण महंगाई, डेवलेपमेंट का रुकना - ये सब उस हिस्से के बीच में आ जाती हैं। इसलिये उन लोगों के लिये इस बजट में कुछ नहीं है। अगर नेशनल सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट देखें तो उसमें बताया गया है:

> "India's economy may be growing rapidly but about a third of its rural population or more than 200 million people still live on Rs.12 – 26 cents a day or less according to the National Sample Survey Organisation. Some 10 per cent of rural population across India survived on just Rs.9 a day. The poor in India cities appear to be slightly better with 30 per cent of people spending Rs.19 a day but 10 per cent of the urban poor population have to live on just Rs.13 a day."

इसमें पूरे हिन्दुस्तान की गरीबी को दिखाने की कोशिश की गई है। यह ठीक है कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोगों में चार भारतीय हैं जो खरबपति हैं। इसके अलावा हमारे देश में करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है परन्तु 8.7 प्रतिशत ग्रोथ रेट का फायदा किसको हो रहा है? गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। रेहड़ी, पटरी, खोंमचा लगाने वाले और स्लम्स में रहने वाले या गांव में लेबर का काम करने वाले लोगों की आमदनी में कोई वृद्धि नहीं हुई है।[s3]

उनके ऊपर जो सर्विस टैक्स लगाया, उसकी मार पड़ रही है और उससे ये ज्यादा गरीब हो गए हैं। मैं किसी अन्य का जिक्र नहीं करता, श्री मणिशंकर अय्यर साहब हमारे केन्द्र के मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा - "When you talk of 9.2 per cent growth rate, it becomes a statistical abstraction. 0.2 per cent of our people are growing at 9.2 per cent." प्वाइंट दो परसैंट, ये सिर्फ सारा का सारा पैसा उन्हें जा रहा है। "But there is a very large number whose growth rate is perhaps down to 0.2 per cent." उन्हें प्वाइंट दो परसैंट, एक परसैंट का भी पांचवा हिस्सा, उनके पास उसका फायदा नहीं जा रहा। सारा का सारा फायदा कुछ थोड़े से चुने हुए अरबपति-खरबपति लोगों के हाथ में जा रहा है। जब से यूपीए सरकार आई है तब से अमीर और गरीब की खाई पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

सभापति महोदय, आम आदमी के नाम पर चुनाव जीतने वाली इस सरकार ने सबसे बड़ा विश्वासघात इस देश की जनता के साथ जो किया है, वह भीषण महंगाई का है। ऐसी भीषण महंगाई, इसके पहले के आंकड़े मैं आपको दूं, वह तो ठीक है, परन्तु लगातार बजट बनने के बाद जो महंगाई बढ़ी है, उसके आंकड़े आप मेहरबानी करके देखने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, जिस दिन बजट पेश हुआ, उससे तीन-चार दिन पहले पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। बजट पास होने के एक दिन बाद स्टील के दाम दस परसैंट से ज्यादा बढ़ा दिए गए और समाचार पत्र में यह आया है - "Steel prices hit the roof. In an unprecendented move, the Rashtriya Ispat

Nigam Limited has hiked prices of steel rounds and wire rods from Rs. 5500/- to Rs. 7500/- per metric tonnes. With today's hike prices of MS rounds have gone up to Rs. 17,000 per metric tonnes in the past three months and because of this that millions of steel based micro, small and medium enterprises will be forced to shut jobs and many units will be forced to close their shops." स्टील का काम करने वाली सारी छोटी-छोटी मिलें समाप्त हो जाएंगी, यह इसमें कहा है - एक अन्य समाचार पत्र का शीर्षक है "Steel prices hike 10 per cent. FM calls for stability." एफएम साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि कीमतें स्थिर रखेंगे और स्टील प्राइसेस दस परसैंट बढ़ गई। अभी 23 फरवरी को जो सप्ताह समाप्त हुआ उसका समाचार अभी तीन दिन पहले यह आया - "Inflation rises to 5.02 per cent." यह पिछले दस महीने का रिकार्ड है। दस महीने में इतनी कीमतें नहीं बढ़ीं, ये बजट पहले की फीगर्स हैं कि बजट से पहले दस महीने में जितनी कीमतें थीं, उसमें सबसे ज्यादा कीमतें 5.02 परसैंट, होल सेल प्राइस इंडेक्स, मैं अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जिक्र नहीं कर रहा, वे इसके अंदर बढ़ गई। 5.02 परसैंट, दस महीने का रिकार्ड। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को बड़ी चिट्ठियां लिखीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े दावे किए और यह कहा कि वे मंहगाई रोकेंगे, पत्रों में तो लिख दिया कि महंगाई रोकनी चाहिए, यहां पर सीमेंट पर बढ़ी ड्यूटी और घर महंगे होंगे। सीमेंट, ब्रिक्स, उसमें जो रोड़ी डाली जाती है, सब की प्राइसेस बजट के बाद बीस परसैंट के करीब बढ़ी हैं। एक अन्य समाचार पत्र का शीर्षक है - बजट आने के बाद, होली नजदीक आते ही महंगाई बढ़ी।

सभापति महोदय, बजट के बाद दाम बढ़े हैं। बजट से पूर्व और बजट के बाद - अरहर दाल 36 रुपए से बढ़ कर 42 रुपए, उड़द दाल 30 रुपए किलो से बढ़ कर 35 रुपए किलो, मसूर दाल 38 रुपए से बढ़ कर 42 रुपए किलो, चना दाल 28 रुपए से बढ़ कर 35 रुपए किलो, रिफाइंड तेल 67 रुपए बढ़ कर 75 रुपए लीटर, सरसों का तेल 65 रुपए से बढ़ कर 75 रुपए, डालडा घी 60 रुपए से बढ़ कर 68 रुपए, मैदा 13 रुपए से 15 रुपए, यह बजट आने के बाद जो दाम बढ़े हैं। यह चार साल का पूरा का पूरा है, 24 मई 2004 को आप सरकार में आए थे तबके और अबके, उसके आंकड़े मैं यहां रखना चाहूंगा। अब आप मसालों के बजट से पूर्व और बाद के रेट देखिए - धनिया 58 रुपए से 71 रुपए, काली मिर्च 160 रुपए से 170 रुपए, हल्दी 38 रुपए से 45 रुपए और लाल मिर्च 50 से 55 रुपए।[rep4] सरसों का तेल 60 रुपए से 72 रुपए हो गया है। मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि आम आदमी की जरूरत की चीजें जैसे मैदा, चीनी, चाय, मकान बनाने के लिए सीमेंट, रोड़ी, ईंटें आदि कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जिसके दाम न बढ़े हों। यह दाम और ज्यादा बढ़ेंगे तथा और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।

सभापति महोदय, मई 2004 से फरवरी 2008 तक दामों में जो वृद्धि हुई है, उसके आंकड़े पढ़ने की बजाय सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। इस दौर में 20 परसेंट से 200 परसेंट तक महंगाई बढ़ी है। चार साल पहले आप इस नारे पर सत्ता में आए थे कि महंगाई कम करेंगे। आम आदमी की, गरीब आदमी की कमर किस तरह से महंगाई से टूट चुकी है, इसे आप देखें। आटा 10 रुपए किलो था, अब 18 से 20 रुपए किलो हो गया है। चावल 10 रुपए किलो थे, अब 30 रुपए किलो हो गए हैं। ब्रैड 8 रुपए की थी, अब 15 रुपए की हो गई है। चीनी 14 रुपए किलो थी अब 22 से 25 रुपए किलो हो गई है। ऐसे सभी आंकड़े मैं सभापटल पर रखना चाहता हूं। इस भयंकर महंगाई का असर किस पर पड़ेगा, आम आदमी और आम औरत पर इस महंगाई का असर पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि बजट आने के बाद कौन सी चीज सस्ती हुई है? सबसे पहले कारें सस्ती हुई। हर कार मेकर ने 16 हजार, 20 हजार, 25 हजार रुपए कम कर दिए। बजट आने के बाद शराब सस्ती हो गई। पानी महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया और जरूरत की चीजें ज्यादा महंगी हो गई। महंगाई ऐसा विश्वासघात है, महंगाई ऐसा अपराध है, जो कि इस सरकार को ले डूबेगी। यह देशव्यापी महंगाई है और सरकार ने जानबूझकर महंगाई को बढ़ने दिया है। महंगाई इस कारण नहीं बढ़ी कि कहीं भूचाल आ गया या फसल नष्ट हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो कमॉडिटी एक्सचेंज किया है, आपने सरमाएदारों को, जमाखोरों को, बड़े-बड़े कैपिटल हाउसिस को जो रिटेल में काम करने दिया और एफसीआई की बजाय इन लोगों को सारी चीजें कंट्रोल करने दीं और गेहूं का आयात किया, इन सभी कारणों से महंगाई बढ़ी। श्री मनमोहन सिंह जी ने यहां भाषण दिया, तो कहा कि किसानों को पैसे कम दिए गए, इसलिए महंगाई हुई है। अब हम किसानों को ज्यादा पैसा दे रहे हैं। क्या सीमेंट खेत में पैदा होता है, क्या स्टील खेत में पैदा होती है, क्या एल्यूमिनियम या दूसरी चीजें खेत में पैदा होती हैं? गेहूं को बाहर से इम्पोर्ट किया जाए और यहां हमारे किसानों की बात कही जाती है। यह महंगाई आपकी नीतियों के कारण बढ़ी है। इस बारे में इस सरकार का बहुत ही शर्मनाक इतिहास है।

महोदय, रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम का भी बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इसके बारे में शायद हमारे दोस्त जिक्र करना चाहते थे, राहुल गांधी जी ने उड़ीसा में क्या कहा, उसका जिक्र मैं यहां नहीं करना चाहता हूं, परंतु उन्होंने कहा था कि एक रुपए में से पांच पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं। राजीव गांधी जी ने कहा था कि एक रुपए में से 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि केवल पांच पैसे ही आम आदमी तक पहुंचते हैं। इसका मतलब यह है कि आम आदमी के लिए आप 60 रुपए प्रतिदिन कह रहे हैं, यानी उस तक केवल तीन रुपए ही पहुंचेंगे। वित्त मंत्री जी ने रूरल गारंटी स्कीम में कैसा भ्रमित किया है,... * पिछले साल के बजट में यह स्कीम 100 जिलों में लागू थी और कहा गया था कि इस साल से 200 जिलों में इसे लागू करेंगे। अभी आपने घोषणा कर दी कि 596 जिलों में आपने इस स्कीम को लागू कर दिया है। पिछले साल बजट में क्या प्रोविजन था, यह वित्त मंत्री जी जानते हैं, 12000 करोड़ रुपए पिछले साल 100 जिलों के लिए रखे थे। पिछले

साल के बजट में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इस योजना के अलावा थी। 12000 करोड़

* Not recorded.

रुपया नेशनल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम के लिए था और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 3420 करोड़ रुपया पिछले साल रखा था। पिछले साल कुल 15420 करोड़ रुपए रखे गए थे और अब 3420 करोड़ रुपए को जीरो कर दिया है, उसे अमलगमेट कर दिया है और इस साल कुल 16000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए रखे हैं। मतलब 100 जिलों के लिए 15420 करोड़ रुपए और 596 जिलों के लिए 16000 करोड़ रुपया, यह कैसा इंसाफ है? यह कैसे हो सकता है? [R5]

सभापति महोदय : गोयल जी, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति महोदय, चिदम्बरम साहब ने एक बात कही है, जिनका ये लोग जिक्र कर रहे हैं उन्होंने कहा था कि मैं बैठा हूं, अगर और रूपये की जरूरत होगी तो मैं दूंगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यह किस तरह का बजट है, जिसमें 100 जिलों के लिए 15400 करोड़ रूपये और 596 जिलों के लिए यदि आप 300 कह रहे हैं तो 300 ही सही, इस तरह से 600 जिलों के लिए 16000 करोड़ रूपये ही हुए। यह कहां का तरीका है...(व्यवधान) इससे ज्यादा भी शर्मनाक कोई तरीका हो सकता है। इन्होंने यह कहा कि और पैसा दूंगा, लेकिन वह पैसा आएगा कहां से? क्या इससे बजट घाटा और नहीं बढ़ेगा? इन्होंने 16 हजार करोड़ रूपये का हिसाब किस तरह से लगाया है? जब इसको शुरू किया गया था तो 11 हजार करोड़ रूपये रखे गए थे। इस हिसाब से 600 जिलों के लिए 66 हजार करोड़ रूपये बनते हैं। जब 12 हजार

करोड़, 15 हजार करोड़ रूपये रखे थे, उस हिसाब से एक लाख करोड़ रूपये होते हैं। 16 हजार करोड़ रूपये देकर आप कह रहे हैं कि रोजगार गारंटी योजना चलाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा आपके मंत्री और आपके लोग, राहुल साहब फर्माते हैं कि पांच पैसे भी लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा फैल्योर इसी में हुए हैं।...(व्यवधान)

महोदय, इनका कॉमन मिनीमम प्रोग्राम इम्पलीमेंट करने का भी यह आखिरी वर्ष है। इसमें इन्होंने लिखा है -

"The UPA Government will immediately enact a National Employment Guarantee Act. This will provide a legal guarantee for at least 100 days of employment to begin with on asset creating public works programme every year at minimum wages for at least one able-bodied person in every rural, urban poor and middle-class households."

* Not recorded

लेकिन क्या इन्होंने एक भी अर्बन पुअर के लिए गारण्टी स्कीम बनाई है? चार साल बीत गए हैं, इन्होंने वायदा किया था कि कस्बों और शहरों में रहने वाले, स्लम बस्तियों, गन्दी बस्तियों और झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए स्कीम बनाएंगे। 40 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं और अधिकांश गरीब भी शहरों में रहते हैं, जो शहरों में आकर मजदूरी भी करते हैं- उनके लिए आपने वायदा किया था कि नेशनल एम्पालायमेंट गारण्टी स्कीम लाएंगे, उनके बारे में आपने क्या किया? आपने अपने वायदे को भी तोड़ा है, यह मैं कहना चाहता हूं।

महोदय, डॉलर की कीमत कम होने से हमारे लाखों एक्सपोर्टर बेकार हो रहे हैं। यह वायदा किया गया था कि ये मिलें बंद न हो जाएं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद न हो जाए, एक्सपोर्ट करने वालों को हम राहत दे रहे हैं और बड़ी भारी राहत आ रही है, लेकिन एक पैसे की भी राहत उन लोगों को नहीं दी गई है, चाहे आप चिदम्बरम साहब का पूरा बजट पढ़ लीजिए। प्रतिदिन एक्सपोर्टर्स की कोई न कोई मिल बंद हो रही है, छोटी-छोटी हजारों इकाइयां बंद हो रही हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा गया है। इसी तरह से सरकार ने नई भर्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है, जिससे स्कूलों और कॉलेजों से निकलने वाले हजारों इंजीनियर बेकार हो रहे हैं। उनके लिए कोई राहत इसमें दिखाई नहीं देती है।

महोदय, इसके बाद वित्त मंत्री जी ने शिक्षा की मद में 28 हजार 674 करोड़ रूपये से बढ़ाकर, 34 हजार 400 करोड़ रूपये कर दिया है।[r6] इसमें 5-6 हजार करोड़ रुपये की इन्क्रीज़ हुई है, पर आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या कहा है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इन्होंने जिक्र किया कि जी. डी. पी. 6 परसेंट इसमें से एजुकेशन के लिए रखा जायेगा।

"The UPA Government pledges to raise public spending in education to at least 6 per cent of GDP with at least half this amount being spent on Primary and Secondary Education. "

यह इनका वायदा है, ऐसे नहीं कि कोई वैसे ही कहा हो। यह 34 हजार करोड़ रुपया जी.डी.पी. का क्या बनता है, 0.6 परसेंट, जबकि करना 6 परसेंट है। ...(व्यवधान) जी हां, स्टेट गवर्नमेंट का भी सब मिला लेंगे तो वह भी एक-डेढ़ परसेंट है, But he never said so. जो करना है, उसका 10 परसेंट आपने एजुकेशन में रखा है। यह ठीक है कि कुछ के बच्चे दून स्कूल में पढ़ सकते हैं, कुछ के बच्चे बड़े-बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़ सकते हैं, कुछ के बच्चे हजारों रुपये की फीस देने वाली जगहों पर पढ़ सकते हैं, परन्तु करोड़ों बच्चे हैं, जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, उन स्कूलों के अन्दर जहां टाट-पट्टी नहीं, टीचर्स नहीं, जहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं, पीने का पानी नहीं, उनके विकास के लिए जो वायदा किया गया था कि वहां पर सब स्कूलों को उस उन्नत जगहों पर ले जाया जायेगा। शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है कि सब का व्यवसायीकरण कर दिया है, सब को प्राइवेटाइज़ कर दिया है और उनके हाथ में छोड़ दिया है। सरकार की ओर से जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी शिक्षा का इसके अन्दर कोई यहां पर प्रबन्ध नहीं किया गया।

इसके बाद मुझे आपसे हैल्थ के बारे में जिक्र करना है। हैल्थ के बारे में भी स्थिति यह है कि हैल्थ में भी वायदा किया था कि हम दो से लेकर तीन परसेंट तक जी.डी.पी. का इसमें लगाएंगे।

"The UPA Government will raise public spending on health to at least 2 to 3 per cent of GDP over the next five years with focus on primary health care "

परन्तु इसमें इन्होंने 16,534 करोड़ रुपये रखे, जिसमें एन.ई.आर. का भी मामला शामिल है वायदे के मुताबिक आपको एक लाख करोड़ से डेढ़ लाख करोड़ रुपये खर्च करना था, परन्तु अगर देखा जाये तो आप उसका दसवां भाग भी खर्च नहीं कर रहे हैं। आपने यह वायदा किया था कि लाइफ सेविंग ड्रग्स को हम सस्ते दाम पर उपलब्ध कराएंगे, परन्तु दवाइयां कितनी महंगी हैं, कितने लोग अस्पतालों के बाहर जाकर दम तोड़ते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास जाना कितना महंगा हो गया है निन्दनीय और सबसे ज्यादा आप देखें कि यहां पर â€¦Establishment of AIIMS-type of super-speciality hospitals-cum-teaching institutes. जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो 6 सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल्स बनाने का तय किया था। उनके यहां पर शिलान्यास हो गये थे, रुपया रखा गया था, परन्तु, चिदम्बरम साहब, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल आपने इस मद में, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल्स बनाने और अपग्रेडिंग के लिए 150 करोड़ रुपया रखा था, इस साल उसे काटकर 50 करोड़ कर दिया। 50 करोड़ रुपये में एक भी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल बन सकता है? Is it not shameful कि आप सारे हिन्दुस्तान में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल्स एम्स टाइप बनाना चाहें और वहां पर कहना चाहें कि हम बाकी हॉस्पीटल्स को अपग्रेड कर देंगे और रुपया 150 करोड़ से काटकर केवल 50 करोड़ उसको कर दें तो इसका मतलब है कि उसमें से एक भी पांच साल बीत जाने के बाद नहीं बनेगा।

एक बात और देखिये, मुझे आश्चर्य है, हैल्थ मिनिस्टर साहब नहीं हैं। हैल्थ मिनिस्टर साहब दिल्ली के एम्स के बारे में, जो हिन्दुस्तान का सबसे सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल है, क्योंकि उनकी लड़ाई वहां पर डायरैक्टर से हो गई और उनका चार साल का, पांच साल का एजेण्डा यही रहा कि उनको कैसे निकाला जाये और उसका विकास करना था, उसका रुपया 490 करोड़ रुपये से काटकर 452 करोड़ इस साल कर दिया। पहले से और कम कर दिया, बजाय इसके कि उसमें 2-3 हजार करोड़ रुपया लगाकर एक इण्टरनेशनल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल बनाया जाया, उसका रुपया उसमें से काटकर कम कर दिया।[R7]

14.00 hrs.[N8]

वहां के पांच सौ डाक्टरों ने मिलकर प्रधान मंत्री जी से अपील की है। उन्होने कहा है कि मंत्री जी और उनका जो झगड़ा चल रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस अस्पताल को ही बर्बाद कर दें और उसका जो खर्चा है, उसे भी पहले से कम कर दिया जाए।

हैल्थ के बाद में डिफैंस के बारे में कहना चाहता हूं। आपने कहा है कि हमने डिफैंस पर 96 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख पांच करोड़ रुपये की राशि रखी है। यह राशि बहुत ही अपर्याप्त है। आप देखेंगे कि डिफैंस पर हमारा खर्च जीडीपी का 1.98 प्रतिशत आता है, चिदम्बरम साहब नें अपना जो हिसाब लगाया है। चीन अपने जीडीपी का 4.5 प्रतिशत खर्च कर रहा है, पाकिस्तान भी 4.5 प्रतिशत खर्च कर रहा है, लेकिन हम 1.98 प्रतिशत कर रहे हैं और वह भी 96 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये, नौ हजार करोड़ रुपये बढ़ा रहे हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स - इन तीनों अंगों ने जो मांग कर रखी है, आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारा सामरिक अनुपात पाकिस्तान से भी और चीन से भी बिगड़ रहा है। सरकार में जो बात हो रही है कि कश्मीर से सेना हटा लें, कश्मीर में सेना कम कर दें, यह बहुत ही खतरनाक बात होगी, यह देश के लिए बहुत ही विध्वंसकारी बात होगी। हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि कश्मीर में सेना कम करके, कश्मीर में पाकिस्तान को कुछ भी करने की इजाजत देना देश के साथ विश्वासघात होगा। डिफैंस पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, डिफैंस पर दिया गया खर्च बहुत ही कम है। मैं इस बात में नहीं जाता कि सेना में तीनों अंगों ने क्या-क्या मांग कर रखी है, उन्हें क्या-क्या चीजें चाहिए, क्या हथियार चाहिए, विज़-ए-विज़ पाकिस्तान और चीन, हमारी जरूरत क्या है, उसे देखा जाए तो हमारे डिफैंस एक्सपर्ट्स इस बात को आपसे कह सकते हैं।

यहां किसानों की कर्ज माफी की योजना को बहुत जोर से कहा गया और बहुत जोर से उसे रखा गया। एक्सपर्ट्स ने लिखा है - Almost 75 per cent of small and marginal farmers may not benefit from loan waiver. उन्होंने सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद कहा है कि 75 प्रतिशत स्माल और मार्जिनल किसानों को लोन वेवर से को फायदा नहीं होगा। श्री विलास मुतेमवार, जो मंत्री हैं, उन्होंने प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, शायद वे चिदम्बरम साहब से भी मिले हैं, कि विदर्भ में इसका किसानों को फायदा नहीं होगा। विदर्भ में लोगों के पास दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। जहां असिंचित भूमि है, वहां इकोनॉमिक होल्डिंग भी 16 एकड़ की होती है। उन्हें भी इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है फिर भी इस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लगातार इस बात को कहा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि साठ हजार करोड़ रुपये की फिगर कहां से आई है? जब आप करने लगेंगे तो देखेंगे कि 23-24 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि नहीं आएगी। आप कह रहे हैं कि हम चार करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाएंगे, जब यह बात सामने आ जाएगी। चिदम्बरम साहब ने कहा है कि मैं हाउस में बताऊंगा। अजीब बात है। पहले वेवर कर दिया। स्कीम के बारे में वे कहते हैं कि मेरे दिमाग में घूम रही है, कई ऑप्शन्स हैं, यानी ऑप्शन्स कई हैं, लेकिन उन पर यहां पहले विचार नहीं किया गया और एक प्रकार से धोखे में रखा गया। किसानों की वेवर स्कीम के बारे में डिटेल में बहुत से आर्टीकल छपे हैं। असिंचित भूमि की बात, महाजनों से लिए गए कर्ज की बात, इसके साथ ही इसमें से जो अन्य राशि आनी है, आपने कहा कि उसमें तीन-चार साल लगेंगे। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम तीन-चार साल में राशि बैंकों को दे देंगे। आपकी सरकार की उम्र एक साल बची है। जब उम्र एक साल बची हो और कह रहे हैं कि हम तीन-चार साल के बाद इसे चुकता कर देंगे, तीन-चाल साल में चुकता कहां से करेंगे? कौन सा हिसाब है? आप इसे आगे आने वाली पीढ़ियों पर डाल रहे हैं।...(व्यवधान) पहले भी इसी तरह बॉंड्स के बारे में किया गया है।...(व्यवधान) क्रेडिट आपको कैसे जाएगा?...(व्यवधान) हम तो इसे करेंगे और हमें खुशी होगी। यह किया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी बात लिखी नहीं जा रही है। आप सुनिए और बाद में जवाब दीजिए।

...(व्यवधान) [N9] *

सभापति महोदय : हल्ला-गुल्ला लिखा नहीं जाएगा।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : गोयल साहब, आप बैठिये। आप अपना आसन ग्रहण कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : राजा साहब, किसान की बात छोड़िये, अभी आप बैठिये।

â€¦(व्यवधान)

* Not recorded

14.06 hrs.

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, समय के अभाव के कारण मैं सारी बातों का यहां विस्तार से जिक्र नहीं कर सकता।...(व्यवधान) परन्तु किसान के कर्ज माफी की योजना को लोग देश भर में बेनकाब करेंगे। मंत्री जी ने बजट में जितना दिया है, उससे 15-20 परसेंट लोगों को ही फायदा होगा। बाकी के 80-85 परसेंट लोगों को इसका फायदा नहीं होगा। वे 85 परसेंट लोग आपको इस बारे में बेनकाब करेंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने आपसे कुछ पूछा है?

â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातों का और जिक्र करना चाहता हूं। समय के अभाव के कारण बहुत सी बातें मुझे कहनी हैं, लेकिन उन सबको विस्तार से कहना यहां संभव नहीं है। मैं खेलों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। अभी हॉकी में हमारा डिबेकल हुआ। पिछले 80 वर्षों में हम हॉकी में पहली बार ओलम्पिक में नहीं जा रहे हैं। परन्तु आप सब लोगों को मालूम है, अभी मणि शंकर अय्यर जी हाउस में नहीं हैं, उन्होंने इस खेल को प्रॉपरिटी केटेगरी से निकालकर नॉन प्रॉपरिटी केटेगरी में डाल दिया गया था। ...(व्यवधान) इसे 'ए' क्लास से निकालकर 'बी' क्लास में डाल दिया गया जबकि यह हमारी नेशनल गेम है। इस राष्ट्रीय खेल को हम बी केटेगिरी में डालें, जिसका मतलब है कि वे साल में एक बार बाहर जा सकते हैं, दो बार नहीं जा सकते। इतना इक्विपमैंट ला सकते हैं और इतना नहीं ला सकते। जब इस बारे में बहुत शोर मचा और हमने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों में भी हॉकी है, ये कॉमनवेल्थ खेल इंडिया में होने हैं और उसमें हम आटोमेटिकली होंगे। यदि इसे बी केटेगिरी में डाला गया, तो कॉमनवेल्थ खेलों में क्या होगा, तब जाकर इसमें थोड़ा सुधार हुआ। परन्तु खेलों के बारे में, चिदम्बरम साहब, आपने देखा होगा, एक खबर आयी थी कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी तीन करोड़ रुपये में खरीदा गया ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Madhusudan Mistry, he is supporting sports. Please take your seat.

...(*Interruptions*)

* Not recorded

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री साहब, वे स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप चुप हो जाइये।

â€¦(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्रिकेट के एक-एक खिलाड़ी को 10 करोड़, 15 करोड़ 20 करोड़ रुपये के साथ-साथ बहुत सारी चीजें मिलती हैं जबकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। परन्तु सारे खेलों के लिए 54-55 फेडरेशनें, कॉमनवेल्थ खेलें, एशियन खेलें, ओलम्पिक खेलें, इंटरनैशनल चैम्पियनशिप, एशिया चैम्पिनयनशिप आदि सारे अवार्ड्स के लिए चिदम्बरम साहब ने बजट में तीन करोड़ रुपये रखे हैं। ...(व्यवधान) टोटल अवार्ड्स के लिए कुल तीन करोड़ रुपये रखे हैं जबकि क्रिकेट में हमने 70 करोड़ रुपये विदेशी खिलाड़ियों को दे दिये हैं जो कि बाहर के खिलाड़ी हैं। अपने खिलाड़ियों को जो मिला, वह अलग है। मैं यह बात नहीं कर रहा कि उनको क्या मिला, परन्तु सरकार को कम से कम अपने खिलाड़ियों को, जो बाकी खेलें हैं, नेशनल खेल हैं, ओलम्पिक खेल हैं, उनके लिए रुपया रखना चाहिए। मैं इस हॉकी की बहुत ही शर्मनाक हार के लिए मिनिस्टर साहब को जिम्मेदार ठहराता हूं और उनके इस्तीफे की मांग करता हूं। ...(व्यवधान) मणिशंकर अय्यर साहब ने इस पूकार से खेलों के साथ व्यवहार किया है। ...(व्यवधान) वे पहले ऐसे मिनिस्टर हैं, जो एंटी स्पोर्ट्स हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं दो बातों का और जिक्र करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।[MSOffice10]

चिदम्बरम साहब ने अपनी हाइलाइट्स, अपने भाषण और उसके साथ जो पेपर्स दिए हैं, उनमें 118 हाइलाइट्स दी गयी थीं। उन हाइलाइट्स में एक शब्द या एक भी हाइलाइट आतंकवाद के बारे में नहीं थी।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, आपकी भी बोलने की बारी आएगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य देते हुए कहा कि पंजाब में आतंकवाद के फिर से फैलने का खतरा है, इसकी मेरे पास पक्की खबर है, इसलिए जो संगठन ब्लैकलिस्टेड हैं, उन पर देखकर विचार करना होगा। उन्होंने स्थिति को बहुत खतरनाक बताया। एक सवाल के जवाब में होम मिनिस्टर साहब ने बताया कि दिल्ली एवं देश के अन्य हिस्सों में धार्मिक स्थानों पर आतंकी हमले होने वाले हैं, वे उनकी नजर में हैं, वे आतंकवाद के निशाने पर हैं। एक पत्र होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली सरकार को लिखा है...(व्यवधान) बजट में इन सभी चीजों के लिए भी प्रावधान होने चाहिए थे। इन्होंने लिखा है कि BSE and CBI Headquarters are on terrorists hit list – The Home Ministry has warned Police in Delhi and Mumbai for suspected terror attacks on important occasions in the cities. आईआईटी और ऐसी ही जगहों पर अटैक होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आतंकवाद का इतना खतरा है, पूरा देश खतरे में है, जहां पर हमारे 150 से ज्यादा जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जब चार करोड़ बांग्लादेशी देश में आ गए हैं तो बजट में इसके लिए जिक्र होना चाहिए था या नहीं? बजट में इसके लिए प्रावधान होना चाहिए था या नहीं? जब हम कहते हैं कि हम आतंकवाद को टालरेट नहीं करेंगे, बजट के अंदर आपने ऐसी कौन सी धनराशि रखी है। एक भी हाइलाइट दी होती, अगर आपने कहा होता कि हम होम मिनिस्ट्री का बजट इतना बढ़ा रहे हैं, बांग्लादेश या पाकिस्तान की सीमा पर बाड़ लगाना है, बांग्लादेशियों को निकालना है, नक्सलवाद का मुकाबला करना है, तो अच्छा होता। लेकिन इसके बारे में एक भी हाइलाइट नहीं है। आतंकवाद को आपने इस तरह से लिया है जैसे कि बजट में उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप उसके मुकाबले के लिए कुछ धनराशि रखते और कहते कि हम आतंकवाद को किसी कीमत पर टॉलरेट नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आपने वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाला है और उसके लिए आपने कोई धनराशि नहीं रखी है।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट का कम्युनलाइजेशन किया गया है, उसे मजहब के आधार पर बांट दिया गया है, यह एक बहुत घिनौनी बात है। देश में पाकिस्तान बनने से पहले जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम विद्यार्थी किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेता है, जहां पर कंप्टीशन होता है, तो दाखिले की पूरी फीस सरकार देगी, किन्तु किसी गरीब हिन्दू विद्यार्थी, किसी दलित या एससीएसटी को यह सुविधा नहीं मिलेगी, यह कौन सा तरीका है? ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except the submission by Shri Malhotra.

*(Interruptions) â€¦**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मुझे समझ में आता है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Aaron Rashid, please go back to your seat first. Mr. Goyal, you should also go to your seat. Please continue, Mr. Malhotra.[r11]

* Not recorded

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि यह बात मेरी समझ में आती, अगर आप कहते की हिन्दू हो या मुसलमान हो, कोई भी गरीब या दलित हो, हम सभी को गरीबी के आधार पर फीस देंगे। परंतु इस तरह माइनोरिटी के नाम पर, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में मुसलमानों के नाम पर ऐसा भेदभाव करना ठीक नहीं है। अगर कोई बच्चा राम कुमार है तो उसे सरकार की तरफ से फीस नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर उसका नाम करीम हो जाए तो सरकार उसकी फीस देगी- यह कैसा कानून है और कैसा तरीका है! यह तो एक पूकार से अन्य गरीब और दलित बच्चों के साथ सरासर अन्याय है। Is it not encouraging conversion? अगर आप उसमें धर्म परिवर्तन करलें तो फीस आपको दी जाएगी वरना नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा बजट में और भी कई बातों का उल्लेख है। आपने उनके लिए 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी के भी दो वक्तव्य आए हैं। उन्होंने भी इसे डिफेंस किया है और कहा है कि हमने जो किया है, ठीक किया है और हम वही करेंगे। हम कब कह रहे हैं कि ऐसा न करो, लेकिन आपको ऐसा काम करना चाहिए जिससे सभी के साथ न्याय हो सके। आप किसी को एपीज़ न करें, सभी को बराबरी का दर्जा दें और एक सा सलूक करें। प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा है कि मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में 45 वर्ष एक ही परिवार का राज रहा है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Silence please.

...(*Interruptions*)

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Sir, you should expunge this word....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing should be recorded.

*(Interruptions) â€¦ **

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : परिवार का नहीं, एक पार्टी का राज रहा है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का जब समय आएगा,तब आप अपनी बात कहना। अभी आप बैठ जाएं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप इस बात को मानते हैं कि नेहरू जी 17 वर्ष तक इस देश के प्रधान मंत्री रहे, इंदिरा जी 18 वर्ष तक प्रधान मंत्री रहीं और राजीव गांधी जी पांच वर्ष तक प्रधान मंत्री रहे, फिर इसमें असंसदीय बात क्या है? आप इसे मानें या न मानें।...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Manvendra Singh ji, please sit down.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: I will allow you when your turn will come.

...(*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यह बात कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी का राज अब भी है, भले ही सोनिया जी प्रधान मंत्री नहीं हैं...(व्यवधान)

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Sir, this word should be expunged....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is nothing unparliamentary; please sit down. When there will be any unparliamentary word, I will expunge it. I know what is unparliamentary.

...(*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यह बता रहा था कि अगर मुसलमानों की स्थिति इस देश में ठीक नहीं है आजादी से लेकर आज तक करीब 61 सालों में, बीच के छः सात छोड़ कर, तीन चौथाई तो आपका ही राज रहा है और अब आपको लग रहा है कि इनकी दशा खराब है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing should be recorded except Shri Malhotra's speech.

*(Interruptions) â€¦ **

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि justice for all and appeasement for none. यह हमारा सिद्धांत होना चाहिए और हर नागरिक को हक मिलना चाहिए। इसमें मुसलमानों को भी मिलना चाहिए, हिन्दुओं को भी मिलना चाहिए।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Adhir Chowdhury, please sit down. First go to your seat.

...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी लीनिएंसी का गलत फायदा उठा रहे हैं।

* Not recorded.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इसलिए इस देश में ऐसे हालात न हो जाएं कि बहुसंख्यक वर्ग को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाए। मुझे प्रधान मंत्री जी के बयान पर आपत्ति थी। उन्होंने जो बजट के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के सरकारी साधनों और सरकारी बजट पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा घिनौना वक्तव्य और कोई नहीं हो सकता। ...(व्यवधान) इससे ज्यादा शर्मनाक वक्तव्य और कोई नहीं हो सकता।...(व्यवधान)[R12]

MR. DEPUTY SPEAKER: Prof. Vijay Kumar Malhotra, please conclude now.

...(*Interruptions*)

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : आप बजट की बात करें।...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मुसलमान भी तो भारत के नागरिक हैं, उनको न्याय मिल रहा है तो आपको क्या आपत्ति है?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रामकृपाल जी, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Prof. Vijay Kumar Malhotra.

*(Interruptions) â€¦ **

MR. DEPUTY SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions) â€¦ **

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने पहले ही आपसे कहा कि उनको न्याय पूरा मिलना चाहिए, उन्हें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। किंतु पहला अधिकार उनका है, यह बात तो शायद ...** यह तो जजिया को दूसरे तरीके से लाने की बात है। यहां पर हिंदू होना कोई अपराध तो नहीं है, हिंदू होना कोई सैकिंड-रेट सिटीजन होना तो नहीं है।...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : उपाध्यक्ष जी, जो इनकी मर्जी में आयेगा, क्या ये वही बोलते जाएंगे, ...(व्यवधान) इन्होंने अनपार्लियामेंटरी शब्द यूज किया है, इस रिकार्ड से हटाया जाए।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : इस शब्द को रिकार्ड से हटाया जाए।...(व्यवधान)

* Not recorded.

** Not recorded as ordered by the Chair.

SHRI J.M. AARON RASHID : Sir, this word should be expunged. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: Please sit down. I will look into it. If there is anything objectionable or unparliamentary, I will expunge it. Shri Madhusudan Mistry, I will look into it. Please sit down.

...(*Interruptions*)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : What is unparliamentary? ...(*Interruptions*) यह शब्द क्या अनपार्लियामेंट्री है। ...(व्यवधान) यह शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : इन्होंने तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री की बात की है, इसमें क्या अनपार्लियामेंट्री है। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: Please take your seats. Do not disturb the House.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: I will look into it later on. If there is anything objectionable, I will expunge it.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER : Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : बजट का सप्रदायीकरण नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान) पीछे से लाकर यह जजिया दुबारा लागू नहीं करना चाहिए और यहां पर जो तरीका अपनाया जा रहा है...(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : Prof. Vijay Kumar Malhotra, please conclude now.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER : This is not unparliamentary.

...(*Interruptions*)

---

* Not recorded

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जितना पैसा बजट में है और जो इन्कम-टैक्स में रिलीफ दी गयी है और जितने लोगों को रिलीफ मिली है लेकिन यह सेंसेक्स जो 21000 से नीचे 15000 टच करता हुआ 16000 हजार पर गया, उसमें से जितना रुपया निकला, अरबों-खरबों रुपया उनका हाथ से निकल गया और हम बार-बार यह चेतावनी दे रहे थे कि यह जो सेंसेक्स में बाहर का पैसा लग रहा है, आतंकवादियों का पैसा लग रहा है, इसको ध्यान से देखिये और इसे रोकिये। यह जब गिरेगा तो करोड़ों स्मॉल-इंवेस्टर्स बर्बाद हो जाएंगे, वे करोड़ों लोग इसमें बर्बाद हुए हैं। इसी तरीके से इसमें इन्होंने दो-तीन चीजें और उठाई हैं, जिनके कारण भी बहुत नुकसान लोगों को हुआ है। इसलिए ये लोक-लुभावनी जो दो-तीन चीजें इनके द्वारा की गयी हैं, जब वे बेनकाब होंगी, तब पता चलेगा कि यह बजट किस पुकार से हमारे देश के लोगों के सामने आयेगा। यह बजट महंगाई बढ़ाएगा, ग्रोथ रोकेगा, विकास को रोकेगा और देश को मजहब के आधार पर बांटेगा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

*** 11 मार्च 2008 के जनसत्ता अखबार में छपा है**

बजट के बाद दाम बढ़े एवं उत्पाद बजट से पूर्व बजट के बाद

अरहर दाल 36 रूपए किलो 42 रूपए किलो

उड़द दाल 30 रूपए किलो 35 रूपए किलो

मसूर दाल 38 रूपए किलो 42 रूपए किलो

चना दाल 28 रूपए किलो 35 रूपए किलो

रिफाइंड 67 रूपए लीटर 75 रूपए लीटर

सरसों तेल 65 रूपए लीटर 72 रूपए लीटर

डालडा घी 60 रूपए किलो 68 रूपए किलो

मैदा 13 रूपए किलो 15 रूपए किलो

और 4 मार्च 2008 के राष्ट्रीय सहारा में यह छपा है

मसाले	बजट पूर्व	अब
धनिया	58-60	71-72
काली मिर्च	160	170
हल्दी	38-40	45
लालमिर्च	50	55
बड़ी इलाईची	200	205
सौंठ	80-85	90-95
जीरा (मीडियम)	95-100	105
गोला	55	60
मखाना	170	190
सरसों	28-30	36-37
राई	32-35	40-42
कलौंजी	78-80	90
अमचूर	90	100

सरसो तेल	60-62	71-72

खुदरा बाजार में खाद्यानों की कीमतों में प्रति किलो एक रूपए और अधिकतम 20 रूपये की बढ़ोतरी हुई है।

* This part of the Speech was laid on the Table.

	May, 2004	Feb, 2008
WHEAT	8 Rs Kilo	13 Rs Kilo
FLOUR	10 Rs Kilo	18-20 Rs Kilo
RICE	10 Rs Kilo	30 Rs Kilo
BREAD	8 Rs	12 Rs
SUGAR	14 Rs Kilo	22-25 Rs Kilo
DAL MUNG	24 Rs Kilo	52 Rs Kilo
DAL ARHAR	26 Rs Kilo	44 Rs Kilo
DAL MASOOR	22 Rs Kilo	44 Rs Kilo
DAL CHANNA	25 Rs Kilo	45 Rs Kilo
RAJMA	28 Rs Kilo	55 Rs Kilo
BESAN	20 Rs Kilo	48 Rs Kilo
MILK	14	24
LPG	244	295
PETROL	33.15	45.52
DIESAL	22.50	31.73
CEMENT	125	245
STEEL	23000 Ton	35000 Ton
MUSTURD OIL	33-35	85
REFINED OIL	45	100
BANANA	10 a Dozen	25 a Dozen

[r13]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं कि मुझ से पूर्व माननीय सदस्य ने बहुत गुस्से में भाषण दिया है। इनके पास कोई खास मुद्दे नहीं थे, इसलिए बहुत मजे से भाषण किया और इधर-उधर की बातें कहीं। इनको इस बात का दुख है कि बजट में ग्रोथ रेट बढ़ रहा है और आज लगभग 7 प्रतिशत की दर से ग्रोथ रेट है।

महोदय, मैं सबसे पहले यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री जी के साथ-साथ यूपीए सरकार की कैबिनेट का अभिनन्दन करूंगा, जिन्होंने समाज का, खासतौर पर किसानों का ऋण माफ किया और लोगों का, देश का बजट प्रस्तुत किया। यह कोई चुनावी बजट नहीं है, लेकिन आपने जो भाषण दिया है, वह चुनावी भाषण है।

मैं कहना चाहूंगा कि the hon. Union Finance Minister, Shri P. Chidambaram presented his fifth Budget in a row in the backdrop of robust economic growth. The first year of the 11th Plan registered the growth rate of 8.7 per cent -- आपने भी माना है कि आंकड़े गलत नहीं हो सकते हैं -- while during the first half of 2007-08, it achieved the growth rate of 9.1 per cent. The average growth rate during 2004-05 and 2006-07 was 8.8 per cent. The drivers of growth continue to be 'services' and 'manufacturing', which are estimated to growth at 10.7 per cent and 9.4 per cent respectively during 2007-08. The 11th Plan targeted growth rate of nine per cent. The agriculture sector remained a cause of concern. The slow rate of growth of agriculture sector and the problem of indebtedness of farmers are issues requiring our focus, which the Government has already focused on.

Besides these, the rising inflationary trend due to increase in prices of food items, burgeoning subsidies, mainly food and oil, increase in the international prices of crude oil and food grains, and slow down of the economies of the world, are some of the important issues causing trouble for the domestic policy makers.

The Budget has taken note of all these factors and issues, and the hon. Finance Minister has made an earnest effort to successfully charter the economy to an accelerated growth path.

The emphasis of the Union Budget 2008-09 is the growth with distribution, making the growth more inclusive. This is proposed to be done by laying greater stress on various schemes targeted for the empowerment of the weaker sections -- हमारे साथी ने जिक्र किया -- of the society, viz., National Rural Employment Guarantee Programme, Bharat Nirman, Sarva Shiksha Abhiyan, Mid-Day Meal Schemes, National Rural Health Mission, ICDS, etc.

To improve the position of the farming community, the Budget has introduced a scheme of debt waiver and debt relief for farmers. Agriculture has been given a place of prominence in the Budget.

The Finance Minister has proposed to introduce a Central Plan Scheme Monitoring System, first of its kind, to be implemented as a Plan Schemes of the Planning Commission. The objective is to ascertain that physical targets of various schemes are achieved. This will help in close monitoring of implementation and enforcing accountability.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you going to reproduce the Budget Speech?

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : No, Sir. This is my opinion; this is my own version.

The hon. Finance Minister has provided Rs. 3,966 crore for schemes benefiting Scheduled Castes and the Scheduled Tribes exclusively; and Rs 18,983 crore for schemes where, at least, 20 per cent of the benefits are earmarked for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The allocation to the Ministry of Minority Affairs has been increased from Rs. 500 crore in 2007-08 to Rs. 1,000 crore during 2008-09.

Sir, the Budget provides Rs. 11,460 crore for women specific schemes; and Rs. 16,202 crore for schemes where, at least, 30 per cent is for women specific programmes. These are the specific beauties of these schemes. I must add that these are the programmes, which are of great benefit to the people. The Finance Minister has increased the allocation of the Ministry of Women and Child Development by 24 per cent over the allocation made in 2007-08.

During the 10th Five Year Plan, the buoyancy of tax revenue, with an average annual growth of 21.4 per cent coincided with an accelerated GDP growth. Considering such a performance, 2008-09(Budget Estimates) projected an increase of 25.6 per cent in tax revenue over 2007-08(Budget Estimates). The non-tax revenue during the same period is budgeted to increase by 16 per cent Capital Receipts, comprising of non-debt capital receipts, borrowings and other liabilities, were projected to decrease by 23.8 per cent in 2008-09 over 2007-08(Budget Estimates).[r14]

The proportion of direct taxes to gross tax collections of the Central Government has increased from 30.2 per cent in 1995-96 to 45.1 per cent in 2006-07. This Budget is providing appropriate incentives to enable self-financing of old age security through the mechanism of reverse mortgage of residential house and health insurance.

The basic exemption limit for all assessee has been increased from Rs. 1,10,000 to Rs. 1,50,000, thus giving every assessee a relief of a minimum of Rs. 4,000 in tax. In the case of a woman assessee, the exemption limit has been raised from Rs. 1,45,000 to Rs. 1,80,000 and in the case of senior citizens, from Rs. 1,95,000 to Rs. 2,25,000. I think, this is a very positive step as far as the country is concerned. अच्छी बाते छुपती नहीं हैं। उनके पास बजट में टिप्पणी करने के लिए कुछ खास बातें नहीं हैं। एक गिलास में आधा पानी भरा है, किसी से पूछो तो वह कहेगा आधा खाली है और कोई कहेगा आधा भरा है। कहने का मतलब यह है कि देखने का अपना-अपना नजरिया है। ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded. Do not disturb.

...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदयः अगर आप इन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो मैं इनको कैसे रोकूंगा।

...(*Interruptions*)

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : The tax proposals on the indirect tax side are estimated to result in a loss of Rs. 5,900 crore. Performance of revenues from excise duty, which had been quite disappointing with growth of such revenue declining steadily from 13.4 per cent in 2002-03 to 10.3 per cent and 9.2 per cent in two subsequent years, revived somewhat to 12.8 per cent in 2005-06. The average growth in excise duty collection remained 10.7 per cent during 2002-07.

Now I come to Plan expenditure and Non-Plan expenditure. I do not want to go into details. The Plan expenditure for 2008-09 has been placed at Rs. 2,43,386 crore. As a proportion to total expenditure, it will be 32.4 per cent. The revenue expenditure is estimated to be Rs. 2,09,767 crore whereas the capital expenditure will be Rs. 33,619 crore. I do not want to go into the details of Plan expenditure.

I will come to the Non-Plan expenditure because this is a major area where deficit and other things figure and on which our learned friend has criticized sharply, which is not a truth. The Budget for 2008-09 has placed the Non-Plan expenditure at Rs. 5,07,498 crore. Interest payments of Rs. 1,90,807 crore, Defence expenditure of Rs. 1,05,600 crore and subsidies of Rs. 71,431 crore constitute major items of Non-Plan expenditure. These three items constitute 72 per cent of total Non-Plan expenditure. The total interest payment constitutes 31.6 per cent of the total revenue receipts. I do not want to go into the details of all these

things.

Now I want to deal with fiscal deficit. Fiscal position of the country has improved tremendously. Revenue deficit for 2007-08 will be 1.4 per cent against a BE of 1.5 per cent and the fiscal deficit will be 3.1 per cent against a BE of 3.3 per cent.

The revenue receipts of the Central Government for 2008-09 are projected at Rs. 6,02,935 crore and the revenue expenditure at Rs. 6,58,119 crore. Consequently, the revenue deficit is estimated at Rs. 1,33,287 crore which is 2.5 per cent of GDP. Trends in revenue *vis-Ã -vis* fiscal deficits are as follows. For the year 2006-07, the revenue deficit was 1.9 per cent at Rs. 80,222 crore. As per the BE of 2007-08, it was pegged at Rs. 71,478 crore, that is, 1.5 per cent. As per RE of 2007-08, it is 1.4 per cent at Rs. 63,488 crore. As per the BE for 2008-09, it is one per cent.[SS15]

So, the fiscal deficit is the same; it has come down from 3.5 per cent to 2.5 per cent, which is a very manageable thing. Everyone knows that there is a conscious shift in expenditure in favour of health, education, and social sector. There is one more year to eliminate the revenue deficit as stipulated in FRBM. However, the Finance Minister intends to revisit the roadmap of fiscal adjustment in view of the significant liabilities of the Government on account of the oil, food, fertilizer subsidies and the likely burden of Sixth Central Pay Commission. He would like to get the job of redrawing the roadmap of the fiscal adjustment done by the Thirteenth Finance Commission, which may suggest suitable measures.

Now, I want to come to some other issues, namely, agriculture. यहां काफी जिक्र हुआ कि 4 करोड़ किसानों को राहत मिलने वाली है, यह बात सही है लेकिन देश में 80 परसेंट छोटे किसान हैं और रू0 60,000 करोड़ किसानों को मिलने वाला है। पांच एकड़ जमीन से नीचे सबको ऋण माफी का लाभ मिलने वाला है और जो कुछ मिलने वाला है उसमें 30 परसेंट किसान भी नहीं हैं यह कहना गलत है। देश में 12 करोड़ किसान हैं जिनमें से 4 करोड़ किसानों को लाभ होने वाला है। यह बात सही है कि जो रेनफेड एरिया खास तौर से ड्रॉट, रेनफेड एरिया और डेजर्ट एरिया के किसान हैं उनकी आमदनी में फर्क होता है। किसान को डेट 25 परसेंट अगेंस्ट द ओटीएस दिया जाएगा - हम कहते हैं कि 25 और 75 परसेंट, राज्य सरकार आगे भी आ जाएं और 25 औ देंगे तो भी सभी जिम्मेदारी केंद्र की है, राज्य सरकारें क्या करेंगी? जिस तरह से एम्पलाएमेंट गारंटी स्कीम का जिक्र किया गया, लेकिन इस पर अमल कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी ने सही कहा था कि नुकसान के बाद पांच पैसे रहते है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी उस पर अमल करना है। राज्य सरकार की सही मायने में जिम्मेदारी लोगों के पैसे को देखने की है। राज्य सरकार में दलाल आते हैं और पैसे खा जाते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार मॉनिटर तो नहीं कर सकती इसलिए मैं कहूंगा कि इस तरफ थोड़ा और ध्यान दें कि जो थोड़े से किसान हैं जिनको लाभ नहीं हो रहा है उनको लाभ कैसे दें। जो रैगुलर मुआवजा रिपेमेंट करने वाले हैं, जो किसान रैगुलर रिकवरी दे रहे हैं, उन्हें ऐसा न लगे कि रिकवरी देकर गलती की है इसलिए उनको इन्सेन्टिव देना चाहिए। मैंने यह छोटा सा सुझाव पहली बार भी दिया था और अब दूसरी बार भी दे रहा हूं कि जिन्होंने पिछले दो साल से रैगुलर लोन की रिकवरी दी है, उन्हें चार परसेंट इन्टरस्ट पर क्रेडिट दिया जाए और जो पैसा जमा हो, उसे आगे जो रिकवरी होगी उसमें मान्यता दी जाए। और अगले दो साल रैगुलर पेमेंट करे तो इन्सेन्टिव देना चाहिए और उसे चार परसेंट की रिबेट भी मिले तभी यह काम सही होगा।

हम जो डेट रिलीफ का काम कर रहे हैं, इस संबंध में मेरा छोटा सा सुझाव है कि यह वन टाइम है, हमेशा आने वाली चीज नहीं है, हम इतना चाहते हैं कि राधाकृष्णन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की हैं, उसे ध्यान में रखें। इस कमेटी ने कहा है कि अगर एक साल आपत्ति आई, उसके बाद दूसरे और तीसरे साल आई तो इन्हें भी माफी की बात कहें। इसके लिए एग्रीकल्चर रिलीफ फंड की बात उन्होंने कही है। अगर 300 करोड़ का रिलीफ फंड है, जैसे नैचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो उस हिसाब से जैसे ऑटोमेटिक कॉरपोरेट सैक्टर और इन्डस्ट्रीज में कप्रोमाइज करके हो जाता है उसी तरह यहां भी हो जाए ताकि किसान जो चीजें सोच नहीं पाता और नैचुरल कैलेमिटी से जो नुकसान होता है एग्रीकल्चर रिलीफ फंड से उसे कुद मिले और उस पर बैड डेट की आपत्ति दुबारा न आए।

महोदय, प्राइस फलकचुएशन का किसान को अंदाजा नहीं होता है, इतनी प्राइस फलकचुएशन होती है, जिसे किसान सोच भी नहीं सकते। किसान उसका शिकार होता है अभी दुनिया में दाम बढ़ रहे हैं, हिन्दुस्तान में भी बढ़ रहे हैं, कभी-कभी दाम इतने नीचे जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए प्राइस फलकचुएशन के लिए रिस्क मिटिगेशन फंड बना दिए जाए जिससे किसानों को राहत मिलेगी। उनको जो नुकसान होगा, मार्किट इंटरवेंशन स्कीम कहते हैं आज भी वह स्कीम है, ...(व्यवधान) लेकिन उसमें हम ज्यादा कामयाबी नहीं पा रहे हैं...(व्यवधान) उसमें सुधार की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के मैम्बर बोल रहे हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): इसलिए हमें थोड़ी राहत देनी चाहिए और रिस्क मिटिगेशन फंड बनाना चाहिए ताकि जिसे नुकसान हो उसे वहां से लाभ पहुंचा सकें। किसानों के बारे में इतना ही कहूंगा कि जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, वह कोई काम ऐसा नहीं कर रही हैं, इसमें सिर्फ 9 परसेंट किसान दायरे में आते हैं, इसके अंतर्गत एक, दो या तीन परसेंट किसानों को लाभ हो रहा है। इसके लिए किसानों को अवगत कराना पड़ेगा। वह स्टेटिक स्कीम है, कई हजार प्लान इसमें लाने पड़ेंगे। इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। कई एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के लिए सरकार ने जो ज्वाइंट कमेटी अभ्यास करने के लिए बनाई थी उसका रिपोर्ट आ चुका है उसे लागू कर दिया जाए। इसमें जितना फलकचुएशन होगा उतना किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा किसानों के घाटे को पूरा करने की बात आती है, वन टाइम सब्सिडी, इसमें खाली प्रीमियम के समय सब्सिडी दे दें बाकी किसान खुद कर लेगा। [r16]

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में तीसरी अच्छी बात इरिगेशन के बारे में है। अभी तक इरिगेशन के क्षेत्र में पैसे की बड़ी कमी थी। इस बजट में इरिगेशन के लिए 84 परसैन्ट इनक्रीज किया गया है। इसमें ए.आई.डी.पी. में 11 हजार करोड़ रुपये से बीस हजार करोड़ रुपये इनक्रीज किया है। इसके अलावा इरिगेशन कंस्ट्रक्शन डवलपमैन्ट कारपोरेशन का भी धन 100 करोड़ रूपये आगे बढ़ेगा। अभी 14 नेशनल प्रोजैक्ट्स भारत सरकार ने देश के लिए अलग से लिये हैं। यह बात जरूरी है कि देश के अंदर जो राज्य हैं, जो देश की अपेक्षा से कम इरिगेशन करते हैं, महाराष्ट्र और नॉर्थ-ईस्ट भी उसमें हैं, इसके अलावा और कई राज्य हैं, ऐसी जगहों पर उपरोक्त कारपोरेशन मैसिव धनराशि लगायेगा और इससे इरिगेशन को बढ़ावा मिलेगा।

अभी पिछले साल 11वीं योजना में केवल आठ लाख हैक्टेअर इरिगेशन की बात करने से कुछ नहीं होगा। उपाध्यक्ष जी, आप खुद भी किसान रहे हैं, आप भी इन सारी बातों को जानते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह बड़ी बात हो गई है, चाहे बांड्स निकालें, कुछ भी करें, लेकिन इससे इरिगेशन को बढ़ावा मिलेगा और जो इरिगेशन के लिहाज से बैकवर्ड रीजन्स हैं, उन्हें फारवर्ड स्टेट के रूप में आगे आने की सुविधा मिलेगी।

चौथी बात इन्होंने अच्छी की है कि स्किल डैवलपमैन्ट कारपोरेशन के लिए, जो एक नॉन-प्रोफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी उन्होंने इस कारपोरेशन के लिए 1000 करोड़ रुपये रखे हैं और स्टेट्स को उन्होंने कहा है कि वे भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। स्किल डवलपमैन्ट में उन्होंने 15 हजार करोड़ रुपये के कॉर्पस की बात की है और एक हजार करोड़ रुपये का उन्होंने यहां से प्रोविजन किया है, क्योंकि स्किल डैवलपमैन्ट आज के वक्त की जरूरत है। हमें किसानों का खेत का बोझा भी कम करना है। इसलिए हर किसान और मजदूर का बेटा कम से कम स्किल डैवलपमैन्ट में चला जाए, चाहे वोकेशनल हो, आई.टी.आई. हो या कुछ भी हो। क्योंकि तभी गांवों की आबादी गांवों में रहेगी, वह शहरों की तरफ नहीं भागेगी। होता क्या है कि गांवों की आबादी शहरों में आती है और यहां गंदगी में रहती है। जो कोई शोभा देने वाली बात नहीं है। समाज की जरूरी चीजों को हमारे विपक्ष के नेता, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी भूल ही गये। उन्होंने सरकार का जो पन्ना एग्जामिन करना था, वह ठीक है, लेकिन समाज के लिए कौन सी बात करना जरूरी है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, क्योंकि दुनिया में सभी जगह महंगाई बढ़ रही है, हिंदुस्तान भी दुनिया का एक हिस्सा है। इंडिया आज एक ग्लोबल विलेज बन गया है। इसमें थोड़ा असर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी डैवलपमैन्ट का रोड मैप ठीक चल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो स्किल डैवलपमैन्ट का सवाल है, देश में आई.टी.आई. की संख्या पांच हजार से 11 हजार करने की बात कही गई है। स्किल डैवलपमैन्ट के बगैर इस देश का कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि देश में जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उन्हें मैनपावर नहीं मिलती है। देश में ग्रेजुएट्स रास्तों पर बेकार घूम रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। और इंडस्ट्रीज एड दे रही हैं,उन्हें लोग नहीं मिल रहे हैं, विदेशों से लोगों को लाना पड़ रहा है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया है और मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक ही कदम उठाया।

अगली बात रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैन्ट के बारे में कही गई है। इस बारे में दो राय है। आर.आई.डी.एफ. ने 14 हजार करोड़ रुपये का फंड दिया है, इसमें चार हजार करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों के रोड डवलपमैन्ट के लिए अलग रखा है। लेकिन मंत्री जी को मेरा इस बारे में सुझाव होगा कि आर.आई.डी.एफ. कहां से आता है, जो 18 परसैन्ट किसान को ऋण देना होता है, वह हम दे नहीं पाते हैं और जो पैसा बचता है, वह रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैन्ट फंड में आता है। हम यह चाहेंगे कि बैंकों की अकाउन्टेबिलिटी होनी चाहिए कि यह 18 परसैन्ट क्यों नहीं बंट रही है, दस परसैन्ट क्यों बंट रहा है। कुछ बैंकों में 12 परसैन्ट क्यों हो रहा है। बैंकों की बॉडीज में जो आर.बी.आई. के डायरेक्टर नोमिनी होते हैं, गवर्नमैन्ट के नोमिनी होते हैं, नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, उनकी एक अकाउन्टेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि बैंक को आसानी हो जाती है कि पैसा आर.आई.डी.एफ. में चला जाए, कोई अकाउन्ट खोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए बैंक की भी अकाउन्टेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी होनी जरूरी है और उन्हें 18 परसैन्ट का बंटवारा करना जरूरी है।

महोदय, एग्रीकल्चर क्रेडिट अभी दो लाख अस्सी हजार करोड़ रुपये पर गया, पिछले तीन साल में हमने दो लाख 43 हजार करोड़ रुपये का बंटवारा किया। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी कहीं न कहीं कमजोरी भी है। हमारा क्रेडिट एक तरफ बढ़ रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। अपनी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ायेंगे। जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ायेंगे, किसान को दाम नहीं देंगे, उन्हें पानी नहीं देंगे तो यह कैसे होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपने अच्छा किया कि एक हजार रुपये गेंहू की फसल का दाम तय किया है, क्योंकि जिसके पास धान है, उसकी एक हजार से कम कीमत नहीं होनी चाहिए और जितना भारत सरकार को जो प्रोक्योरमैन्ट करना है, वह ओपन मार्केट से करे। जैसे दाल है, तिलहन है, उनका हम आयात कर रहे हैं। हम पहले 20 परसैन्ट सैल्फ पर निर्भर थे, खुद बना रहे थे, अभी 70 परसैन्ट इम्पोर्ट करना पड़ रहा है - ये क्यों हो रहा है? इसलिए हम चाहेंगे कि उसके दाम भी कम से कम तीन हजार रुपये मिलना चाहिए। क्योंकि रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, इस तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें उन्होंने ठीक किया कि पांच सौ सॉइल टैस्टिंग लैब्स के विस्तार की बात की है। एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए इन्होंने काफी पैसा रखा है।

रूरल डैवलपमैन्ट के बारे में मेरा कहना है कि जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, रुरल इकोनोमी और मैकेनिज्म जब तक मजबूत नहीं होगा, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन जो रूरल डैवलपमैन्ट इम्पलायमैन्ट गारंटी स्कीम है, इसमें जो स्किल डैवलपमैन्ट के साथ इंटीग्रेटेड एप्रोच होनी चाहिए क्योंकि जो हम 80 रुपया रोज मजदूर को दे रहे हैं, उसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वह भी हमें देखना चाहिए। अगर एक-एक हजार रुपया बच्चे को दिया जाता है तो वह स्किल्ड डैवलपमेंट में कामयाब हो जाता है। गरीब बच्चे कहां जाएं? इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं कि उसने शिक्षा में बड़ी स्कीम बनायी है और इकॉनोमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए भी अच्छी योजना बनाई है। शिक्षा अभियान भी चलाया है, एक लाख के करीब बच्चों को छात्रवृति भी दी है, एससी और एसटी के बारे में उन्होंने 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं चाहता हूं कि जो पॉजीटिव चीजें हैं, समाज के उद्धार के लिए, समाज को मजबूत बनाने के लए समाज के गरीब आदमी के सम्मान के लिए, पिछड़े और आदिवासी लोगों के सम्मान के लिए, गरीब आदमी के सम्मान के लिए, जो योजना बनाई हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

एक बात मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूं। नाबार्ड की स्थापना को 25 साल हो गये। नाबार्ड को रिव्यू करना चाहिए। वहां जो गलतियां हुई हैं, उसमें सुधार करना चाहिए। हम कितने दिन नाबार्ड ऐसे ही चलाएंगे? पिछले साल भी मैंने बजट में इसका जिक्र किया था। इसलिए हम सोच रहे थे कि हम कुछ अच्छी बातें आगे करें। ऐसा कोई बजट नहीं होगा जिसकी कोई आलोचना नहीं होगी। कमी तो कोई न कोई रहेगी। लेकिन जो हमारा उत्पादन है, जो हमारे साधन हैं और जो खर्चे की कमिटमेंट है, उसके साथ ही हमें चलना है। यह कोई जादू नहीं है कि एक दिन या एक रात में पैसे ला दिये और सबको हरा भरा कर दिया। कुछ समय लगने वाला है।

कोआपरेटिव की बात कहकर मैं अपनी बात 5-7 मिनट में समाप्त करूंगा। वैद्यनाथन कमेटी ने जून 2009 तक काम पूरा करने का वादा किया है। कमेटी ने यह भी कहा है कि दो साल के अंदर शॉर्ट टर्म लोन हो या लॉंग टर्म लोन हो, उसे दो साल में खत्म करना जरूरी है क्योंकि सहकारी आंदोलन को मजबूत करना जरूरी है। उसे रीस्ट्रक्चर करना जरूरी है, उसके बारे में भी सोचना है और उसके लिए और धनराशि देनी जरूरी है। मैं यहां यह भी कहूंगा कि उन्होंने निजी बैंक्स, नेशनेलाइज्ड बैंक्स, रूरल बैंक ने अच्छा काम किया है, उनका अभिनंदन करने का काम किया, अच्छा काम किया लेकिन कोआपरेटिव बैंक का अभिनंदन नहीं किया। उनकी क्या गलती थी जिसकी वजह से ये कामयाब नहीं हुए क्योंकि आजकल कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से ही छोटे और सीमांत किसानों को लोन मिलता है और उसी की पार्लियामेंट में हम चर्चा कर सकते हैं। कोआपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए खास प्रावधान करना जरूरी है। कोआपरेटिव बैंक के ऊपर इंकम टैक्स लगाया गया है, इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे हटाना जरूरी है क्योंकि वैद्यनाथन कमेटी कितने साल चलेगी? उसका दो साल या एक साल, उसका टाइम-बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। जो राज्य सरकार इस काम को नहीं करती, मैं चाहूंगा कि उन्हें इसे करना चाहिए चाहे कोई भी राज्य सरकार हो।

अंत में, मैं कहूंगा कि जो ऋण माफी की बात हो रही है, इसके बाद हम इतना ही कहेंगे कि हमने राधाकृष्णनन कमेटी की रिपोर्ट मानी है, लेकिन उस पर अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। There is a need for introduction of a nation-wide Debt Swap Scheme – bank loans to farmers to clear high cost loans from informal sources (moneylenders). In view of difficulties in ascertaining the exact debit from the moneylenders, appropriate ceiling under the scheme may be fixed. जो महाजनों का कर्जा है, वहां हमें देना जरूरी है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभारी हूं, उन्होंने अपने

भाषण में कहा है कि The scheme will continue. मैंने उनसे मुलाकात भी की तो उन्होंने कहा कि यह योजना चलती रहेगी। इसका विस्तार करने के लिए भी हम सोच रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जब तक हम मनीलेंडर का बंदोबस्त नहीं करेंगे, जो अनऑथोराइज्ड मनीलेंडर्स हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? कुछ गांव के नेता भी मनीलेंडर्स होते हैं, उधार देने वाले दुकानदार भी मनीलेंडर्स हैं। इसलिए जो अनऑथोराइज्ड मनीलेंडर्स हैं, उनके संबंध में हमें कुछ न कुछ कानून बनाकर उनके खिलाफ कुछ न कुछ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। Most of the rural population is outside the coverage by any insurance. जो गांव वाली आबादी है, उसे हम कैसे इंश्योरेंस में कवर करें? एक अच्छी योजना उन्होंने अनऑरगेनाइज्ड सैक्टर में आम आदमी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है जिसके तहत 31000 रु. तक स्वास्थ्य के लिए राहत दी है। [r17]

It was suggested that an integrated micro insurance product for providing cover for medical requirements of the family which is Rs.10,000 may be extended up to Rs.30,000. कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। इसलिये हमें असंगठित क्षेत्र की ओर ध्यान देना पड़ेगा। अभी छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट आने वाली है। असंगठित क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की तनख्वाह में अंतर बढ़ जायेगा। जब कॉरपोरेट सैक्टर में ज्यादा पैसा मिलता है तो यह अंतर और अधिक बढ़ जायेगा। इसलिये मेरी अर्ज है, मेरा सुझाव है और मेरा आग्रह है कि हम असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिये ज्यादा सोचें। हमें उनकी सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, शैल्टर या दूसरी जो कमजोरी होती है,उन के बारे में कुछ सहायता देनी चाहिये ताकि उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा में ये सुविधायें मिलें। हमें डर इस बात का है कि जितना अंतर बढ़ रहा है या जिस ढंग से कारपोरेट सैक्टर की 2 प्रतिशत की सोसायटी बन गई है, उनके लिये पैसा खर्च करने का सवाल ही नहीं आता। वे कहां खर्च करने वाले हैं? लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे के 30 प्रतिशत लोग हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिये। योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सही कहा है कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिये कानून बनाया है जिसमें उन लोगों की सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि उनके लिये मिनिमम वेजेज क्या होनी चाहिये? स्टेट गवर्नमेंट ने मान लिया कि मिनिमम वेज क्या देनी है लेकिन उस पर अमल कौन करता है? इसलिये हम लोग इनवाल्व हैं क्योंकि हम किसान हैं और मजदूरों के लिये थोड़ा मजदूरी बढ़ा सकते हैं। मैं सभी राजनैतिक दलों से आग्रह करूंगा कि हम लोगों को यह सोचना चाहिये कि किसानों और किसान-मजदूरों को लाभ कैसे मिल सकता है और हम पैसा उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं? अगर हम नहीं सोचेंगे, एक-दूसरे को गालियां देंगे, यह पार्टी का सवाल नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा कि यह बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार का आभारी हूं कि उसने चीनी मिलों के बारे में कुछ किया है। आज से तीन साल पहले चीनी मिलों की क्या स्थिति थी? काफी चीनी मिलें बंद हो रही थीं। हजारों-लाखों किसानों का बकाया पड़ा हुआ था लेकिन अब वह बकाया किसानों को मिल रहा है। किसानों को एक्साइज ड्यूटी और बैंकों से ऋण देने की स्कीम में छूट मिल रही है। मुझे पता है कि बिहार के किसानों को वही दाम नहीं मिल रहा है। सरकार को देखना चाहिये कि जो स्कीम किसानों के लिये है, वह उन तक जा रही है या नहीं? क्या उन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं? मैंने पाया है कि को-आपरेटिव चीनी मिलों का ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सुधार हो रहा है इनफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस बजट में और 11वी योजना में को-आपरेटिव के अंदर एग्रो-प्रोसैसिंग का एक स्पेशल पैकेज हो जाये और जो उपज पैदा करने वाला है, वह उसका सदस्य हो जायेगा, वह मालिक बनेगा, दो एकड वाला किसान उद्योग का मालिक बन जायेगा और उसे संतुष्टि मिल सकेगी। को-आपरेटिव की जनरल मीटिंग में वह आन्सवरेबल हो जाता है। ऐसा इसमें पैकेज दिखाई नहीं देता लेकिन को-आपरेटिव के अंदर इन लोगों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सामाजिक सुरक्षा के पैकेज की बात कही गई है, हर मजदूर 15 से 30 रुपये प्रतिदिन लेता है लेकिन उसके बीमा को पैसा कौन देखेगा? गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिये 50 प्रतिशत केन्द्र और 50 प्रतिशत राज्य सरकार दे- ऐसी स्कीम बनाई जाये क्योंकि जो मजदूरी करने वाले हैं, उनमें गरीबी का अंतर बढ़ रहा है। जो कानून बनाया है, उसमें गरीबी अमीरी का अंतर कम होना चाहिए उसके अनुसार अरबन और रूरल में डिवीज़न आगे बढ़ रहा है। मैं जानबूझकर आंकड़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह ठीक नही होगा। आज की तारीख में तिगुना अंतर हो गया है। एक 12 हजार होगा तो दूसरा 24 हजार न होकर यह 56-58 हजार होगा। मैं चाहूंगा कि अरबन और रूरल में परफोर्मेंस इनकम का अंतर कम करना चाहिये। इसी कारण हम असंगठित क्षेत्र के लिये कुछ दे सकते हैं। मगर मैं चाहूंगा कि There should be a permanent policy in the case of import and export of agricultural products. जब ध्यान आया तो चीनी का आयात किया गया, जब ध्यान आया तो बंद कर दिया गया। इसी प्रकार प्याज का एक्सपोर्ट कर दिया गया और जब चाहा बंद कर दिया। इस तरह आयात-निर्यात करके किसानों को घाटा दे रहे हैं। जब उन्हें बैड-डैट हो जाता है तो उनके कर्जे माफ करने पड़ रहे हैं। कर्जे माफ करने से हल्ला-गुल्ला होता है तो यह गलत बात है। इससे किसानों को गलत समझा जायेगा और वह क्या करेगा? वह कानून तोड़ नहीं सकता है। वित मंत्री जी ने उनके लिये जो कुछ कहा है, उसके लिये मैं आभारी हूं। [s18]

उन्होंने मद्रास में एक भाषण दिया। मैं कितने सालों से कह रहा हूं कि किसान मजदूर इतने ईमानदार होते हैं कि वे कर्ज में डूबने को पाप मानते हैं। वे कर्ज में डूबना नहीं चाहते, इसलिए वे सूसाइड कर रहे हैं। इनसोलवेंट सर्टिफिकेट किसी से नहीं लिया, न बेटे के नाम से लिया, उनके बारे में हम कुछ नहीं सोचते हैं। इनसोलवेंट हो गया तो कर्जा डुबोना ही पड़ता है, फिर वे क्या करें? फिर बैंक वाले उनकी मदद करते हैं इसलिए किसान के बारे में यह सोचना गलत है कि उन्हें ऐसी आदत हो जाएगी, यह गलत हो रहा है। सेकिण्ड ग्रीन रिवॉलयूशन प्रधानमंत्री लाना चाहते हैं इसके कारण सभी क्रेडिट लाइन उसके लिए खुली होंगी। दस साल से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के बारे में सुन रहे हैं अभी तक उसे टेकअप नहीं किया गयाहै अभी भी किसान दलाल या मिडलमैन के हाथ में है। हर एक जिले में 165 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की मान्यता मिली है। कौन सा एक्टीवेट हो गया है, क्यों नहीं एग्रीकलचर में इकनॉमिक जोन लगाते हैं? क्यों नहीं एजुकेशन में इकनॉमिक जोन लगाते हैं? ऐसा माहौल चल रहा है कि एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर और अमीर हो रहा है, जातपात का काम खत्म कर दिया है इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। मॉडल और सैंट्रल स्कूल बनाने की बात कही है, यह अच्छी बात है, डिफेंस में मिलिट्री स्कूल को पैसा दिया है।

डिफेंस के बारे में आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा। स्पेशल इकनॉमिक जोन में निर्णय हुआ है, नीति तय हुई है, किसान के खेत पर स्पेशल इकनॉमिक जोन नहीं लगा लेकिन अब लग रहा है। बंजर जमीन है, लाखों की जमीन है, उस पर SEZ लगा है। हमें इसे कैसे एग्री कर लेते हैं। सारे हिंदुस्तान में आंदोलन हो रहा है, खेती के ऊपर एसईजेड न आए, तब भी लग रहा है। एक्वीजीशन के बारे में कहा है कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन एक्वीजीशन में एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी आ गई है। गांव में रहने वाला परिवार हिंदुस्तान का नागरिक है, उनके लिए कैसे काम करना है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यह भी हमें देखना पड़ेगा। इसके कारण रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया है। रिहैबिलिटेशन के साथ भी कई बार चर्चा की है वे कहते हैं कि मजदूर के रहने की जगह है परंतु मजदूर तो बदल जाता है, ऑनरशिप नहीं बदल जाती है, रियल एस्टेट एसईजेड न बन जाए। मैं आखिरी बात एजुकेशन के बारे में कह रहा था, इस बारे में मेरा एक सुझाव है सैंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है लेकिन यह गांव की तरफ भी बननी चाहिए। शहरों में इतना बोझ हो रहा है कि यहां न पीने का पानी और न ही रहने के लिए लोगों के पास मकान, सड़क हैं। मेरे गांव में 500 की आबादी थी वह 5000 हो गई है, वह शिक्षा संस्था है। वहां सब फैकिलिटी है, ऐसी बात नहीं है कि गांव में फैकिलिटी नहीं है, हमारी पॉलिटिकल विल और नीति होनी चाहिए जिससे कि फैकिलिटी वहां पहुंच जाए और गांव के बच्चे वहां पढ़ाई कर लें। गांव में यह वातावरण होना चाहिए कि हमें स्कूल जाना है और पढ़ाई करनी है तथा आगे जाना है। शहर में जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता और शहर में जाने से कई गलत चीजों के शिकार हो जाते हैं। वहां अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वह भगवान को प्यारा हो जाता है। वहां उसके पास कोई घर भी नहीं होता इसलिए जितने सैंट्रल इंस्टीट्यूशन्स आ रहे हैं वे सब गांव में हो जाएं और इस बारे में एक नीति तय हो जाए। गांव में जाने के लिए थोड़ा इफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र में तीन यूनिवर्सिटी को सौ करोड़ दिया है, यह अच्छा काम हुआ है, ठीक हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हमे यह पक्का करना पड़ेगा कि संस्था गांव में बने इसके

अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। मैं डिफेंस की बात कहता हूं। नेशनल केडिट कोर के लिए डिफेंस बजट नहीं होता इसलिए उनका विस्तार नहीं हो रहा है। डिफेंस का बजट सही मायने में एक परसेंट घटा है लेकिन एब्साल्यूट टर्म में 9000 रुपए बढ़े हैं। जैसे दो करोड़ सैनिक स्कूल को दिया है, मेरी आपसे और रक्षा मंत्री से दरख्वास्त है कि हर एक जिले में 11वें प्लान में कम से कम एक सैनिक स्कूल देखा जाए।

15.00 hrs.

उपा[r19]ध्यक्ष महोदय, सैनिक स्कूल के बारे में मेरी दूसरी आपत्ति है कि उनकी पहले जो स्कॉलरशिप रु. 125.00 या रु. 130.00 थी, उतनी ही आज है, जब कि 15-20 साल पहले जो ट्यूशन फीस थी वह 10 हजार रुपए हो गई, लेकिन जो स्कॉलरशिप थी वह वही 15-20 साल पुरानी ही है। इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 50-50 परसेंट देती हैं। राज्य सरकारें कोऑपरेट नहीं करती हैं, जिसके कारण कई सैनिक स्कूलों की हालत बिलकुल खराब है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि 11वीं योजना में धीरे-धीरे देश के सभी जिलों में एक-एक मिलिटरी स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया जाए। इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री भी खुद तय कर सकती है। लेकिन इनके लिए ज्यादा धनराशि की जरूरत है।

महोदय, नैशनल कैडेट कोर के बारे में विशेष ध्यान रखा जाए। मैं कहना चाहता हूं कि सभी कैडरों में फौजी अधिकारियों की काफी कमी है। यह पब्लिक को पता है। पूरी दुनिया को पता है। इसे कैसे मीट-आउट करेंगे। कितना भी अट्रैक्शन दे दो, लेकिन लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि बाहर जाएं तो 10 लाख रुपए मिलते हैं और यहां आने पर बहुत कम रुपए मिलते हैं। फिर यहां स्ट्रैस भी ज्यादा है। यहां तो हम राष्ट्र भक्ति कर के काम करेंगे, लेकिन राष्ट्र भक्ति करने वाले को मिलता क्या है? क्या मिलेगा? इसलिए सिक्स्थ पे कमीशन तो ठीक है। उसकी रिपोर्ट आनी है। उसे वित्त मंत्री जी देखेंगे कि इस बारे में क्या करना है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा जो डिफेंस का बजट है, उसमें एच.आर.डी. की तरफ और खासकर सैनिक स्कूल और नैशनल कैडेट कोर की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।

महोदय, जो चीजें मैंने विस्तार से कहीं उन पर मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री जी ध्यान देंगे और कुछ कहना चाहेंगे; मैं और कहना चाहता था, लेकिन समय नहीं है। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी ने मुझसे पहले कहा कि यह गलत है, वह गलत है। ठीक है, उन्होंने अपना काम किया है। मैं कहता हूं कि यह यू.पी.ए. सरकार का बजट है और आम लोगों का बजट है। मैं कहता हूं कि उनका भाषण ही चुनावी भाषण है। वे हमेशा हिन्दू-मुसलमान की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि देश को आजाद हुए 60 साल हो गए और माइनॉरिटी को कुछ नहीं दिया गया। 60 साल पहले जब डॉ. बाबा साहबे अम्बेडकर ने घटना लिखी, तब सोश्यली बैकवर्ड इकनॉमिक क्लास को दिया गया। अब जब 60 साल के बाद इनके ध्यान में आया, तब सच्चर कमेटी बनाई। जो वर्ग पिछड़ा है, उसे सुधारने की जरूरत है। अगर उसे कुछ दिया गया है, तो आपत्ति करने की क्या जरूरत है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इकनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को भी कुछ मिलना चाहिए, लेकिन जिसको मिल रहा है, उसे गाली देने से क्या लाभ है? हिन्दू और मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? अब शांति से सब लोग रह रहे हैं, इंटीग्रेशन का एक अच्छा माहौल बन रहा है। ये हिन्दू-मुसलमान की बात कर के इस माहौल को खराब करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अब 60 साल के बाद क्या ये यह कहना चाहते हैं कि वे देश के वफादार नहीं हैं। मैं कहता हूं कि वे देश के वफादार हैं। उन्होंने देश के लिए कुरबानी दी है। आज भी वे लोग देश के लिए कुरबानी दे रहे हैं। आजादी के समय भी दी है। इसलिए उनके दिल को दुखाना ठीक नहीं है। उनकी कुरबानियों को कम कर के आंकना ठीक नहीं है। हमारे समाज के लिए यह अच्छी नीति नहीं है। यह हमारी स्पीरिचुअल पावर में भी नहीं है और यह हमारी भारतीय संस्कृति भी नहीं है। जो संस्कृति के ठेकेदार हैं, उनके मुंह से ऐसी भाषा अच्छी लगती होगी लेकिन आपको शोभा नहीं देती। इसलिए मैं इसका बिलकुल खंडन करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, before I call the next speaker, I want to make an announcement. I have a list of more than 75 speakers who want to participate in this discussion but it is not possible for me to give time to everyone. So, I would request that those hon. Members who want to lay their written speeches on the Table of the House, they can do so.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Sir, this annual exercise known as the General Budget is an event and different sections of the people look forward to this exercise to see how it is going to solve some of the burning problems being faced by them. The General Budget presented by the hon. Finance Minister is the fifth and the last Budget of the UPA Government. It has some spots of tokenism in it but it has failed miserably to address the basic issues involving our economy. They are aware of the commitments in the Common Minimum Programme and we have been repeatedly reminding them about it.[R20]

But unfortunately they have failed to rise to the occasion. They have failed to understand the depth and crisis in the economy, particularly in the agriculture sector. They have failed to address the issues. However, I welcome the announcement of the Government about waiver of loan of small and marginal farmers to the tune of Rs. 60,000 crore. But I do not know whether four crores of small and marginal farmers would be benefited by this. Today I find a report, the hon. Minister may explain, which says that 75 per cent of the small and marginal farmers may not benefit from this loan waiver. Again a study by an important Committee has observed that about 22.5 per cent of such farmers have borrowed credit from the institutional credit providers like the commercial banks, the co-operative banks and all and the rest have borrowed credit from the moneylenders, from friends and relatives. If that is the situation, then what is going to happen to these large numbers of distressed farmers who are indebted and are not being provided any relief? When the hon. Prime Minister was asked about this, he made a reference to a scheme that was in operation since 2004. He said that in the year 2004 the UPA Government had one such scheme which could address this problem. He said, `We adopted a scheme in which those who are indebted to moneylenders can show off their debt by going to the commercial banks and substitute the debt of moneylenders by institutional credit. That scheme is still in operation and many farmers in Andhra Pradesh have benefited by it'. This was the assurance of the hon. Prime Minister that those people who had taken loan their problem will be adequately addressed.

Sir, let me talk about the definition of the small and marginal farmers. Not only Dr. Swaminathan, but many others like Shri P. Sainath have raised this issue of definition. The National Sample Survey and such other agencies have got a particular definition. But this particular definition does not distinguish between irrigated and dry farming. Shri P. Sainath has lamented in an article that those people whose suicides initiated this move and thinking of waiver, places like Ananthapur in Andhra Pradesh and Vidarbha in Maharashtra, they are not going to be benefited. Cryptically he has made an observation that a large number of farmers in certain provinces will be enjoying the large chunk of this waiver and not the small and marginal farmers. It is not that the Government had no recommendations before it. The Radhakrishnan Committee was set up by the Government itself and it had not spoken about loan waivers, but it talked about Moneylenders Redemption Funds. The Committee spoke about consortium. That Committee spoke about the processes to uplift these indebted people out of their indebtedness so that they can join their productive activities in agriculture and contribute to agriculture because our agriculture today is in total doldrums. The Government has admitted it at the very beginning. I would just like to read it out with your permission. [R21]

> "Agriculture has struck a disappointing note. Despite a fine start in the first half of 2007-08, the growth rate for the whole year in agriculture is estimated at only 2.6 per cent."

It is for the whole decade. The population growth has surpassed food grains growth. The food grain growth is at 1.6 per cent but the population growth is at 1.9 per cent. This picture has been given. The Prime Minister has been saying it and this Government has been saying this. I agree that, of course, this Government is paying unpaid distress bill for the chaos that they had created in the previous NDA Government in agriculture and everywhere. I appreciate this observation but what the Finance Minister is not saying is this. I would like to read a section of the Radhakrishnan Committee Report. It says:

> "Neglect of agriculture – The available evidence both from macro and micro level suggests significant decline in public agricultural support system including public investment in agriculture."

This led to unprecedented distress that has been one of the causes underlying the rising trend in the incidents of farmers' suicides

> "The crisis in agriculture was well underway by late 1980s".

The Congress Government was there and economic reforms had begun with 1990s It had started in Dr. Manmohan Singh's period, passed through the NDA regime and now they have it. It is not my report. This is from Prof. Radhakrishnan Committee Report. It says:

> "The crisis in agriculture in the post reform period has become pervasive."

The culprit is elsewhere. Both the NDA and the UPA Governments are trying to cover up that particular point. It is the wrong direction in the name of economic reforms. As such, we are not against economic reforms. What is the direction? The Prime Minister says it and he is aware of it. He says that fruits of growth will be inequitably distributed and therefore, it is the duty of any popular Government to address that question. We need strong growth in agriculture, remunerative prices, productivity and all these things. He has said so many things. That means the Government is aware of these things. In 2004, it was aware of it. In 2004, while they adopted the Common Minimum Programme, they said:

> "Public investment in agricultural research, rural infrastructure and irrigation to be stepped up."

It continues to speak about the farmers' income, etc. and then it says about steps to ensure clearance of farmers' dues. They have said a lot of things.

In this year's Budget, they have spoken about irrigation, that is, the foundation of agriculture. The Government says about it. It is aware and conscious of it from those days. They have ruined agriculture and it is the Government's responsibility to revive and save it. It says:

> "While these ongoing programmes will raise the level of investment in agriculture, I think, (FM thinks) that we need an ambitious scheme of a much larger proportion. Government is of the view that massive investments are required to be made in irrigation projects. I propose to establish the Irrigation and Water Resources Finance Corporation with an initial capital of Rs. 100 crore contributed by the Central Government."

The rest is with the State Governments. The rest is story, the rest will be history. This irrigation is the foundation of agriculture. They admit it but there is an increase of only Rs. 9000 crores and for the repair of water bodies, we have to go to the World Bank. They say that some States like West Bengal, Orissa and Uttar Pradesh have done it. You go there and find out and it is your job. That is the problem. This Government knows its duty. The Government is aware of the crisis. Still, the Government is not doing enough. It is not addressing the fundamental issue that it should have addressed. We expected that at least in the last Budget, the Government should compensate for the steps that it has not taken. But, unfortunately they have lost the last opportunity. I wonder how they are going to pay for it. The NDA Government paid for it for its obsession with growth, for its obsession with "India Shining". They are now saying that they were misguided by the FICCI. I do not expect this Government to

say like that. I do not expect this Government to say that we are misguided by our advisers. The Government should use this last opportunity to initiate some measures to address the agrarian crisis.

15.16 hrs.

(Shri Balasaheb Vikhe Patil *in the Chair*)

Let me now come to social issues. Let me take up health sector. The Government's commitment was two to three per cent of the GDP. Now, it is not even one per cent of the GDP. Everything has been left to the responsibility of the States. Now, there is fifteen per cent increase. But, is it enough? Is it enough for this country? In the HDI, we are at the 128th rank. We have an emerging economy. In the price parity, we are on par with Japan, with the US, etc. But in the health sector, we are even below Bangladesh in certain public health care services; and we are even below some sub-Saharan countries.

But this Government, even after being quite conscious about public health care system, has done precious little. If you take into account the inflation, the allocation is reduced. Ten days back the inflation was 5.5 per cent. Now, it may have gone up to six per cent.

Allocation has been reduced in terms of food subsidy; in terms of health care; and for education there is very nominal increase. Unemployment is a big problem in our country. We want that the Employment Guarantee Programme should be extended to all the districts and that this Programme should be extended to urban areas also.

There was a concern expressed in the last year's Budget about urban unemployment. People are losing jobs because of the wrong policies, like privatisation, etc. In the public sector joblessness is growing and the private sector is not adequately compensating for that joblessness. In the small industries, reservation is continued to be done away with. There is liberal imports, which is occupying the Indian markets, which is making our small scale and cottage sector less competitive. It is resulting in loss of jobs because small and cottage industries provide a good number of jobs. Agriculture is becoming uneconomic and unviable. Dr. Swaminathan's Committee Report says this. Forty per cent of the farmers want to leave agriculture. Non-farming activities are increasing. Of the Indian workforce, 92 per cent are in the unorganised sector. We insisted upon the Government to do something for them, like extending some social security and providing them with jobs, etc. But this time there is no mention about it. There is only a lip service to the unorganised sector. [MSOffice22] The Bill is yet to come in spite of the recommendations of the Standing Committee. Regarding that also, on 1st of October, they had come out with one Scheme. On 2nd of October, they had come out with another Scheme. These are the two Schemes. The third one is about the elderly, the senior citizens. There is nothing more. But the people are growing impatient. I am not trying to illustrate how it is happening because the Government knows better than I know. The Home Minister is sitting here. Frustration is rampant among the youth of this country. There is lack of job opportunities. There is total frustration. There is lesser job opportunities in agriculture, lesser job opportunities in other sectors and more retrenchment. The Government is obsessed with growth. What is the result of this growth? About 51 per cent of the GDP is accounted for 53 billionaires of this country. The richie-rich are becoming richer. They are richer than most of the rich countries of the world. I repeat that 53 billionaires are accounting for 51 per cent of the GDP in our country. On the other hand, the Government Report itself says - the Arjun Sengupta Committee Report - that 78 per cent of the Indian people live with Rs. 9 to Rs.20 a day after sixty years of Independence. What do they want? They want to perpetuate this gap. If they want to perpetuate this gap with a certain tokenism, with token gestures to the small and the marginal farmers, with some sops in the name of social security here and there, I caution the Government.

The Government is playing with fire. More regional insurgency, more manifestation of frustration in several ways is there. They are being exploited by them also. By the Hindu card, by their communal card, they are trying to divide the nation, trying to weaken our secular democracy. To save the nation from the hands of the communalists, to render justice to the Dalits, Scheduled Caste people, Scheduled Tribe people, OBCs and also the minorities, the Government is moving in the right path but not adequately. It is not as they should have done according to their commitment in the Common Minimum Programme. That is our charge. Opportunities are being lost.

In the matter of food security, I have mentioned it. Food insecurity is looming large. The population growth is surpassing during the last ten years of reforms. On the one hand, there is less availability. The *Economic Survey* says that it ranges from 68 grams a day to 12 grams a day. In respect of availability of pulses, it is miserable. It is 33 grams. About 56 grams was available 30 years back. It is declining. The prices of wheat, rice, dhal or whatever you call it, are becoming unbearable. About 55 per cent of the expense of the rural household is for food only. What will they do? The new Index is coming. It is about the WPI-led inflation. The Arjun Sengupta Committee is coming out with fuel price growth. It is adequately included. The inflation figure will be much higher. Why is it that you are raising the prices of petrol and diesel? You have earned so much of money in

the name of Oil Development Fund. You have not given anything for the development of the oil sector. We have suggested that instead *of ad valorem,* you can go for specific duty. It is not that we are agitating on nothing. We have concretely suggested one thing. Why do you not set up a Stabilisation Fund for diesel and petrol?[R23]

This is because when the prices of petrol and diesel are raised, it has a cascading effect on all the essential commodities. In the Budget there is simply nothing said about it.

Sir, the Government was committed for universalisation of the Public Distribution System. But what is the status today? The allocation of rice to Kerala has been reduced by 50 per cent, wheat allocation for APL families in West Bengal is stopped and wheat is being imported. Once we took pride by saying that we are self-sufficient in food, but now, continuously, year after year we are importing wheat and this year also we are importing wheat. It is said that there is some serious problem throughout the country and so there is a decline in the production of wheat. It is also said that because of the switching over to bio-fuel and all that, there is a decline in the production of certain other commodities. That means we are integrating with the world economy. We wanted that. This is the problem with this Government. Sometimes they say that we have not fully integrated. So, when the 1997 crisis touched other countries, it could not touch us. Even after what has happened in the sub prime crisis in the United States of America, they said that it will not touch us. Now they say that the crisis in the US Stock Market will have an effect on our market also.

Sir, on commodities, we have been saying that one of the instruments of controlling the price, particularly of foodgrains, is to stop forward trading in essential commodities. The Government has banned it. Now, again they are trying to strengthen it by allowing FDI and by allowing changes. There is rampant speculation on essential commodities. Our farmers are not getting remunerative prices for their produce and in double the price the Government is importing wheat from Australia and other countries. When will they stop it? The previous Government was exporting our foodgrains at half the price. The Prime Minister has rightly pointed out that this is ruining our economy, this is ruining our agriculture and this is ruining our farmers. But after taking the lessons, what are you doing?

Sir, a loan waiver scheme to the tune of Rs. 60,000 crore has been announced in the Budget and it is said that four crores of small and marginal farmers will be benefited. I do not know where the money will come from. We are told that on Friday the hon. Finance Minister will announce as to where the money will come from, whether through borrowings, whether through some bonds and some cash. Otherwise, our banks would not get back the money and they will show it in their balance-sheets. Then, the 2009 is set as the target date for certain financial sector reforms.

What will happen to the cooperatives? In my constituency, people are saying that they have borrowed to pay back the loan that they have taken from the banks because they have the culture of paying back and so they are deprived of the benefit under this loan waiver. Is it not creating a division in the society? What will happen to those who have paid back the money to cooperatives with great hardship, by taking money from their friends and by selling the ornaments of their daughters? Our friends on the other side are dividing the country on communal lines, but you should not divide our farmers as those who have paid back loans and those who have not paid back loans. You should not divide them, those farmers in Vidharba who are suffering because of their quantum of land on a particular crop, cotton, do not distinguish.[R24] [r25]Redefine small and marginal farmers. Let there be appropriate assessment of the situation giving relief to all those who suffered because indebtedness is not for production loan only, sometimes some heavy deals take place and for these also, for the medical bills, etc. it has been taken. Some cooperative people have been telling me that they have to give the details of loans taken by the farmers by 15th March. Is it possible for them? It is such a haphazard sort of an exercise, but still I welcome it. It is better than not doing anything. A tokenism is better than not doing anything.

Now, let me come to the gender budgeting. At long last they have woken up to this -- women reservation, women at the top of the political party, women's share in the political organisation and all that. Suddenly they have woken up. It is very ironical. But late is good. But this gender budgeting exercise is a clumsy one, but I do not know how they have come to this conclusion. I think, it should be re-looked, though I am not going into the details. But it can be done in a more transparent manner without confusing the allocation done exclusively for children. Of course, the mothers and children are always given relief and all these things.

Now, I come to Government's tax code. The Government has been saying for long that we shall come with a tax code to do away with the exemptions. Maybe some exemptions are good for countrymen and some exemptions are not at all required. The Government itself says that 40 per cent of the budgetary collection is given as exemption. It is according to the Government's own admission. But what does the Government propose to do with regard to these huge arrears? Twenty per cent is the effective tax rate, although statutory rate is 33 and odd per cent.

I found a comparison made by some economists between India and China, India and the US and all those things. The

Indian corporate sector gets the highest quantum of exemptions. But the Government is obsessed with Sensex and Forex. They are obsessed with growth and in spite of the Prime Minister's admission, they do not care much about the distribution, the benefits of growth to the agriculturists, to the unorganised sector, to the poor unemployed, to the middleclass, to the suffering India. The Government says that it gets 42 per cent of the revenue collection plus buoyancy. But how much of it are they giving for the social sector? We have been repeatedly insisting that long-term capital gain is one area that they must address. It is good that they have imposed something on the short-term capital gains.

As far as double taxation is concerned, avoid the Mauritius route. My friends are here, who worked with me in some Committee. They agreed with me there about what is happening. Indian money is going and coming out through the Mauritius route and enjoying all the benefits. Repeatedly I had drawn the attention of this Government asking how many people are there in our country who are richi-rich. In the written submission they have mentioned that they have an income of more than ten lak[r26]hs.

In their returns that they submitted, they mentioned that they had an income of more than Rs. 10 lakh. Again I am asking it. Is it by the tax administration, by the philosophy of, what they say, moderate tax and more compliance and all these philosophies? But the Indian psyche is different. Still now I insist let the Finance Minister come to this House with the figures as to how many such persons are there? There are 53 billionaires and there are one lakh people having huge assets in our country. They can buy out assets of other countries also. How many people are the Richie Rich, the high net worth individuals in the corporate sector? They declared in their returns that they have an income of more than Rs. 10 lakh.

Some of my colleagues will address some of the other issues. I would like to conclude by saying that this Government had got a lot of opportunities. For the last four years, we supported this Government on the basis of the Common Minimum Programme. We do not say that they have not done anything. At least the National Rural Employment scheme is one of the great achievements of this UPA Government. I fully agree. I hope that, similarly, the Prime Minister is quite conscious about the Unorganised Sector Bill and he has mentioned about it, about equity, about these unfortunate people who constitute 92 per cent of our workforce. As soon as possible, the Government must come forward with the Bill and provision for adequate fund must be made for them and there should not be token or lip service.

Again I emphasise – what he said – the last two points. The fundamentals ailing agriculture will have to be addressed. The greatest concern for the nation is the declining food-grain production and food insecurity. For that purpose, we have been repeatedly demanding that PDS should be strengthened and it should be expanded. There should be a reorientation in the whole scheme of distribution of food-grains to the public.

With this objective in view, I believe that this Government can exonerate at least partly from the sins they have committed by not addressing their commitments fully during this period. Thank you.

***श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली (वाशिम):** सभापति महोदय, बजट 2008-2009 के लिए मैं आपके माध्यम से अपनी मांग रखना चाहती हूं। इस बजट में किसानों के लिए ऋण माफी दी गयी है और जहां आत्महत्या किसानों की उसमें से महाराष्ट्र एक राज्य है, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है उस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहती हूं। मंत्री जी ने घोषणा की है कि दो हैक्टेयर के किसानों का कर्जा माफ होगा। यह घोषणा तो बाकी राजयों के लिए तो ठीक हो सकती है लेकिन जिन राज्यों में आत्महत्या हुई है और उस राज्यों के जिन जिलों में यह हुई है जैसे महाराष्ट्र के विदर्भ में जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनके पास जो जमीन है उसमें 5 से 10 एकड़ के जो किसान है उनकी संख्या 20.7औ है और जो 10 से 20 एकड़ के जो किसान हैं वह 15.3औ की संख्या में है और 5 से 20 एकड़ वाले किसानों की संख्या 36औ है और आत्महत्या करने वाले किसानों की जो संख्या है वह सारे प्रकार के किसानों की है। वह फिर 5 एकड़ वाला किसान हो या 20 एकड़ वाला किसान हो। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि जो जमीन की मर्यादा रखी गयी है वह 5 एकडद्य की न रखकर उसे बढ़ाया जाये और उसकी मर्यादा 20 एकड़ तक बढ़ाया जाये। क्योंकि विदर्भ में रहने वाले जो किसान हैं उनके पास जमीन तो ज्यादा है लेकिन ऐरिगेशन न होने के कारण उस खेती में उत्पादन बहुत ही कम होता है और इस कारण आत्महत्या बढ़ती ही जा रही है। इसलिए यह जो जमीन की मर्यादा न रखकर उसे बढाने की आवश्यकता है और सर विदर्भ, महाराष्ट्र के किसानों की जो स्थिति है वह ध्यान में रखकर उसे लाभ देने की आवश्यकता है।

सर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं कि जो महाराष्ट्र का आत्महत्या करने वाले किसानों का क्षेत्र है उसमें शिक्षा की भी कमी है। उसे ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करती हूं कि वाशिम जो उन 6 जिलों में आता है जहां बड़ी संख्या में आत्महत्या हुई है उस वाशिम जिले में आई आई टी या आई आई एम को दिया जाये और यहां पर शिक्षा की जो कमी है उसे पूरा किया जाये। सर इसी के साथ जो मंत्री जी ने नेहरू युवा केंद्र के लिए घोषणा की है उसमें उन्होंने कहा है कि इस बजट में 123 नये नेहरू युवा केंद्र दिये जायेंगे । सर मैं 1999 से वाशिम जो गया जिला बना है वहां पर नये नहेरू युवा केंद्र की स्थापना की जाये। अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती है कि वाशिम के लिए केंद्र दिया जाये

सर इसी के साथ साथ माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में स्वास्थ्य के लिए भी कहा है लेकिन हम देख रहे हैं कि गांवों में स्वास्थ्य की सुविधा बहुत ही कम मिल पाती है जो आज आयुर्वेद के डाक्टर है

---

* Speech was laid on the Table

वह आज की एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और गांव में हम सेवा देना भी चाहते हैं तो यह डाक्टर ऐसी सेवा नहीं दे पाते। इसलिए मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग है जो आयुर्वेद के डाक्टर है उनका शिलेबस है उसे इंटीग्रेटेड शिलॉबस बनाया जाये और उन्हें एलोपैथी की प्रैक्टिस के लिए मान्यता दी जाये।

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): श्रीमन्, मेरे से पहले आदरणीय रूप चंद पाल जी ने बहुत ही विस्तृत और तथ्यात्मक बातें सदन के सामने रखी हैं। मेरे दल से अन्य सदस्य भी बोलना चाहेंगे इसलिए मैं संक्षेप में कुछ बिंदुओं पर ही बात कहना चाहूंगा।

जब भी कभी कोई संकट की घड़ी आती है, किसी परिवार पर या किसी राज्य पर कोई संकट आता है तो जिसके हाथ में खज़ाना होता है, जिसके हाथ में अर्थ की कुंजी होती है, लोगों को उसी से उम्मीद होती है कि वह राहत देने का काम करेगा और समस्याओं को निपटाने तथा उनका निराकरण करने का काम करेगा। यद्यपि कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जिनका आभास सबको है। वित्त मंत्री जी ने भी कई वर्षों से अपने बजट भाषणों में इसकी तरफ संकेत भी किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान खासतौर से एक समस्या पर आकर्षित करना चाहूंगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक खासतौर से हमारे वैज्ञानिक भी लगातार स्टडी कर रहे हैं कि जलवायु में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है।[R27] जो एटमोस्फेयर है, जिसमें 78 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, 21 प्रतिशत आक्सीजन और एक प्रतिशत अन्य गैस होती हैं, जिनमें कार्बन-डाइआक्साइड, नाइट्रस-आक्साइड या मिथेन जैसी गैसे हैं, जिन्हें ग्रीन-हाउस गैसें कहते हैं। इस ग्रीन-हाउसेज गैसेज के अत्यधिक रिसाव के कारण जो टैंपेचर में वृद्धि हो रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो मैं इस बात पर आना चाहूंगा कि इसी की वजह से, कुछ साल पहले माननीय वित्त मंत्री ने कुछ बातें, अपने बजट भाषण में निरंतर कही। हमारे वैज्ञानिकों को आशंका है कि वर्ष 2100 तक आते-आते जो हमारे एटमोस्फेयर का टैंपेचर है उसके 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की संभावना है। जिसके चलते गेहूं की फसल का उत्पादन 10 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड टैंपेचर बढ़ता है तो हिंदुस्तान में ओवरआल 4 मिलियन टन तक गेहूं के उत्पादन में कमी हो सकती है। प्रश्न यह है कि इस समस्या का निराकरण कैसे होगा? जलस्तर निरंतर नीचे जा रहा है। प्रतिवर्ष लगभग 6 फुट पानी का स्तर गिर रहा है और अगर यही स्थिति रही तो वर्ष 2025 तक देश में पीने के पानी का भयानक संकट हो जाएगा। खेती की सिंचाई की बात तो दूर, पीने के पानी का संकट पैदा हो जाएगा। फिर आप जितना मर्जी नयी तकनीक या नये सीड आप देते रहिये, कोई चीज काम में आने वाली नहीं है। मैं इस संबंध में दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। एक तो वाटर मैनेजमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ इंवैस्टमेंट होना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब उन्होंने वित्तीय वर्ष 2005-2006 का बजट पेश किया था तो अपनी बजट स्पीच में उन्होंने कहा था कि :-

> "The National Project, announced by me last July, for the repair, renovation and restoration of water bodies will be launched in the month of March 2005. The pilot project is planned for 16 districts in nine States and will cover nearly 700 water bodies, and 20,000 hectares of additional land will come under irrigation. The allocation for the pilot project has been increased to Rs. 100 crore in 2005-06. â€¦"

इसी तरह की बात आपने हर बार कही है। पानी की वाटर-बॉडीज को रेनोवेट करने के लिए नये जल-संसाधन के मैनेजमेंट के लिए और मुझे निराशा तब हुई जब आपने वर्ष 2007-2008 में इसी संबंध में यह कहा कि :-

> "Honourable Members will recall that, in March 2005, a pilot project to repair, renovate and restore water bodies was launched in 13 States. I am happy to inform the House that the World Bank has signed a loan agreement with Tamil Nadu for Rs.2,182 crore to restore 5,763 water bodies having a command area of 400,000 hectares. An agreement for Andhra Pradesh is expected to be concluded in March 2007 and will cover 3,000 water bodies with a command area of 250,000 hectares. â€¦"[r28]

इसी तरह की प्रिप्रेशंस अन्य राज्यों में भी हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। जो पैसा आप देते हैं, वह कैसे खर्च होता है? इस बार आपने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि उसकी मोनिटरिंग के लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पुराने तालाबों को, पुरानी झीलों को रिस्टोर करने की बात तो छोड़िए, पैसा खर्च करने के लिए दो-दो मीटर ऊंची जमीन पर, जहां बारिश का पानी एक मिनट नहीं रुकता है। वहां तालाब खोदे जा रहे हैं,

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): This time, I did update this announcement. Agreements have been signed with Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka of a total sum of US$ 738 million, that is approximately, Rs. 3,000 crore. The command area is 9 lakh hectare. Now, implementation of this project is with the Government of Tamil Nadu, the Government of Andhra Pradesh and the Government of Karnataka. There is, of course, in the Ministry of Water Resources, a Monitoring Committee, which monitors it. But the State Governments have to implement it. The State Governments have set up either a Special Purpose Vehicle or in some cases, they are doing it through their PWD. If the implementation is bad, we can only pull up the State Governments and advise them to improve the implementation. Whether you are in the Government or I am in the Government, what is it that you or I can do, except design a scheme, get the money, give it to the State Governments and appeal to them to implement it effectively?

The larger question, Prof. Ram Gopal Yadavji, is: why are the other States not coming forward when the money is available? The World Bank agrees to lend the money, why are the other States not coming forward? Last year, I mentioned Orissa and West Bengal; and this year again, I have to mention Oriss and West Bengal. They are simply not coming forward with their plans to me to take it to the World Bank and get the money. The money is available; the will is not available in the State Governmentsâ€¦ (*Interruptions*)

PROF. RAM GOPAL YADAV : Sir, this is not a question of one or two or three States. It is a question of all the States...(*Interruptions*) The question is about the entire country; and the hon. Finance Minister is the Finance Minister of the entire country.

SHRI P. CHIDAMBARAM: That is why we are getting the scheme.

PROF. RAM GOPAL YADAV : When the existence of the entire new generation is in danger, then, will you, Mr. Minister, wait for the prayer of the State?...(*Interruptions*) Under the Constitution, under special circumstances, the Central Government has every right to direct the State Government to get in a particular way.

MR. CHAIRMAN : The Centre cannot encroach upon the authority of the State Government.

...(*Interruptions*)

प्रो. राम गोपाल यादव : महोदय, यह गंभीर स्थिति है और मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने नजदीक से हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को देखा है। मेरी बेटी की शादी उसी इलाके में हुई है और मैं अभी वहां गया था। वहां जमीन फट रही है, पीने के लिए पानी नहीं है। आठ-आठ किलोमीटर दूर से लोग बैलगाड़ियों में ड्रम रखकर जाते हैं और नदियों से पानी भर कर लाते हैं और वह भी गंदा पानी होता है। अभी तो गंदा पानी है, बाद में शायद वह पानी भी उपलब्ध नहीं होगा।

Sir, there is one thing more, which I want to say. सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमैंट में यह फैसला दिया कि वर्ष 1950 के बाद से जितने भी तालाबों की जमीन को पट्टे पर दिया है, जिस जमीन पर लोग खेती करने लगे हैं और वे तालाब खत्म हो रहे हैं, वे सारे पट्टे राज्य सरकार निरस्त करे। ये तमाम ऐसी बातें हैं, जिन पर आपको डायरेक्शन देना चाहिए। आप कभी भी अचानक मोनिटरिंग करने के लिए कमेटी भेज दें, तो आप देख सकते हैं कि पैसे को प्रोपर तरीके से खर्च नहीं किया जा रहा है। If somebody is not spending money in a proper way, the Centre should give directions. जैसा राजीव गांधी जी ने कहा था कि एक रुपए में से पन्द्रह पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं, मुझे लगता है कि अब वह पैसा भी नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चाहे रोजगार गारंटी योजना हो या मिड डे मील की योजना हो, इनकी क्या स्थिति है?[R29] यह कह कर कि स्टेट्स इम्पलीमैंट कर सकती हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप पैसा देते हैं, आप मालिक हैं, आप इसे ठीक कर सकते हैं। मिड-डे मील में कल एक सवाल आया था और कहा गया था कि जहां लड़के-लड़कियां ज्यादा हैं, वे सब स्कूल जाएं, कोई नहीं बचे, उन्हें आकर्षित करने के लिए कोई योजना बनाई जाए जिससे गरीब लोगों के बच्चे स्कूल जाएं। सच्चाई क्या है? सब टीचर्स उनमें इनवॉल्व होते हैं, उन्हें कुछ पढ़ाना-लिखाना नहीं है, हर गांव में एक नया मॉन्टेसरी स्कूल खुल गया है, जिस में बच्चे ज्यादा हैं, प्राइमरी स्कूलों में कम हैं। एनरोलमेंट है, लेकिन सब पैसा खा जाते हैं।

MR. CHAIRMAN : School is a State subject. What can we do?

PROF. RAM GOPAL YADAV : The money is given by the Central Government. Should I not raise it? ...(*Interruptions*) मंत्री जी कह रहे हैं, मैं इतना पैसा दे रहा हूं, इस कारण मैं यह बात कर रहा हूं।

ये बातें वाटर बॉड़ी से संबंधित थी। मेरा सुझाव था कि इस पर जैसे भी हो सकता है ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी का स्तर जो गिर रहा है, उसे रिचार्ज किया जा सके। इसके लिए वाटर बॉडीज का रिकनस्ट्रक्शन, रैनोवेशन या जो भी हो सकता है, वे प्रयास करने चाहिए। इसके लिए पैसा दिया जा रहा है लेकिन वह काफी नहीं है। वर्ल्ड बैंक से लोन लें या कहीं और से लें लेकिन सैंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे। यह सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है कि अगर पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो हम न कुछ पैदा कर सकते हैं, चाहे आप बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बना दीजिए, कनक्रीट के जंगल बना दीजिए, बहुत बढ़िया शहर बना दीजिए, पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? यह स्थिति है।

किसानों के लिए इंश्योरेंस का कवरेज होना चाहिए। मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के बारे में लगातार प्रयास किया जा रहा है। संसद की एग्रीकल्चर कमेटी ने भी रिकमेंड किया है कि इसे गांव लैवल तक यूनिट के रूप में और उसके बाद किसान को इकाई मान कर किया जाए। कम से कम इसे गांव लैवल पर किया जाए, जिसके लिए रिकमेंड भी किया है लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, पूरा नुकसान हो जाता है। अगर कहीं जिले पर है तो वह ब्लॉक पर आ गया है। इंश्योरेंस का कवर किसानों को मिलना चाहिए। गांव स्तर पर यूनिट मानना चाहिए, हमारी यह मांग है क्योंकि सबसे ज्यादा 66 परसेंट के आसपास लोग खेती पर निर्भर हैं। बड़े पैमाने पर 56 परसेंट से लेकर 60 परसेंट लोगों को खेती से रोजगार मिलता है, कुछ लोग 63 परसेंट कहते हैं। अभी भी खेती से लोगों को रोजगार मिलता है और वे उस पर निर्भर रहते हैं।

इनफ्रास्ट्रक्चर की बात में मैं एक बात कहना भूल गया था। वाटर बॉडीज के अलावा एक काम और भी हो सकता है कि हमारे वैज्ञानिकों को इतनी सुविधाएं दी जाएं, इतना धन उपलब्ध करवाया जाए कि वे इस तरह के रिसर्च भी कर सकें कि बहुत कम बारिश में या ड्राई लैंड या रेन फैड एरियाज में भी नए बीजों के माध्यम से, फसलें कम पानी से ज्यादा अन्न पैदा कर सकें। इस तरह के बीज तैयार करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन को ज्यादा मदद देनी चाहिए। यद्यपि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कुल मिला कर पिछले साल की तुलना में थोड़ा ज्यादा कुल बजट का 3.42 परसेंट हिस्सा दिया है लेकिन एग्रीकल्चर रिसर्च ऐंड एजुकेशन पर वर्ष 2006-07 में .53 परसेंट, 2007-08 में .51 परसेंट और इस बार घटकर .46 परसेंट रह गया है। जब तक आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन्स को पूरी मदद नहीं देंगे तब तक नए सीड्स और नई वैराइटीज को डैवलप नहीं कर सकते हैं। वैसे ही वहां साइंटिस्ट्स की कमी है। आपकी कृपा से पहले भी मैंने सप्लीमेंटरी प्रश्न किया था, आपने कहा था कि साइंटिस्ट्स के अपाइंटमेंट के लिए कोई बंदिश नहीं है, अपाइंटमेंट होना तो आईसीएआर में शुरू हुआ लेकिन अब भी वहां मैन पावर की बहुत कमी है जिससे रिसर्च जिस स्तर पर होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे यहां जो एग्रीकल्चर जीडीपी है, वह कुल जीडीपी का लगभग 18.50 परसेंट कन्ट्रीब्यूट कर रही है जब देश आजाद हुआ था तब सन् 1950 में लगभग 50 फीसदी हिस्सा था और अब घटकर इस वर्ष 18.5 परसेंट रह गया है।

MR. CHAIRMAN: It was 54 per cent.

प्रो. राम गोपाल यादव : रिसर्च पर हमारे पड़ोसी देश, श्री लंका में GDP का 0.9 परसेंट खर्च हो रहा है और लैटिन अमेरिकी जैसे गरीब देशों में .8 परसेंट खर्च करते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ में उनकी जीडीपी के 4.2 परसेंट तक खर्च करते हैं लेकिन हमारा अब भी इस वर्ष एलोकेशन .46 परसेंट है। हालांकि विभाग द्वारा अलग-अलग वर्षों में दसवें प्लान के लिए 15,000 करोड़ रुपया मांगा था लेकिन योजना आयोग ने केवल 5368 करोड़ रुपए दिए। 11वीं योजना के लिए 31,672 करोड़ रुपए मांगे गए लेकिन 12023 करोड़ रुपए दिए गए और इस बजट में 2646 की डिमांड थी और लेकिन आपने 1760 करोड़ रुपए दिए। रिसर्च पर एग्रीकल्चर से संबंधित नए सीड्स और नई वैरायटी, चाहे वह प्लांट या क्रॉप से संबंधित हो या अन्य मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में एनीमल हजबैंड्री और फिशरीज से संबंधित हो, जब तक इनकी रिसर्च के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, पर्याप्त धन नहीं देंगे तब तक रिजल्ट्स बेहतर नहीं आ सकते हैं। वह गंभीर संकट जो आने वाला है उसे देखते हुए यह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

मैं सिर्फ दो या तीन मिनट बोलूंगा, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं घंटी बजने से पहले अपनी बात समाप्त कर देता हूं, ज्यादा समय लेने की मेरी आदत ही नहीं है।

MR. CHAIRMAN: I just wanted to request you to conclude your speech. Please do not take it otherwise. Please continue your speech.

प्रो. राम गोपाल यादव : आपने स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में किसान आयोग बनाया था और इसने सिफारिशें भी की थी जिसके बारे में रूपचंद पाल जी ने भी कहा है। उसमें सब्सिडी की अन्य बातों के अलावा किसानों को चार परसेंट इन्टरस्ट पर लोन देने की बात थी लेकिन आप इसके बारे में साएलेंट हो गए हैं। आपने कर्ज तो माफ किया, लेकिन इस बारे में हमारा मानना है और जैसा रूपचंद पाल जी ने कहा आपने सिंचित और असिंचित में कोई फर्क नहीं किया। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का बयान टीवी पर देख रहा था, उन्होंने कहा कि विदर्भ में लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, जहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं वहां लाभ नहीं पहुंचता है। वहां एवरेज 2.4 हेक्टेयर है, दो से ज्यादा है, बुंदेलखंड में 8 और 10 हेक्टेयर से कम नहीं है, लेकिन वहां एक बूंद पानी भी नहीं है, वहां किसान भूखा मर रहा है, उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप जून तक माफ कर देंगे, आपका कमिटमेंट है इसके बाद वे फ्रेश लोन के लिए अप्लाई करेंगे लेकिन जो इंटरस्ट रेट को 7 परसेंट कर दिया है, पहले की तुलना में कम किया है। अगर वह 3 लाख तक कर्ज लेगा तो 7 परसेंट किया है लेकिन इसे 4 परसेंट पर करने के लिए सिफारिश करनी चाहिए थी, यह मेरा आपसे अनुरोध है। मेरा आरोप है कि एग्रीकल्चर की निरंतर उपेक्षा हो रही है और इसलिए किसानों की यह बदहाली है। जो किसान इतने बड़े पैमाने पर देश में लोगों को रोजीरोटी देते हैं, उनके लिए इस वर्ष बजट में 12865 करोड़ रुपए दिए हैं।[r30]

16.00 hrs.

जबकि कम्युनिकेशंस पर 21937 करोड़ रुपये और सामाजिक सेवाओं पर 95919 करोड़ रुपये अलाट किये हैं। जबकि एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण सैक्टर पर तुलनात्मक दृष्टि से काफी कम है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की दुर्दशा इसलिए भी हो रही है, क्योंकि कहीं भी किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिला। तमाम अनुमान, तमाम रिसर्वेज हुई, हिसाब-किताब लगाया गया और यह पाया गया कि इस वक्त जो प्रति क्विंटल धान पैदा होता है, उस पर एक हजार रुपये खर्च होता है और गेहूं पर लगभग नौ सौ रुपये खर्च होता है। जब एक हजार रुपये क्विंटल लागत आयेगी और साढ़े छः सौ रुपये क्विंटल के हिसाब से किसान की बिक्री हो तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। इसलिए जो कमीशन आपने ही बनाया था, उसी ने रिकमैन्ड किया था कि लागत मूल्य का पचास परसैन्ट बोनस और दिया जाना चाहिए, तब किसान लाभ में पहुंचेगा और जब किसान को लाभकारी मूल्य मिलेगा तो किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा। आत्महत्या के मूल में उसके लागत मूल्य से कम पैसा मिलना मुख्य कारण है। यह सबसे बड़ा संकट किसान के सामने है। किसान की जमीन पर बोझ कम हो, यह भी बहुत जरूरी है और उसके लिए रोजगार के नये एवेन्यूज तलाशने होंगे। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज आदि पर ध्यान देना होगा, ताकि लोगों को रोजी-रोटी ज्यादा मिले और खेती से कुछ वजन कम हो। वरना यह दुर्दशा लगातार बनी रहेगी।

सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। हालांकि इस बजट के आने के बाद कई चीजों के दाम बहुत बढ़ गये हैं। कार के दाम कम हो गये हैं, लेकिन साइकिल के दाम बढ़ गये हैं। आपने कार पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, लेकिन स्टील के दाम बढ़े, सीमेंट के दाम बढ़े। आप जो इंदिरा आवास योजना आदि के लिए पैसा दे रहे हैं, ये सब बन नहीं पायेंगे। ये इसलिए नहीं बन पायेंगे कि कोई आदमी एक कमरा भी नहीं बना सकता, चूंकि सीमेंट और स्टील के दाम आसमान को छू रहे हैं। जो बड़े लोग हैं, जो पचास अरब और सौ-सौ अरब के एक-एक प्लाट खरीद रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, चाहे आप कितना भी महंगा कर दीजिए। लेकिन जो गरीब आदमी है, वह एक कमरा भी नहीं बना सकता है, आज यह हालत हो गई है। स्टील के दाम एक साल में कितना बढ़े, आपको इस पर विचार करना चाहिए कि इतने दाम क्यों बढ़े। सीमेंट का दाम एकदम से स्टीप राइज कैसे हो जाता है, क्या आपने कभी इसकी मानिटरिंग की है कि ऐसा क्यों हुआ? जिन संस्थाओं को, जिन एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जहां आप मदद कर रहे हैं, अब यह चर्चा चलने लगी है कि साइंस और टैक्नोलोजी जहां पढ़ाई जा रही है, उन्हें मदद कीजिए, इनसे कुछ होता है। मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि एक अपसंस्कृति इस देश में पैदा होने लगी है। अब जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं है, जैसे आई.आई.एम्स. आदि हैं, जिनमें पढ़ने वाले लोग, वे सिर्फ न अपने प्रति जिम्मेदार हैं, न अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी महसूस करते हैं और न अपने राज्य और देश के प्रति जिम्मेदारी महसूस करते हैं और अंततोगत्वा सब अमेरिका जाना चाहते हैं। जिन पर आप इतना पैसा खर्च करते हैं। अभी कोलकाता के आई.आई.एम. ने एक लाख रुपये फीस बढ़ा दी। वहां कौन गरीब आदमी अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेज पा रहा है। हमारे पूरे इटावा जिले से पिछले पांच-सात साल में केवल दो बच्चे ही आई.आई.एम. अहमदाबाद में पढ़ने के लिए गए। एक मेरे कुलीग लैक्चरर थे, उनका लड़का था और दूसरी मेरे मित्र की बेटी गई, जो बहुत एवरेज्ड ऑर्डिनेरी थी। वे लोग आई.आई.टी. से पास हुए, तब कहीं जा पाये। वहां किसी गरीब आदमी का लड़का नहीं पहुंच पा रहा है। वहां के बच्चों को पैकेज मिलता है और अखबारों में निकलता है कि कैम्पस में आकर बच्चों को इतने का पैकेज मिला। मैं समझता हूं कि ह्यूमैनेटीज और सोशल साइंसेज वगैरह को भी आप अनुदान दीजिए। आप ये पैसा पैदा करने वाली मशीनें पैदा कर रहे हैं, जो किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। आप उन सब्जैक्ट्स और उन संस्थाओं को भी मदद कीजिए, जो आदमी पैदा करती है। मेरा आपसे यह अनुरोध है और इसके साथ ही आप इस महंगाई पर काबू कीजिए, किसानों को आपने जो कर्ज दिया है, उसमें सिंचित और असिंचित में फर्क कीजिएगा, वरना कोई लाभ नहीं होगा। कम से कम असिंचित क्षेत्र में जो दो हैक्टेअर की सीमा है, आप इसे बढ़ाकर दस हैक्टेअर कर दीजिएगा[b31]। हमारे यहां 10 हेक्टेयर से कम बुंदेलखंड में किसी के पास जमीन ही नहीं है। अगर अगर कर देंगे तो इसी के साथ कुछ लोगों को राहत हो जाएगी।

*DR. M. JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): Hon'ble Speaker Sir, Thank you very much for giving me the opportunity to participate in Debate on the General Budget 2008-09 and supplementary grants.

Our Finance Minister had taken lot of strain and must have had lot of pressure on him to formulate such type of Budget. I feel the Finance Minister have tried to satisfy every section of the Society on Paper, but on reality it will prove his ill conceived in certain fields.

)1 NREGS Though the intention of passing the National Rural Employment Guarantee Scheme is good and received support from all political parties. The Scheme is more misused than used for the benefit of the people for whom it was meant by Congress workers and leaders.

This programme has become ATM for the Congress workers and leaders in our State of Andhra Pradesh and like wise in

the other States of India as payments are made on benami names and middle men are swallowing the money.

In recent past some of the National dailies have come out with survey where under this scheme only 4-6% of poor got benefited and rest 94-96% of benefit had gone to non-poor.

Though the thousands of crores of rupees spent on NREGS, no infrastructure had been created. Just it is washed away in the drains lust of Congress Leaders

2) DEBT WAIVER AND RELIEF PACKAGE The 60,000 Crores debt relief package announced for farmers, though it is welcome gesture on the part of Government, but it is not giving much relief as it is expected as per the survey conducted by some Agencies only 25% of the small and marginal farmers getting benefited and 80% if farmers are in the grip of private money lenders and

---

*Speech was laid on the Table.

Government of India had not taken any step to relieve the farmers from the private money lenders.

Even there is no Budgetary provision in the Budget. Banks are worried about their further sustinence as they have to make up the loss they are going to suffer.

The Finance Minister promise to liquidity in three years time is unbelievable and again the common tax payer will have to face the music by paying more tax burden.

OTS announced is the discrimination among farmers and total waiver to be announced to all the farmers who are having loans.

Some measures to be taken to relieve the farmers from the private money lenders clutches.

IRRIGATION SECTOR The Finance Minister had announced that the irrigation and water resources finance Corporation with initial capital of 100 crores of rupees will be established. This Corporation will mobilize resources for major and medium irrigation projects.

Under the National Irrigation Projects Scheme the major Projects were identified by the Government of India to help them to the tune of 90% of the cost by Central Government, not even a single project is identified from Andhra Pradesh which is discriminatory.

The Andhra Pradesh Projects like Itchampalli, Jurala, Vamshadhara, SRSP Phase -II, Bheema etc. fit into the grade links of selecting as a National Project.

While many Central Leaders who come to Andhra Pradesh praise the State Government of Anahdra Pradesh for taking up so many irrigation projects which are supposed to irrigation water to one crore acres. But the way the projects are being constructed and the progress, corruption involved not even a single acre of extra irrigation potential will be created than the existing irrigation potential in near future as the project will not be completed in time because of lack of funds. It is shame that not even a single project from Andhra Pradesh is included as National Irrigation Project. It is the failure of the Government of Andhra Pradesh to provide required data in respect of the Irrigation Project to the Government of India, Ministry of Water Resources to construct the Project as a National Irrigation Project.

The allocation for the irrigation and water resources, the Finance Corporation is Rs.100 crores as initial capital and Government wants to mob iles resources. The Finance Minister had not spelt out how and from where he is going to mobilize the funds again. It will be burden on the common man as Government will definitely impose some taxes and I wonder at the present rate of allocations for the Corporation how the major Projects are going to be completed in time.

PUBLIC DISTRIBUTION SYSTENM PDS had become irrelevant and defunct by the policies of the present Government.

Some of the items like sugar, the price is same in the PDS dealers and in the open market.

Kerosene on which the Government claims to be not increasing the prices is short supplied and card holders arte not getting sufficient quantity of kerosene.

HOUSING SECTOR The cost of construction of one IAY house has gone several times high than the Government providing, due to raise in the cost of cement, steel and sand and other building material apart from labour charges. The raise in the unit price from Rs.25,000 to Rs.35,000 in plain areas and from 27,000 to Rs.38,000 in hilly/difficult areas is not sufficient. The unit price of IAY house should be increased to Rs.50,000 in plain areas and Rs.75,000 in difficult hilly areas with 50% of it should be in the form of subsidy as the IAT houses are meant for SC/ST, p;hysically handicapped and other poor sections of the society.

EDUCATION AND HEALTH After the 60 Years of Independence the Hterarcy rate in India is 64% and in the women it is still low.

This is because of the lack of sufficient budgetary allocations. The Sarvashiksha Abhiyan had become Sarvabhaksha Abhiyan as the most of the funds allocated for Sarvashiksha Abhiyan is swindled away by unscrupulous elements with the help of officials at the office of Chief Minister as it has happened in Andhra Pradesh. The Chief Security Office of Chief Minister is alleged to be involved in swindling away of the funds meant for Sarvashiksha Abhiyan nearly to the tuner of hundreds of crores. Stringent action to be contemplated against such type of offenders and money should be recovered.

Number of posts of teachers and Head Masters are vacant in rural areas. These posts have to be regularly filled up to make the country totally literate and more budgetary allocation for construction of more school rooms and sanitary facilities to the children.

MID-DAY MEAL The Government previously announced that 10,000 Crores children are provided with midday meals at the cost of 11,400 crores. What is the amount spent on each child is Rs.1.40. Under the given circumstances of raising prices of essential commodities by spending Rs.1.40 a child, will get WHO standard colories Food. I request the Finance Minister to double the budget for Mid Day Meal so that children could be provided at least reasonably nutritious food.

SCHEMES BENEFITTING SCs/STs Allocations are not commensurate with the percentage of the population of Scheduled Caste and Scheduled Tribes population of the country. It is just mearly not even 3% of the total planned Budget. Budget on special component plan and tribal sub plan is diverted/ Only in the State of Andhra Pradesh. Nearly 18-20 thousands of crorrs of rupees is diverted it is alleged. Government of India to take stringent steps to stop diversion of SCP and TSP funds and allocate the funds to the tune of 25% of Gross budget for SC/STs Welfare.

In the end Sir, Inspite of the Governfment announcement Loan waiver to the small and marginal farmers to the tune of Rs.60,000 crores. The suicides of farmers are taking place unchecked. During the span days from the date of Finance Ministers Loan waive scheme announcement, 35 farmers in Andhra Pradesh have committed suicides.

Merely loan waivers are not going to help the farmers. Issues like MSP. Private Money lender issue also to be attended as 80% of loans are from the Private Money Lenders in rural areas.

The UNPA had been agitating since long time for the implementation of the Swaminathan Committee report on MSP to the Agriclture produce.

Clubbed with the loan waver scheme, unless the Government provides MSP to the Agrriculture Produce to the extent of Swaminathan Commission Report and RBI modifies its rules of Easy loan to farmers and attention towards regulation of Private lending, it is difficult to stop the suicides of the farmers and I request the Government of India to take steps in that direction. I conclude.

*SHRI DAHYABHAI VALLABHBHAI PATEL (DAMAN AND DIU): The Daman was liberated along with Goa and Diu from the Portuguese Rule on 19th December, 1961. Considering its poor development in all the fields, Goa, Daman & Diu were included in the first schedule of the Constitution as Union Territory.

- In October, 1962 Panchayat Elections were held in Goa, Daman & Diu. The Election for Legislative Assembly for Goa, Daman & Diu was also held in December, 1962 and popular Ministry has taken over the charge on 20th December, 1962.
- From 1st September, 1964 the Government of India's Administrative Control was transferred from the Ministry of External Affairs to the Ministry of Home Affairs and till date Daman & Diu are under the control of Ministry of Home Affairs after giving a Statehood to Goa in May, 1987.

Keeping these aspect in view, the UT of Daman & Diu deserves a better treatment, as far allocation of funds are concerned. But this UT has always been given a step motherly treatment in the allocation of funds. Even a much smaller UT of Lakshadweep

with fewer population has been allocated funds to the tune of rupees 263 crores, whereas for the UT of Daman & Diu only Rs.83 crores have been released against the sanctioned amount of Rs.130 crores whereas the administration of the UT of Daman & Diu has made a demand for Rs.220 crores.

Despite all these odds UT of Daman& Diu has been making rapid development in the field of industrialization since 1991 and more than 5000 LSI, MSI and SSI units have been developed during the past seventeen

* Speech was laid on the Table

years. Despite this pace of industrialization, the UT of Daman & Diu has managed to retain its beauty and cultural heritage. Therefore, about 5 lakh tourists visit Daman & Diu every year. But this industrialization and growing hospitality industry require expenditure on infrastructural needs and additional allocation of funds are required for this purpose. Even the neighbouring BJP ruled State of Gujarat is taking away much of the development potential of this small UT with its capital powered development policies.

Keeping all the aforesaid facts in view, you will very kindly appreciate that the UT of Daman and Diu has been facing a strange situation with regard to Annual Plan Size for this UT. Though the UT's Revenue Receipts are growing up consistently over the years; the allocation of plan-size has not kept pace with it. In the year 2002-03, the net receipts were Rs.116.16 crores; whereas the plan-size was Rs.44.38 crores. Similarly for the years 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, the respective revenue receipts vis-a-vis the allocated plan -sizes were Rs.145 to 45 crore, Rs.214 crore to Rs.53 crore, Rs.286 crore to Rs. 59 crore, Rs.327 crore to Rs.64 crore respectively; which indicates that the allocated annual plan-sizes over the years have not increased in comparison to revenue receipts and the gap is not only huge but also widening year by year. As a result there has not been adequate investment towards the creation of capital assets. As the UT is rapidly industrializing which is leading to increasing urbanization and pressure on infrastructure, therefore, realistic plan allocation should be made to cater to the requirements of major upgradation of infrastructure and other required socio-economic activities initiated by the Administration. Unless substantial investment is not made within a few years, the existing physical infrastructure be it roads, bridges, power and water-supply, drainage etc. and social infrastructure will crumble. Similarly, the other services such as Police and Law & Order, Health-Care, Education, Social Welfare activities also need immediate strengthening to meet the growing expectations of the people.

As the allocated plan-sizes have been kept at very low-levels in the previous yeas, it is my humble request that besides the revenue receipts of the UT Administration the needs for providing physical and social infrastructure be taken as yardstick for determining the plan sizes of the future years. You will agree with me that, unless we take immediate corrective action and make commensurate increase in the plan size of the territory, new capital assets will not be created and the existing assets will not be serviced and the socio-economic decay will step in. The UT of Daman & Diu has been earning a revenue of around Rs.3800 cores viz. Rs.3000 crores as Central Excise, Rs.500 crores as Income Tax, Rs.25 crores as local excise, Rs.130 crores as VAT, Rs.100 crores from power and Rs.50 crores as revenue, whereas the plan allocation is a meager Rs.83 crores only. Hence, I earnestly request that annual plan-size of the territory be increased substantially as already requested to the Ministry of Home Affairs, and the demand for the allocation of Rs.220 crore made by the Administration of the UT of Daman and Diu be considered and sanctioned to fulfill the needs and aspiration of the common people of this UT.

I hope the demand for additional allocation of rupees 220 crores would be considered positively in the larger public interests of the UT of Daman & Diu.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं इस सामान्य बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हुं। यह बजट स्वागत योग्य बजट है क्योंकि यह बजट ग्रामोन्मुखी और किसानों की उन्नति करने वाला है तथा इस बजट ने अल्पसंख्यकों की काफी सुध लेने का काम किया है। वित्त मंत्री जी ने वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखते हुए संतुलित और अनुशासित बजट पहली बार पेश किया है। इस बजट में जो प्रबंधन कौशल की उन्होंने इसमें झलक दिखाई है, वह स्वागत योग्य है लेकिन बजट में संतुलन के साथ-साथ विकास के लक्ष्य को भी दर्शाया गया है। पहली बार यूपीए सरकार खाद सुरक्षा मिशन कि कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े, इसके लिए राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन में जो पैसा दिया है, उसे पैसे से काम नहीं चलेगा। इसमें और पैसे देने होंगे। सरकार ने 25000 करोड़ परिव्यय से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और 4882 करोड़ रुपये परिव्यय से राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन की शुरुआत की है। दोनों योजनाएं 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वित की जाएगी। इससे खाद्यान्न पर हमारा देश कैसे आत्मनिर्भर हो, उसके लिए कम से कम इतने समय के बाद एक संकल्प तो माननीय वित्त मंत्री जी ने लिया है। एक भारी-भरकम खर्च वाली कल्याणकारी योजनाओं को बजट में शामिल करने तथा किसानों को 60,000 करोड़ रुपये की कर्जेमाफी टैक्स में छूट देने के बावजूद वित्तीय घाटा और इसमें खासकर जीडीपी 3.1 फीसदी से घटाकर अगले साल के लिए 2.5 फीसदी कर दी गई है। राजस्व घाटा जीडीपी का एक प्रतिशत आंका गया है। इससे बजट के संतुलन को बढ़ाया गया है। जिस समय यूपीए सरकार ने कार्यभार संभालना था, उस समय जीडीपी का 4.8 फीसदी था। सरकार ने 5 बजटों के दौरान सालाना 22 फीसदी राजस्व भड़ाया, इंकम टैक्स और कंपनी टैक्स से पिछले दो वर्षों में राजस्व 40 फीसदी से ज्यादा बढ़ाया है जिसके कारण सरकार आयकर दाताओं को राहत देने में समर्थ हो पायी है।

कोई भी बजट वार्षिक लेखाजोखा ही नहीं है बल्कि आम जनता के दुख-दर्द का आयना है और वह उसे प्रतिबिम्बित करता है कि दिशा क्या हो। जो आर्थिक दशा है और

जो आर्थिक दिशा है, इसे समावेश करने की कोशिश की गई है लेकिन हम कुछ जानकारी भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी जब अपना जवाब दें तो उसको स्पष्ट करें। इकॉनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया के अध्याय 7 में यह बात स्पष्ट है और उसमें कहा गया है कि खेती की भारतीय अर्थ व्यवनवस्था में बराबर महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भले ही राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इसका योगदान घटता रहा है। इस क्षेत्र के रोजगार और आजीविका सृजन में काफी अधिक भागीदारी है। सकल घरेलू उत्पाद में खेती की भागीदारी निरन्तर घटती जा रही है। यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है क्योंकि जो 1982-83 में 36.4 प्रतिशत था, वह घटकर 2006-07 में 18.5 प्रतिशत रह गई। राम गोपाल यादव जी ने भी अपने भाषण के क्रम में इसका जिक्र किया था। यह गंभीर स्थिति है, इसीलिए यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है क्योंकि आधी अरब से अधिक आबादी यानी 52 फीसदी लोग यानी जो देश की पोपुलेशन है, इसके 52 फीसदी लोगों का जो कार्यबल है, उस आबादी को निरन्तर सहायता प्रदान की जाती है।

सभापति जी, देश के पूरे कार्यबल के 52 प्रतिशत हिस्से को कृषि क्षेत्र से रोज़गार मुहैया किया जाता है। हमारे देश में कच्ची सामग्री एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें उर्वरक. कीटनाशक, कृषि उपस्कर कई उद्योगों के स्रोत रहे हैं। आज यह गम्भीर स्थिति है कि कृषि क्षेत्र में विकास गैर-कृषि क्षेत्र की तुलना में कम हुआ है। इसके बजाय जनसंख्या विकास की तुलना में यह अधिक था। वर्ष 1950-51 से लेकर वर्ष 2006-07 के बीच में जनसंख्या की बढोत्तरी की तुलना में 2.5 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। परिणामस्वरूप भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन वर्ष 1976-77 से 2005-06 के दौरान खाद्यान्न की बढ़ोत्तरी दर 1990-2007 में 1.2 प्रतिशत गिर गई जो जनसंख्या की औसत में 1.9 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी की दर की तुलना में कम है। इसलिये खाद्यान्नों और दालों की खपत में प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है, उसमें गिरावट देखी गई है। वर्ष 1990-91 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 468 ग्राम थी जो वर्ष 2005-06 में प्रति व्यक्ति गिरकर 412 ग्राम रह गई। यह गिरावट 13 प्रतिशत दर्शाता है। वर्ष 1956-57 में यह खपत 42 ग्राम थी लेकिन आज 72 ग्राम प्रति व्यक्ति से घटकर 33 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गयी है। सभापति महोदय, यही नहीं, आज भी कृषि उत्पादन में ट्रेंड स्लो हुआ है। वर्ष 2007-08 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 2.7 मिलियन टन कम हुआ है। जो उत्पादन का ट्रेड स्लो है तो खपत में भी ट्रेंड स्लो है। कृषि क्षेत्र में जीडीपी का योगदान मात्र 18.5 प्रतिशत रह गया है। यह राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। मैंने इसलिये आर्थिक सर्वेक्षण का जिक्र किया है।

सभापति जी, फूड सिक्यूरिटी हमारी महत्वपूर्ण और संवदेनशील राष्ट्रीय योजना है, इसे कैसे बढ़ाया जाये? इसे बढ़ाने के लिये जो काम हो रहे हैं, इसमें क्या प्रगति हुई है, क्योंकि इसमें कोई मौनिटरिंग सिस्टम नहीं है, इसलिये मैं चाहूंगा कि इसकी मौनिटरिंग होनी चाहिये कि कितना उत्पादन बढ़ा है, कितनी बंजर भूमि को कृषि लायक बनाकर उपजाऊ किया गया है? क्या सरकार के पास या ग्रामीण विकास विभाग के पास कोई डॉटॉ है कि कितनी जमीन को कृषि करने लायक बनाया गया है जबकि सरकार का फूड सिक्यूरिटी मिशन चल रहा है कि किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जाये ? जब तक उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषि भूमि नहीं होगी, उत्पादन कहां से बढ़ायेंगे? जमीन बढ़ाने की बात तो छोड़िये, यहां कृषि भूमि को घटाने का काम किया जा रहा है। SEZ के जरिये कृषि भूमि घटाने की बात की जा रही है। एक एक्ट बना हुआ है जिसके तहत 10-15 प्रतिशत जमीन ली जाती है लेकिन प्राथमिकता बंजर जमीन को दी जायेगी जिसमें कोई उपज नहीं होती है और उसका अधिग्रहण किया जायेगा। लेकिन आज जो चल रहा है, उसके तहत अगर कृषि लायक जमीन है या सिंचित जमीन है तो SEZ के लिये ली जा सकती है। हालांकि इस तरह के दिशा-निर्देश दिये गये हैं लेकिन फिर भी कृषि जमीन कम हो रही है। जब कृषि जमीन घट जायेगी तो राष्ट्रीय उत्पादन पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा।[s33] जो नेशनल प्रोडक्शन है, उस पर इसका असर पड़ेगा। यही कारण है कि आज देश में आयात करने की स्थिति आ गई है। हमारी जो आत्मनिर्भरता है, उसमें प्रभावित हो रही है। मैंने इसीलिए इसका जिक्र किया और अभी खास करके मैं कहना चाहता हूं कि अभी जब बाढ़ एवं सुखाड़ के मामले में मंत्री जी उदार होने लगे हैं, ऋण के मामले में उन्होंने कहा है, कर्ज माफी की बात कही थी और न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी किसानों को संकट से उबारने की बात की है। उसे सहूलियत देने की, वेलफेयर करने की बात सन् 2007-08 में 225 हजार करोड़ ऋण दिया जा रहा था। चालू वित्तीय वर्ष में उसमें 240 करोड़ लिखा हुआ है, वैसे 280 करोड़ का भी एक जगह मैंने देखा कि दो तरह का फीगर है, ऋण देने का जो प्रावधान किया गया है, लेकिन जो लिखित वित्त मंत्री जी का स्पीच है उसमें 240 करोड़ का ही जिक्र किया गया है। इस सरकार में दो वर्ष में कृषि ऋण दोगुना हो गया है। सन् 2008 तक इसके 240 या एक हजार करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, यह तय किया गया है। यह वित्त मंत्री जी ने यहां कहा है।

16.18 hrs.

(Dr. Laxminaryan Pandey *in the Chair*)

महोदय, इसमें मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृषि ऋण को मोटे तौर पर दो भागों बांटा गया है - प्रत्यक्ष वित्त और अप्रत्यक्ष वित्त। प्रत्यक्ष वित्त में जो फाइनेंस होगा, उसमें अल्प अवधि ऋण, दीर्घ अवधि के ऋण में किसानों को डायरेक्ट खाद, बीज, पम्पसेट इत्यादि दिए जाते हैं। लेकिन जो अप्रत्यक्ष ऋण है, उसकी क्या परिभाषा है? जब किसानों के लिए ऋण बढ़ाया जा रहा है, इससे किसे लाभ पहुंचेगा, क्या यह सभी बड़ी-बड़ी कम्पनियों को पहुंचाया जाएगा? इसमें जो खाद एवं बीज का व्यापार करने वाली कम्पनियां हैं या जो पशु चारा आपूर्ति करने वाले लोग हैं, किसे लाभ पहुंचाया जाएगा, जो मधुमक्खी का पालन करने वाले हैं, मछली पालन करने वाले या डेरी के धंधा से जुड़े व्यवसायी लोग हैं, उन्हें कृषि ऋण दिया जाएगा या किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए बिजली बोर्ड से जो बिजली मिलती है, क्या उसे भी दिया जाएगा? क्या वह कृषि ऋण के दायरे में आएगा, इसकी हम परिभाषा जानना चाहते हैं? माननीय वित्त मंत्री जी से इसका दायरा जानना चाहते हैं, क्या ये लोग भी इसी दायरे में हैं? जो प्रत्यक्ष वित्त, अप्रत्यक्ष फाइनेंस होगा, क्योंकि आप कर्ज बढ़ा रहे हैं, आप आगे लक्ष्य भी रखेंगे कि आगे और दें, किसानों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज देंगे तो किसानों का वेलफेयर होगा। मैं जानना चाहता हूं कि अब तो रिलायंस कम्पनी की सब्जी एवं फल की दुकान है और वे आलू और सब्जी भी बेच रहे हैं। मैं यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या इन्हें भी फाइनेंस किया जाएगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष फाइनेंस इन्हें किया जाएगा तो कितना प्रतिशत किसान को दिया जाएगा। जैसे इनकी अमेरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी मोनसेंटो है, बीटी कपास, बीज के एजेंट, बियर हिन्दुस्तान लीवर लि. कम्पनी, नमकीन बनाने वाला हल्दीराम तथा बिस्कुट बनाने वाली पारले कम्पनी, कलकत्ता में बैठे दार्जिलिंग के चाय बागान में जो धनी मालिक हैं, इन सब को मिलने वाला कर्ज भी क्या कृषि के दायरे में रखा जा रहा है? मंत्री जी अपनी स्पीच में ये सब बातें स्पष्ट करें। किसानों के हित में 60 हजार करोड़ का पैकेज हुआ है, कर्ज की राशि बढ़ाई गई है, यह आपने अच्छा कदम उठाया है। लेकिन ये जो चाय बागान के मालिक आदि के बारे में मैंने कहा है, क्या इन लोगों को भी मिलेगा, यह मैं जानना चाहता हूं? यह सही है कि वास्तविक किसानों को कर्ज देने की बजाए बड़े-बड़े उद्योगपतियों और बिचौलियों, दलालों तथा कम्पनियों आदि को ही और कर्ज दिया जाएगा। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किसानों को आप कितना ऋण दे रहे हैं?[rep34]

महोदय, उसका ब्रेक-अप हो जाना चाहिए कि कितना किसानों को दिया जाएगा, कितना मिडिल मैन लेंगे और प्राइवेट कंपनियों को किसानों के नाम पर, किसानों से संबंधित सामान को बनाने के लिए कितना दिया जाएगा, क्योंकि ऋण देने के लिए किसानों की समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो सकती है। इसलिए यह स्पट होना चाहिए। किसानों को खाद, उन्नत बीज, बेहतर और सस्ती सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर ही खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है। बिना ऐसी व्यवस्था किए, खेती कैसे लाभकारी हो सकती है? आज यदि कोई सबसे घाटे का व्यवसाय है, तो वह खेती है। प्राचीन काल में कहा जाता था कि "उत्तम खेती, मध्यम बान, निि◌ाद्ध चाकरी, भीख निदान।" आज खेती करना सबसे ज्यादा खराब काम हो गया है। आज सबसे घाटे का अगर कोई धंधा है, तो वह खेती है। इसे कैसे लाभकारी बनाया जाए। इस हेतु कदम उठाने के लिए जो आपने इनडायरैक्ट फायनेंस की व्यवस्था किसानों के लिए की है, उसमें से वास्तव में किसानों को कितने प्रतिशत मिलेगा और यह भी स्पट होना चाहिए कि जो ऋण बढ़ेगा, उसमें से कितना किसानों को मिलेगा? इसमें से प्राइवेट कंपनियों और बहुराट्रीय कंपनियों को कितना मिल रहा है, इसका ब्रेक-अप आना चाहिए।

सभापति महोदय, किसानों की हालत सुधारने के लिए जहां तक समर्थन मूल्य का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि प्रैक्टीकल स्थिति यह है कि मंडी स्ट्रक्चर के अभाव में समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। अभी हमने रु. 1000/- एक हजार प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य तय किया है। यह अच्छी बात है, लेकिन यह मिलेगा कैसे? इसको देने के लिए कोई मैटर्कानिज्म नहीं है। एफ.सी.आई. का ऐसा कोई ट्रक विलेज मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने नहीं जाता है, जो उसे डायरैक्ट भुगतान कर दे। आज सपोर्ट प्राइस मिलना ही कठिन टास्क हो गया है। समर्थन मूल्य की घोषणा करना एक बात है और उसे किसानों को दिलाना दूसरी बात है और यह कठिन है। आज स्थिति यह है कि किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता है और उन्हें अपनी कृषि उपज तुरन्त डिस्ट्रैस सेल पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि भी जगह मंडी स्ट्रक्चर नहीं है। पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य प्रदेशों में मंडी स्ट्रक्चर है। वहां समर्थन मूल्य मिल जाता है। अनेक ऐसे राज्य हैं जहां प्रक्योरमेंट का कल्चर पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। इसलिए वहां डायरैक्ट कैसे समर्थन मूल्य मिले, इसकी व्यवस्था करें। जैसे यहां से समर्थन मूल्य की घोषणा होती है वैसे ही वह समर्थन मूल्य किसानों को डायरैक्टड मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए, ताकि किसान की जेब में पैसा आए और उसे वह अपने रोजमर्रा के काम में लगा सके। उससे उसकी आर्थिक उन्नति हो सकती है। देश के अनेक राज्यों के किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह प्रैक्टीकल स्थिति है। इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया।

सभापति महोदय, जहां तक लाभकारी मूल्य देने की बात है, मैं बताना चाहता हूं कि खेती की लागत आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जितने में कृषि उपज बिकती है, उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। किसानों की ब्याज दर 7 प्रतिशत की गई है, यह अच्छी बात है। प्रो. राम गोपाल यादव ने भी ठीक कहा था, हम भी यह मांग करते हैं जैसी कि नैशनल एग्रीकल्चर कमीशन के चेयरमैन, श्री एस. स्वामीनाथन की भी रिपोर्ट आई है कि किसानों के लिए इंटरैस्ट की दर 4 प्रतिशत रखनी चाहिए। किसानों को सहूलियत देने हेतु ऋण की ब्याज दर जो वर्तमान में 7 प्रतिशत करने के लिए कहा गया है, वह 7 प्रतिशत की बजाय 4 प्रतिशत होनी चाहिए। किसानों को ऋण लेने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसानों को ऋण लेने में बहुत जटिलता है। किसानों को ऋण देने की जो प्रक्रिया है, वह बहुत जटिल बना दी गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसे 4 प्रतिशत करने पर सरकार को विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, देश के पिछड़े राज्यों को धन देने के लिए योजना आयोग और वित्त मंत्री द्वारा मिलकर जब प्लान बनाया जाता है, जैसा इस बजट में बैकवर्ड रीजन को पैसा देने की बात की गई है और पैसा देने का प्रावधान किया गया है, पिछड़े राज्यों को प्लान का पैसा किस आधार पर दिया जाता है, वह मैं बताना चाहता हूं। उस राज्य को प्लान का जो पैसा दिया जाता है, वह उसके इंटरनल रिसोर्सेस के मोबिलाइजेशन के आधार पर दिया जाता है। जो राज्य अपने इंटरनल रिसोर्सेस का जितना अधिक मोबिलाइजेशन करेगा, उसे उतना अधिक प्लान का पैसा दिया जाएगा। इंटरनल रिसोर्सेस का मोबिलाइजेशन ही उस राज्य को प्लान का पैसा देने का मापदंड होता है और उसी मानदंड के आधार पर वित्त मंत्री और योजना आयोग द्वारा प्लान का पैसा उस राज्य को देना तय किया जाता है। जो फायनेंस कमीशन है या जो गाडगिल फार्मूला है, उनमें भी इस प्रकार की गाइड लाइन है कि जो राज्य अपने इंटरनल रिसोर्सेस कंसर्न को जितना अधिक मोबिलाइजेशन करेगा, उसे उतना अधिक प्लान का पैसा दिया जाएगा। प्लान का बजट देने के लिए उस राज्य के आन्तरिक संसाधनों के मोबिलाइजेशन का आधार बनाया जाएगा। यह एक बुनियादी सवाल है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन, उस स्टेट की गरीबी, उस स्टेट की नीड्स और उस स्टेट की स्थिति को देखते हुए उन्हें प्लान का पैसा दिया जाए। उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जब उसे देखकर प्लान का बजट तय किया जाएगा, तब पिछड़े राज्य मुख्य धारा में आ सकते हैं, वरना पिछड़ा राज्य हर बार पिछड़ता रहेगा, चाहे जितना बजट दिया जाए। पिछड़े राज्यों में चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, जो पिछड़ा राज्य है, वह और पिछड़ता जाएगा क्योंकि उन राज्यों के सी.डी. (क्रेडिट एंड डिपॉजिट) रेश्यों की स्थिति में बहुत अन्तर है।

उनकी आर्थिक स्थिति को देख कर यदि कारगर प्लान बने, तभी पिछड़े राज्य मुख्य धारा में आ सकते हैं, नहीं तो जितने बजट प्रस्तुत हो जाएं, पिछड़े राज्य पिछड़े ही रहेंगे। चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, जो पिछड़े राज्य हैं, वे और पिछड़ते चले जाएंगे। आज बिहार में मात्र 15 प्रतिशत सीडी रेशो है, छोटे किसान, मझौले किसान, मजदूरों का पैसा बड़े-बड़े शहरों में खर्च होता है। सीडी रेशो का यह हाल है। कैसे विकास होगा, क्योंकि कहा जाता है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 15 प्रतिशत कंसर्निंग स्टेट में खर्च होता है, जबकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि 40 प्रतिशत कंसर्निंग स्टेट में खर्च होना चाहिए, खास कर एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्या कभी इस बारे में मोनिटरिंग की गई है? इसकी मोनिटरिंग करके देखी जाए, 15 प्रतिशत से ज्यादा सीडी रेशो का पैसा उस बैकवर्ड स्टेट में खर्च नहीं होता है। प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाए गए प्लान तभी कारगर बनते हैं, वह इस तरह से होता है कि उस राज्य में कितने इंटरनल रिसोर्सिज वह राज्य मोबलाइज कर सकता है। हमारे पूरे उत्तर बिहार में पानी है, बाढ़ है, नदियों का जाल है, वहां कैसे इंटरनल रिसोर्सिज़ मोबलाइज हो सकते हैं। वहां बालू है, बालू में क्या पैदा हो सकता है? झारखंड के अलग हो जाने के कारण रायल्टी, खनिज पदार्थ आदि दो भागों में बंट गए। इस कारण बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। जो फाइनेंशियल मेमोरैंडम दिया था, आज तक विशेष पैकेज नहीं दिया गया है। थोड़े बहुत पैसे राष्ट्रीय श्रम विकास के जरिए जरूर दिए गए हैं, बैकवर्ड रीज़न के जरिए बिहार को पैसे मिले हैं, लेकिन स्पेशल पैकेज बिहार को संतुलन में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, दिया जाना चाहिए, वह नहीं मिला। फाइनेंशियल मेमोरैंडम के लिए उसी समय प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी कि पूरी तरह से देखें कि कैसे आर्थिक दशा सुधारी जाए, लेकिन हमारा कहना है कि पिछड़े राज्यों की गरीबी, आबादी और जरूरत के हिसाब से कारगर प्लान बनाना चाहिए। On the basis of needs, poverty and population के आधार पर प्लान बनना चाहिए। मेरा निवेदन यही है कि बेसिक गाडगिल फार्मूला या फाइनेंस आयोग या जो भी दिशा निदेश हैं, जिनके आधार पर आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है, तब जा कर पिछड़े राज्य राष्ट्र की मुख्य धारा में आ सकेंगे, नहीं तो पिछड़ा राज्य और ज्यादा पिछड़ता रहेगा, वह आगे नहीं बढ़ सकता है। संगठित क्षेत्र के लिए माननीय मंत्री जी ने अच्छी घोषणाएं की हैं, 30 हजार करोड़ रुपए संगठित क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, उन्हें टोकन मनी दी जा रही है।...(<u>व्यवधान</u>)

सभापति महोदय : आपके दल के और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आपको बोलते हुए 25 मिनट हो गए हैं, अब आप स्वयं देख लीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं दो-तीन मिनट में कन्कलूड कर दूंगा। यदि आपका, चेयर का आदेश होगा तो मैं अभी बैठ जाऊंगा।...(<u>व्यवधान</u>)

सभापति महोदय : ऐसी बात नहीं है, मैं कहना चाहता था कि आप उनके लिए समय छोड़ेंगे या नहीं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उनके लिए भी समय जरूर छोड़ेंगे।

महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि असंगठित क्षेत्र के लिए सरकार ने आश्वासन दिया था और विधेयक के बारे में भी कहा गया था। उस विधेयक को जल्दी लाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र में बीड़ी मजदूर, खेतिहर मजदूर, कन्स्ट्रक्शन लेबर, रिक्शा और तांगा वाले गरीब लोगों के कल्याण के लिए, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए विधेयक को तुरन्त सदन में लाना चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य का, उनके बच्चों की शिक्षा का ख्याल हो सके। पूरे देश में 93 प्रतिशत वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र के हाथ में है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी यह कहा गया है कि इन लोगों का कल्याण किया जाएगा। चार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। यह सही है कि इसकी एक प्रक्रिया है और सरकार ने इस संबंध में पहल भी की है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसी सत्र में इस बिल को आना चाहिए।

महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग को कितना पैसा दिया गया है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि समय कम है। ओबीसी की 52 फीसदी आबादी है और सबसे कम एलॉटमेंट पिछड़ा वर्ग आयोग को किया गया है। पिछड़े वर्ग के विकास के लिए सबसे कम राशि रखी गई है, जबकि उनकी आबादी इस देश में 52 फीसदी [r35]है।

जहां तक बेरोजगारी का मामला है, खुदरा व्यापार में भी बड़ी-बड़ी कम्पनियां आ रही हैं, इनकी कहीं तो सीमा होनी चाहिए। क्या कारण है कि पिछले साल अनाज सैण्ट्रल पूल में भी इकट्ठा नहीं हो पाया, जितना अनाज सैण्ट्रल पूल में रहना चाहिए, उतना प्राप्त नहीं हो पाया। खुदरा, रिटेल व्यापार में मैगामार्ट जैसा अहमदाबाद, गुजरात में खुला है, उसमें 33 हजार आइटम्स, प्याज, आलू आदि सब एक साथ बिकते हैं। गरीब लोग जो खुदरा व्यापार में थे, वे इससे बेरोजगार हो रहे हैं और तेजी से हजारों गरीब आदमी, छोटे-छोटे लोग जो प्याज बेचते थे, आलू बेचते थे, उनको भी उनके रोजगार से बेदखल किया जा रहा है। गरीबी इसलिए है, क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगारी ही गरीबी का कारण है तो पावर्टी एलीविएशन कैसे होगा? जब तक उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, गरीब लोगों की जेब में पैसा नहीं आयेगा, तब तक उनकी गरीबी दूर नहीं होगी। क्रय-शक्ति बढ़ने से ही माना जायेगा कि वे मुख्य धारा में आ रहे हैं। मैं समाज के अन्तिम आदमी के लिए लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि क्रय-शक्ति बढ़ायें, उसको रोजगार ज्यादा मिले, उसकी बेरोजगारी दूर हो, तभी गरीबी उन्मूलन हो सकता है। गरीबी उन्मूलन का इंडीकेटर केवल यही है कि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ी है? जब तक उसकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकती। गरीबी इसीलिए है, क्योंकि बेरोजगारी है, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मेरा लास्ट पाइंट्स यही है कि स्थाई समाधान बाढ़ और सुखाड़ का होना चाहिए। किसान के लिए हर साल हम 10 हजार करोड़ रुपये, 15 हजार करोड़ रुपये रिलीफ बांटने पर खर्च करते हैं, लेकिन इससे उसका स्थाई समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी भारत नेपाल का एक समझौता हुआ था कि हाई लेवल डैम बनायें, क्योंकि हाइड्रो इलैक्ट्रिक उससे सस्ती दर पर मिलेगी। हाई लेवल डैम बनाने से हाइड्रो इलैक्ट्रिक भी

हमको उपलब्ध होगी और बाढ़, सुखाड़ का स्थाई समाधान भी होगा, पानी से निजात भी मिलेगी और जो फसल हजारों एकड़ में, लाखों एकड़ में हर साल बर्बाद हो जाती है, उसका भी बचाव होगा, इसलिए बाढ़ सुखाड़ के स्थाई समाधान के जो भी ऑन गोइंग प्रोजैक्ट्स हैं या हाइड्रो इलैक्ट्रिक पैदा करने के जो भी प्रोजैक्ट्स हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकार को उन पर विशेष बल देना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI D. VITTAL RAO (MAHABUBNAGAR): Speaker Sir, I rise in support of the Union Budget 2008-09 presented by Hon'ble Finance Minister, and I thank the UPA Government headed our Hon'ble Prime Minister, Dr. Manmohan Singh ji under the Leadership of Hon'ble Chairperson of UPA, Madam Sonia Gandhi ji for the dream budget.

While congratulating the Finance Minister on waiving of loans of farmers, I take this opportunity to discuss a very important issue pertaining to the Handloom sector in the country.

Handloom is an ancient industry in India. The features of this sector vary across the country. In Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Assam and Orrisa, it has attained the status of a matured industry, and in the other parts, it is still an enterprise confined to the needs of the households.

Handloom sector occupies a place second only to agriculture in providing livelihood to the people. However, the sector is beset with manifold problems such as obsolete technologies, unorganized production system, low productivity, inadequate working capital, conventional product range, weak marketing links, overall stagnation of production and sales and above all, competition from power loom and mill sector. As a result of effective government intervention through financial assistance and implementation of various welfare activities, the handloom sector, to some extent has been able to tide over these disadvantages.

WEAVER & RURAL ARTISANS:

Apart from the farming activity, the rural economy also consists of Handloom, Weaving, carpentry, blacksmiths, pottery, fishing and many other inherited occupations. Above all, it is necessary to mention that more than 2 crores families depend on weaving in our country.

---

* Speech was laid on the Table.

LOAN FACILITY TO WEAVERS AND ARTISAN

In the country more than 2 crores weaver's families depend on weaving. There is no other source accept to take the loan from the nationalized banks and Cooperative Banks to carry out their livelihood. 1412 societies are functioning in Andhra Pradesh, Out of these societies, 300 societies have since been closed due to non-payment of loans plus interest accrued thereon taken from Government Banks and Private Banks. Therefore, at present only 1090 societies are in existence in Andhra Pradesh. Only 249 societies are getting loans from District Cooperative Banks against the Cash credit facility. Thus 20% societies are reaping the Budget allocations of 150 crores fund allotted to Andhra Pradesh during the last four years. The Finance Minister has, in Budget 2008-2009, allocated 6000 crores loan for the whole country, out of which only 200 crores loans have been allocated for A.P.

It is pity to say that no financial support is available to individual weavers, artisans and other small families engaged in this field to earn their livelihood. I, therefore, feel that the same financial support like providing credit card, loan from the Government and Cooperative Banks may be extended to every individual engaged in this sector.

Lack of information to weavers regarding various policies and schemes is no less a significant cause for the dwindling fortunes to the weaving community. Even government departments and implementing agencies related to handloom suffer from inadequate information and data resulting in a widening gap between policy formulation and implementation.

COMMITTING SUICIDE IN ANDHRA PRADESH

In Andhra Pradesh alone, there are about 3,20,000 handlooms. About 5,00,000 families directly and 20,00,000 families indirectly are dependent on them. It is unfortunate that in the recent past, several weavers have committed suicide because the distress has become unbearable. Suicidal deaths are clear sign and outcome of crises in the handloom sector. The other major sign is dramatic decline of number of handlooms in the State.

The management of the Cooperatives is not left to the cooperatives themselves but there are many Government rules and regulations related to credit provision, wages and margins etc. The handloom cooperative system is riddled with corruption and political interference. Many handloom weavers are not members of these cooperatives. The Government department has to stop using them as primary source of routing government funds and schemes. Cooperatives have to become independent at district level in terms of management and decision-making.

The UPA government is committed for creating socio-economic balance among rural - urban societies. While appreciating waiving loans of the farmers, I appeal that the weaving sector, the second largest employment providing sector, may also be brought under the same umbrella. I, therefore, earnestly request the Hon'ble Prime Minister to waive off the loans of the weaving sector as have been done in the case of the agriculture sector.

Thank you Speaker Sir for providing me the opportunity to speak in the House.

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद): सभापति महोदय, 29 फरवरी को जो देश का आम बजट पेश किया गया है, उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। जैसे किसानों की कर्जा माफी, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों के बावजूद मैं उसका समर्थन करता हूं कि किसानों की 60 हजार करोड़ रुपये की कर्ज माफी होगी।

वित्त मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि बहस के नतीजे में जो त्रुटियां समाने आयें, उनमें सुधार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब किसानों को फायदा पहुंच सके। इन्कम टैक्स का स्लैब इन्होंने बढ़ाया है, वह भी स्वागत योग्य कदम है, मैं उसका समर्थन करता हूं, इसलिए कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि डेढ़ लाख रुपये तक इन्होंने उसे पहुंचाया है। डेढ़ लाख रुपये में आदमी का खर्च ही पूरा नहीं होता, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। कुछ जरूरी चीजों पर ड्यूटी इन्होंने घटाई है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। सीमेण्ट, लोहा और बहुत सारी जरूरी चीजों को जो महंगा किया गया है, उसका मैं विरोध भी करता हूं। कर्जा माफी का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन यह भी बताता हूं कि बार-बार कर्ज माफी इस समस्या का कोई मुस्तकिल हल नहीं है। आस्ट्रेलिया के किसानों को भारत सरकार ने उनकी उपज का जितना दाम दिया है, अगर उतना ही दाम अपने किसानों को भारत सरकार देने पर तैयार हो जाये तो आस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाने की जरूरत आज भी नहीं पड़ेगी। अगर किसानों को इन्श्योर्ड करने पर कुछ पैसा खर्च कर दिया जाये तो न तो किसानों की खुदकुशी होगी और न बार-बार उनका कर्ज माफ करना पड़ेगा।[R36] महंगाई चार साल में नाकाबिले बरदाश्त हद तक बढ़ चुकी है, जो बरदाश्त के बिल्कुल बाहर है। मेरा ख्याल है कि इस बजट के बाद महंगाई और बढ़ेगी।

महोदय, मैं महंगाई की सिर्फ एक मिसाल दूंगा। ग्यारहवीं लोकसभा में मैं सदस्य था, तब चिदंबरम साहब ही वित्त मंत्री थी। उस वक्त एक करोड़ रूपए सांसद निधि मिलती थी। कुल डेढ़ साल वह लोकसभा रही। मुझे जो डेढ़ करोड़ रूपए मिले थे, उससे मैंने सत्तर काम कराये थे। वर्ष 2004 से अब तक मान लीजिए कि वर्ष 2009 में चुनाव होते हैं, तो पांच साल में दस करोड़ रूपए मिलेंगे, लेकिन दस करोड़ में सत्तर काम पूरे होंगे या नहीं, इसके बारे में मुझे पूरा विश्वास नहीं है। इसका मतलब यह है कि डेढ़ करोड़ रूपए में जो काम वर्ष 1996-97 में होता था, वह काम अब दस करोड़ रूपए में भी नहीं हो रहा है। आज यह महंगाई का हाल है।

महोदय, मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा कि भ्रष्टाचार के मामले में यूपीए पूरी तरह संवेदनहीन है। मैं यूपीए को क्यों कहूं, मैं तो कहता हूं कि हम सब संवेदनहीन हैं। चार साल हो गए, इस चौदहवीं लोकसभा को आए हुए, भ्रष्टाचार पर बहस के लिए जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको आतंकवाद से भी बड़ी समस्या मैं मानता हूं, उस पर बहस के लिए दो मिनट भी कभी इस चौदहवीं लोकसभा में नहीं दिया गया। यह एक अलग मुद्दा है। जितना पैसा आप खर्च करते हैं, आप सीना तानकर कहते हैं कि हमने इतना पैसा पीएमजीएसवाई को बढ़ा दिया और इतना दूसरी किसी योजना को बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ाने से फायदा क्या है, वह पैसा कहां जा रहा है, क्या वह हकदारों तक पहुंच रहा है? इसके बारे में कहने के लिए मैं चंद मिनट लूंगा।

महोदय, जीडीपी और सेंसेक्स का इतना नाम हमारे वित्तमंत्री जी लेते हैं कि बाहर लोग इनको जीडीपी और सेंसेक्स मंत्री ही ज्यादा कहते हैं और वित्त मंत्री कम कहते हैं, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? भ्रष्टाचार का हाल क्या है? सेंसेक्स जिस तेज रफ्तार से बढ़ा था, भ्रष्टाचार के बढ़ने की रफ्तार उससे भी ज्यादा तेज रही थी। इस वक्त सेंसेक्स गिर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उसके गिरने के संबंध में कोई प्रावधान के बारे में हम सोच रहे हैं, जबकि हम भ्रष्टाचार के बारे में बातें ही नहीं कर रहे हैं, न बजट में, न बहस में। जब हम भ्रष्टाचार की बातें ही नहीं कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा।

रोजगार गारंटी योजना की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री जी मुझे माफ करेंगे कि पूरी यूपीए सरकार रोजगार गारंटी योजना की तारीफ करने में लगी हुयी है और उसका नाम ही पड़ गया है - भ्रष्टाचार गारंटी योजना। ये तो सीना तानकर कहते हैं कि हमने पंचायतों के थ्रू इसे किया है। पंचायतों के थ्रू जो धन जा रहा है, उसमें तो राजीव गांधी वाला 15 प्रतिशत वाला हिसाब नहीं है, राहुल वाला हिसाब आ गया है कि केवल 5 प्रतिशत पहुंच रहा है और 95 प्रतिशत नहीं पहुंच रहा है।

*(Interruptions) *â€¦*

MR. CHAIRMAN : Interruptions would not be recorded. Shri Azmi, please address the Chair.

श्री इलियास आज़मी : राजीव गांधी जी ने कहा था कि 15 प्रतिशत पहुंच रहा है, उनका कहना है कि पांच प्रतिशत पहुंच रहा है। मैं यह नहीं मानता कि 5 प्रतिशत ही पहुंच रहा है, उतना नहीं है। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं कांग्रेस की बात कहां कह रहा हूं? मैं तो फैले हुए भ्रष्टाचार की बात कह रहा हूं। मैं भ्रष्टाचार के विरोध में बोल रहा हूं और ये कांग्रेस ...(व्यवधान)

* Not recorded

MR. CHAIRMAN : Shri Azmi, please address the Chair.

श्री इलियास आज़मी : महोदय, जितनी भी ग्राम विकास की योजनाएं हैं, उनको जितना पैसा जा रहा है, उसकी हालत बहुत खराब है। खासतौर से पंचायतों के थ्रू खर्च होने का जो रूझान बढ़ा है और हमारे मंत्री जी पार्लियामेंट में सीना तानकर कहते हैं कि हम इसे पंचायतों के थ्रू कर रहे हैं, यानि हम बहुत सही कर रहे हैं। उसमें तो पैसा बिल्कुल ही डूब रहा है। कितनी ही योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं लगता कि ग्राम विकास की चौदह-पंद्रह योजनाएं हैं। आधी योजनाओं के बारे में जनता जानती तक नहीं कि इस योजना में भी जिले में दस-पांच करोड़ रूपए आए हैं और पूरा का पूरा पैसा खत्म होता जा रहा है। पीएमजीएसवाई एक अच्छी योजना थी और मैंने बार-बार पीएमजीएसवाई योजना का बखान किया है। वित्तमंत्री जी बैठे हैं, मैं बता दूं कि मेरे क्षेत्र में वर्ष 2004 का जो पैकेज था, उसमें 32 सड़कें थीं और उन 32 सड़कों में से आज तक एक सड़क भी नहीं बन सकी। [p37]आप लाख सीना तानकर कहें, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर पैसा गया कहां? वे सड़कें क्यों नहीं बनीं? मैं यह नहीं कहता कि इनका कोई कसूर है। काम करने के लिए एस्टीमेट बना, वह पास हुआ।...(व्यवधान) सन् 2004 से लगातार आपकी सरकार है।...(व्यवधान) मेरी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Shri Azmi ji, I heard you say that 32 roads were to be constructed, but not a single road was constructed. Who was in the State Government? Who was responsible for constructing the roads? Who was the Minister in-charge of the State Government in respect of roads? Please tell us that also.

श्री इलियास आज़मी : वह कार्य क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में वहां के अधिकारियों ने बताया कि एस्टीमेट बना। जिस दिन वह केन्द्र सरकार से सैंक्शन हुआ, उसके बाद रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और कोई उतने पैसे पर वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम लिखते रहे कि हमें रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाने का आदेश दिया जाए। रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाने का आदेश डेढ़ साल के बाद आया। तब तक रेट्स और ज्यादा बढ़ गए। नतीजा यह हुआ कि सन् 2004 में जो कार्य सैंक्शन हुआ था, वह आज तक नहीं हो पाया। यह पीएमजीएसवाई का हाल है।

ग्राम विकास की छोटी योजनाओं के बारे में मैं पहले कह चुका हूं कि उनका पता ही नहीं लगता। मैं हरदोई जिले की सतर्कता निगरानी समिति का चेयरमैन हूं। आप जिस योजना के लिए, जिस जिले में जितना पैसा देते हैं, यदि आप उसके बारे में वहां के विधायकों और सांसदों को लिखकर बता दें कि इस योजना के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है, तो वह थोड़ी-बहुत जानकारी रखेगा। विधायकों और सांसदों को भी पता नहीं लगता कि किस योजना के लिए कितना पैसा आया है। पूरा पैसा खा लिया जाता है, लोग पूरी सड़कें खा जाते हैं, पूरी योजना खा जाते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। उसके बारे में सिर्फ कलैक्टर जानता है, अधिकारी जानते हैं और सरकार जो पैसा देती है, वह जानती है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बड़ी शान के साथ लागू हुई। वह बहुत अच्छी योजना थी। मैं उसका पूरा समर्थन करता था और आज भी करता हूं। यह कहा गया कि हम पांच साल में पूरे देश का विद्युतीकरण कर देंगे। वह कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। अभी राजस्व गावों का हुआ है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र, अपने जिले और अपने पास-पड़ोस के बारे में कह सकता हूं कि जिन गांवों का विद्युतीकरण हुआ, खम्बे गाढ़े गए, तार[N38] खींचे गए, उनमें कनैक्शन देने से पहले तार भी उतर गए, खम्बे भी नीचे चले गए। अगर मेरे क्षेत्र के एक गांव के बारे में बता दिया जाए कि वहां बल्ब जला है, तो मैं जुर्माना भुगतने के लिए तैयार हूं।...(व्यवधान)

भ्रष्टाचार की बात हो रही थी। बैंकों का भ्रष्टाचार नाकाबिले बरदास्त होता जा रहा है। थानों से ज्यादा बदतर पोजीशन हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों की हो चुकी है। यदि किसी गरीब व्यक्ति का पचास हजार रुपये का कर्ज मंजूर भी हो जाता है, तो जब तक वह दस हजार रुपये बैंक मैनेजर और बैंक के स्टाफ को न खिलाए, उसे पैसा नहीं मिलता। जब वह पैसा जमा करता है, उसमें भी गड़बड़ी होती है। आप बैंकों का भ्रष्टाचार रोकिए। वित्त मंत्री जी, आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मेरा मकसद आपकी तौहीन करना नहीं है। आपका तरीका डेमोक्रेसी के राजनेता से ज्यादा ब्यूरोक्रेट का तरीका है। आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करते।[N39]

मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मेरे यहां एक कस्बा है, बड़ा शहर है--पाली। पाली में कोई राष्ट्रीय बैंक नहीं है। वह बहुत बड़ा बिजनेस का सैंटर है। उसके अगल-बगल के दो-तीन किलोमीटर में कई राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। वहां बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक है। मैंने कई बार आपको लिखा कि पाली में राष्ट्रीय बैंक की जरूरत है। उसके आस-पास 4-5 किलोमीटर के एरिया में जो गांव हैं, वहां बैंक हैं लेकिन पाली में कोई बैंक नहीं है। हर बार आपके अधिकारी हमें लिखकर भेज देते हैं कि पाली से तीन किलोमीटर दूर बाबरपुर में बैंक है। पाली से चार किलोमीटर दूर निजामपुर में बैंक है। पाली से पांच किलोमीटर दूर रूपापुर में बैंक है। आपने वही जवाब मुझे दे दिया है। मैंने आपसे कहा कि मैं ज्यादा जानता हूं क्योंकि वह मेरा क्षेत्र है और मैं गली-गली दौड़ता हूं। आपका एयरकंडीशन में रहने वाला एक अधिकारी मुझसे ज्यादा नहीं जानता। मैं आपको कह रहा हूं कि आप पाली में बैंक खोलिये। अगर वह बैंक घाटे में चला गया, तो आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लीजिए। वह बैंक नफे में चलेगा, लेकिन अधिकारी कहता है कि तीन और पांच किलोमीटर दूर बैंक है। मैं कहता हूं कि आप छोटे-छोटे हर गांव में बैंक खोल दीजिए। इतने बड़े बिजनेस सैंटर में, कस्बे में आप बैंक नहीं खोलते। मैं कह रहा हूं कि आपका जो व्यवहार है, वह ब्यूरोक्रेटिक है, राजनीतिक नहीं है। आप उसे थोड़ा सा बदल दीजिए, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप अपना भाषण समाप्त करिये।

â€¦(व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी : अभी मेरे से पहले वाले वक्ता 35 मिनट बोले हैं। इसलिए आप मुझे कम से कम 20 मिनट तो बोलने का समय दीजिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के हिसाब से जो समय है, उस हिसाब से मैंने आपको टाइम दिया है।

â€¦(व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी : आपने दूसरी पार्टियों को समय दिया है इसलिए मेरी पार्टी को भी बोलने का समय दीजिए।

सभापति महोदय : दूसरी पार्टियों का जितना समय था, उतना उनको दिया है। आपकी पार्टी का जितना समय था, वह मैंने आपको दिया है।

â€¦(व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी : मिड डे मील, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और पंचायतों के जरिये विकास, कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनको पूरी तरह समाप्त करने की जरूरत है क्योंकि उनमें पूरा भ्रष्टाचार फैल रहा है। प्रधान मंत्री ने बजट से पहले कहा था कि बजट में पहला हक मुसलमानों का है। मैं मानता हूं कि प्रधान मंत्री जी यह कहकर मुसलमानों को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन इनको एक हथियार दे दिया। शायद यह मकसद हो कि वे कांग्रेस और प्रधान मंत्री को गाली दें कि प्रधान मंत्री जी सब कुछ मुसलमानों को दिये दे रहे हैं और मुसलमान बेवकूफ बन जायें कि हां, यूपीए हमें बहुत ज्यादा दे रही है और वे कांग्रेस की तरफ घूम जायें। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था क्योंकि बजट में यह नहीं बताया गया कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या किया गया? ...(व्यवधान) कुछ भी नहीं दिया गया। सच्चर कमेटी के बाद ...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): आजमी जी, जितना पैसा माइनोरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ने दिया है, वह सारा खर्चा बीजेपी स्टेट ने किया है। ...(व्यवधान) गुजरात में पूरा खर्चा किया गया है। मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आप देख लीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Kharabela Swain, do not interrupt him.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: It will not go on record.

(Interruptions) â€¦*

श्री इलियास आज़मी : आप मुझे क्यों सुना रहे हो? सच्चर कमेटी की सिफारिशों को टालने के लिए फातमी कमेटी बनायी गयी। फातमी कमेटी ने सिफारिश की कि 93 जिलों में, जहां मुसलमानों की आबादी 20 परसेंट से ज्यादा है, वहां शिक्षा पर विशेष खर्च किया जाये। लेकिन 93 जिलों की जगह इस साल आपने 19 जिलों में खर्च किया है। इसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि इसमें मेरा जिला भी शामिल है। जो गाइडलाइन वहां गयी है, उसमें सबकी राय है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही पैसा खर्च हो। लेकिन उसमें दस ऐसी चीजें शामिल कर दी गयी हैं जिससे वह सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला जायेगा। मैं कहूंगा कि आप माइनोरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को मशविरा दें कि माइनोरिटी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो पैसा जा रहा है, उसे केवल शिक्षा पर खर्च करें। वह सिर्फ मुसलमानों की शिक्षा पर खर्च नहीं होगा बल्कि सबकी शिक्षा पर खर्च होगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करिये।

â€¦(व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी : मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सारे मुस्लिम मैम्बरान ऑफ पार्लियामैंट ने मिलकर डिमांड की थी कि माइनोरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनायी जाये। मैं स्वागत करता हूं कि आपने हमारी डिमांड मानी। अगर आप मुस्लिम मैम्बरान ऑफ पार्लियामैंट से वोट लेने के लिए कहेंगे तो वह कहेंगे माइनोरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बंद कर दी जाये, तो ठीक है क्योंकि माइनोरिटी अफेयर मिनिस्ट्री वहां सिर्फ अपने लोगों को बैठाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। मौलाना आजाद फाउंडेशन के बारे में, मैंने इसी पार्लियामैंट में कहा कि वेल्फेयर के जितने दायरे हैं, सबसे बेहतर काम मौलाना आजाद फाउंडेशन कर रहा है। मैंने यह सर्टीफिकेट इसी पार्लियामैंट में दिया है। आज मैं कह रहा हूं कि हर जगह मुसलमानों से मुताल्लिक माइनोरिटी मिनिस्ट्री में ऐसे आदमी को बैठा दिया गया है कि सारे सहारे चौपट हो रहे हैं।

* Not recorded

आज मौलाना आजाद फाउंडेशन जैसा पुरस्कार इदारा बर्बाद हो रहा है। मैं उसके लिए क्या कह सकता हूं? मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि नीयत नहीं है।[MSOffice40] सच्चर कमेटी के बाद उसकी सिफारिशों पर अमल करने के लिए रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनाई गयी। शायद नीयत यह रही हो कि रंगनाथ मिश्रा जी, सच्चर कमेटी ने जो कुछ किया है, उसको पोंछ दें। लेकिन लगता है कि मिश्रा कमेटी ने कोई अच्छी रिपोर्ट दे दी है, इसीलिए सरकार उसे दबाकर बैठी है, पार्लियामेंट में नहीं ला रही हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट अच्छी नहीं होती, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को धाने वाली होती तो अब तक उसे पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया होता। सरकार की नीयत सही है। अगर सरकार अकलियतों की हमदर्द है, अगर आप मल्होत्रा जी को मौका देते हैं हमें गाली देने के लिए, तो रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट को सदन में क्यों प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। आप उसे सदन में लाइए और उस पर अमल कीजिए।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री इलियास आज़मी : महोदय, जिस तरह से श्रीकृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की नीयत नहीं थी, उसी तरह लगता है कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को भी सरकार लागू नहीं करना चाहती है। श्रीकृष्णा कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत तो कर दिया, लेकिन उसे आज तक लागू नहीं होने दिया। महाराट्र में पिछले दस साल से आपकी सरकार है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट संसद के इसी सत्र में प्रस्तुत की जाए और उस पर अमल किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Chairman, Sir, in a very hesitating manner I wish to support this Budget because the media and everybody has bashed this Budget as being an 'Election Budget'. But my understanding, as far as it goes,

is that I am convinced that any Budget that helps the common man, obviously the voter, is the success of the Government or of the governance system. So even though I sit in the Opposition Benches, a move that supports the farmers, the neediest of the needy in this country, is to be welcomed by all. But it is another matter that in the Supplementary Budget of 2007-08, a meagre amount of Rs. 100 crore has been marked to be included in this scheme and the rumours go that when actually the scheme will be worked out, 3 per cent will be borne by the Central Government, 30 per cent will be borne by financial institutions but the major chunk of 40 per cent – this is the suspicion, the hon. Finance Minister can clarify – will be dumped on the States' shoulders with the hope that the States will meet this amount. As we all know, this will never happen and the pity is that although it is a welcome step, but this step should have been followed by the Finance Minister and this UPA Government not only in the fifth year, it should have been done in the past four years too.

Sir, as we all know, Machiavelli used to say that you can do whatever wrong you want in the beginning, but just before you kick the bucket if you do something good, people will remember that you were a good man. But Machiavelli, unfortunately, lived and walked on this earth many centuries ago and in the beginning of the 21st Century, the young common India is very aware. [r41]People do not forget, people remember the mindset of those who govern. When a Prime Minister uses the words 'Congress Regime, NDA Regime', the message goes clearly to the people that that old mindset of a regime still persists in this Government. Where does the word 'regime' come from? It comes from regiment, regimentation, regimen -- a military word or at best a bureaucratic word. It is also a colonial word.

Although, supporting this Budget, which is intended to help the farmers, when we see the sheer figures of Rs.60,000 crore to be divided by four crore farmers, it is a meagre Rs.15,000 per head. When banks are asked to invest 18 per cent on the farming sector, the best performance in my State of Orissa has been 11 per cent, banks are unwilling to invest with farmers. So, your institutional financing is so low that you will not really reach out to the needy.

But come what may, even the newspapers say that this will touch only 22 per cent of the farmers. We must all welcome it because even if it is 22 per cent and *alas* if this Government would have done it in the last four years also, then it would have reached 100 plus per cent of the needy farmers by now. But in the past years, the investment was for superficial foreign investors, the investment was for SEZs, the investment was for people who were rich and who were powerful.

The Budget was decided not in Delhi. It was decided in Mumbai, in Dalal Street and all *dalals* got together to control this country's Budget. It is sad when the Prime Minister very categorically said, which is a negative point and I do not support if the past Government had done this, that the NDA controlled inflation by keeping the support price to farmers depressed. But what are you doing now? You are taking the very land the farmer depends on for his survival and giving it to SEZs and big companies. In which way do you want to show that you want to bring about a collective change?

This loan waiver is simply a sinister move to confuse the people. This is to spoil the habit of the small and the marginal farmers that if you do not pay your loans, if you become a conscious defaulter, if not today, tomorrow, two years later, five years later a Government will come with a brilliant Finance Minister like Mr. P. Chidambaram who will waive the loans.

But who benefits from this? It is those farmers who have some kind of clout with the banking fraternity, with small politicians, with the goons in the villages, who know that their homes or their lands will not be mortgaged. They are the defaulters and they will be probably the ones who will be mostly benefited. But the real farmer who goes to the extent of committing suicide never defaults. He goes out of his way to ensure that the loan is paid back on time because he is scared for his daughter's marriage, for his son's education, for his home, for everything and he is not the one who is going to benefit. So, by this kind of a largess which is definitely welcome, they are also spoiling the habit of the farmers, they are also spoiling the habit of the people at large.

The people are talking and saying that this is a clever trick.[r42]

17.00 hrs.

What is the trick? If you have a loan of Rs. 15,000, your loan is waived. If a big industrial magnate has Rs. 30,000 crore as loan, if his loan is waived, you have no reason or no right to complain about that. So, you are creating a mindset where waiving of loans is acceptable and is condoned by the lowest of the low, the poorest of the poor of this country. This is a dangerous move, if you keep the future of the nation in mind.

In the matter of energy transmission and distribution, in the Budget speech it was admitted that heavy investment, has to be made in this sector. We are now talking about the longevity of this Government and if the Left ever has shown any courage or any guts and whether it has the stamina to pull the rug from under this UPA Government. But, we all know that they cannot. The ground, what they claim, is the nuclear deal with the US. First of all, I do not know why it is called 'with the US' because it is simply a nuclear deal which is applicable to probably all countries. But anyhow this World Bank employee-led Government

decided that it will be called the nuclear pact with the US. When you are not investing in energy transmission and distribution, you want to go and sign a nuclear treaty with other countries. But, have you made the simplest research of what is the requirement of energy for this nation in the coming decade, for the next ten years? Has there been a White Paper in this Parliament, by the Prime Minister or by the Energy Minister as to what will be the requirement of energy for the development of this country for the next 10 years, for the next 20 years? As far as I know, no such thing has been done. So, we are playing football without knowing where the goalpost is.

Similarly, when we take this loan waiver, are we aware of what is the total quantum of cooperative loans in this country? What is the total quantum of other institutional loans in this country? Has it been given to Parliament? Have we, the people's representatives, been enlightened? Has it been given to the media to enlighten the common people? Nothing of this sort has been done. Sir, Rs. 60,000 crore is a figure out of thin air. Obviously, as many learned speakers before me have said, no sources of funding have been highlighted. When the whole world is investing for greener sources of energy, alternative sources of energy, it finds no mention in this Budget. We live in a world where in the foreseeable future, known sources of carbon fuel will be depleted, will be finished. But, what are the alternatives? Have we started investing for them? We have not.

I would like to come to the specific issues of my State. My State of Orissa has NSSF loans to the tune of Rs. 1997.24 crore outstanding as on 30.9.2007. This loan carries a high rate of interest of 10.5 per cent. In the interest of the State that is on the threshold of a major launch forward, it is necessary that the Central Government allow us, allow the Government to swap as a part of the Orissa Socio Economic Development Programme, at least 60 per cent under the Structural Adjustment Support from the World Bank. This means that we must be allowed to prepay this loan of 10.5 per cent because in the open market you can today avail loans at a much lower rate of interest.

Similarly, as suggested by NDC Sub-Committee in their Memorandum No. F-18/1/2005/NS2/volume II of February 12, 2007, the State must be allowed to prepay high-debt, high-cost non-NSSF loans also.[r43]

At face value, this is a good budget. But whenever we hear the hon. Finance Minister talks about his achievements, he always talks about the 'eight point something' growth rate in GDP. But unfortunately when all of us, including the hon. Finance Minister go to our constituencies, we somehow have failed to see where this 'eight point something' growth rate has manifested itself. It is probably that in a country with 120 crore people, only eight per cent of the population is benefiting from this GDP growth and the rest 92 per cent of the people are desperately trying to make sure their ends meet.

Sir, Orissa has vast coal reserves and as a power surplus State, it has the capacity to export energy to other States, and we are exporting energy to other States also. But unfortunately, the system is that that the electricity duty is collected by the importing State and not by the State which is exporting. We are the ones who are losing out our natural resources like coal and we are the ones who are condemned to suffer the externalities like environmental pollution and damage to water, air and environment but the advantage goes to those States which import power from us. Sir, if 1,000 MW of power is generated in Orissa and evacuated, the importing State gets Rs. 100 crore as electricity duty. Under this circumstance, it is necessary that the situation should be reversed. The Central Government has to think of giving at least 20 per cent power free to Orissa from any unit that is using coal and resources of Orissa and exporting it outside the State. If they cannot give 20 per cent power, they must allow the State to levy a duty on generation.

The Central Sales Tax is phased out. We all know that it has already come down from four per cent to three per cent. This commencement of reduction is affecting not only Orissa but I assume it is affecting all the States.

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, kindly allow me to speak for a couple of minutes more.

Sir, because of this huge loss sustained by the State, the CST loss must be compensated by the Union Government in the form of cash. The Orissa Government has budgeted Rs. 1,321.39 crore for 27 externally-aided projects in 2008-09. The Central assistance is only anticipated, and we do not know what kindness will be shown to us because in this Budget, somehow Orissa has not got anything. The Central assistance that is anticipated is Rs. 1,262.86 crore. Of these 27 projects, 14 projects are on-going. Out of the rest 13 projects, one project has been accorded clearance by the Central Government, and the rest 12 projects are awaiting clearance from the Government of India. These 12 projects should be expeditiously cleared by the Central Government.

MR. CHAIRMAN : Now, I am going to call another hon. Member to speak.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I have only one last point.

Although coal, iron ore, bauxite and chrome are contributing 98 per cent of mining revenues, the royalty on iron ore is being levied on tonnage basis and chrome ore is being determined on a ridiculously low rate determined by the Indian Bureau of Mines. There is a demand of the people of not only from Orissa but also our neighbouring States. [h44]

Our State Government has written to the Central Government also that the royalty for the State must be fixed keeping the market or *ad valorum* price in mind.

It is a matter of disgrace for all of us that even today, in the 21st Century, we still take out our natural resources and sell it without getting the proper price. We talk about poverty; we talk about backwardness; we talk about trying to develop people; but we do not enable the same people to build their own reserves, and to build their own resources by which they can build themselves.

Orissa is an ideal State, and the nation has to learn a lot from this State. If Orissa is given the strength and is supported not only financially but in every other way, it can be an ideal State in every sense, economically it can be a viable State, which can fend for other neighbouring States also. But unfortunately, the UPA Government has not thought it fit; and the step-fatherly attitude -- I do not use 'step-motherly' because why should only mothers be step...(*Interruptions*) – the discriminatory attitude of the UPA Government is strongly condemned.

I hope, after the next elections, a Government will come into existence, which will also decide that an institution like the All India Institute of Medical Sciences, an Institute of Higher Education would come up in the rural areas. We have excessive problems with doctors not willing to go to rural areas. It is necessary that the Central Government has to fund Medical Colleges at the Government level.

17.12 hrs.

(Shri Varkala Radhakrishnan *in the Chair*)

Sir, as we know that the private medical colleges take a lot of money from students, which normal middle-class students cannot afford, therefore, the Central Government has to assist the States like Orissa, to set up medical colleges whereby you can create doctors. Maybe not with the full five years, you can condense the course and create doctors, who will be willing to go to the rural areas, to fend for the poor. It is of vital importance that the Higher Institutes of Learning like IIT, IIM, AIIMS and medical colleges are set up in Orissa. I demand that they should not be set up in the urban areas. It is wrong mindset, it is a regime mindset. Let us break free of this regime mindset and let us think of the rural areas, the villages of Orissa where we should take and place these institutes so that the ensuing infrastructure also takes place in those areas.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, just in one minute, I am concluding.

Last but not least, I would suggest to the hon. Finance Minister about this waiver of Rs. 60,000 crore loan to the farmers. It is the wish of the common man of India about this Rs. 60,000 crore loan waiver that if this kind of money would have been given in the past five years to develop infrastructural facilities for farming like irrigation projects, communication, crop insurance and electricity to the farmers, then in these five years, you would have made every single small and marginal farmer of India self-sufficient; his backbone would have been strong enough to pay back all your loans; and you need not have gone in for this kind of a sinister, surreptitious move, which everybody in this House, doubts including people from your own ruling allies.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): Sir, we have all been discussing for a long time the serious crisis in agriculture sector. This requires a two-prong solution. One, pertaining to the past crisis, the debts that farmers have inherited for a long time; and two, how to tackle agriculture, making it profitable for future.

The loan waiver is addressing the first part of the problem. How to address the problems of today? I am happy that the hon. Finance Minister has conceded to our demand partially, of waiving loans to the extent of Rs. 60,000 crore.[r45]

Sir, what is the logic behind waiving the loan? It is that the farmer cannot repay the loan because they do not have income and therefore, these loans have to be written off. If this is the logic, then this logic should be applied to all the loans which fall into this category. Can we say that the farmers can pay loan to the moneylenders? Can we say that the farmers, who are holding land above 2 hectares, can afford to pay the loans? If they cannot afford to pay the loans and if the same logic is applied for waiving of certain categories of loan – if the logic is valid – then it should be applied to all categories of loans. Therefore, we have been making this demand. We have visited village after village and farmer's house after farmer's house and came to the

conclusion that the farmers will not be able to repay the loans and that is why, they should be written off. But unfortunately, what has been done now is only a partial application of this logic to some categories of loans, defying the real expectations of the people of India, the farmers of India.

This is a very important issue because in the euphoria that is going on now, the farmers are thinking that all loans have been written off because rallies have been going on, celebrations have been going on and the people are distributing sweets. The farmers are really feeling now that there is something like a festival. Diwali is celebrated once in a year; Christmas is celebrated once in a year; Id is celebrated twice in a year. But it looks as if celebrations of all the religious festivals are taking place now because huge celebrations are going on.

As per the statistics of the Government of India, 52 per cent of the farmers do not get any bank loan and therefore, they have to go to the institutions beyond bank - like moneylenders and others. That is why, in fact, the Government has launched a programme for financial inclusiveness. They realised that this was not happening. If you have accepted that, you must make sure that 52 per cent of the farmers to begin with, and all those who are now falling into this category, should be covered.

When the hon. Finance Minister announced that loans amounting to Rs. 60,000 crore would be written off, we were happy as well as wondering as to how a provision is made for it. I started looking into the Budget figures, but there is no provision corresponding to this writing off of loans. I know that the Finance Minister has been saying outside the House that he would make an announcement in the House. I think, it is the privilege of the House to know first how Rs. 60,000 crore worth of loans are going to be written off because the Finance Minister announced at the time of presentation of the Budget that this amount would be written off in the books of banks before 30 June, 2008. So, it is to be done within three months from now and in this very financial year for which the Budget is presented. Obviously, the money has to be provided in this year's Budget. Therefore, how it is going to be provided is to be seen.

Banks have been slowly recovering as a result of recommendations of Narasimham Committee I and Narasimham Committee II, capital adequacy, income recognition provisioning norms. Now if we are going to burden the banks to carry the political wish, it is going to be really a huge give away from the banking system. Therefore, we must make sure that banks are properly compensated. This sum of Rs. 60,000 crore should be provided in the manner that the Budget shows this figure. How it is going to be done should also be reflected in the Budget for us to know.

I was saying that there are two parts with respect to agriculture. The first is the waiving of loans because of the history. Now I come to the future. Agriculture has shown a growth of 2.6 per cent this year as opposed to what we were thinking of more than four per cent in this 5-year Plan period. The share of agriculture in GDP has fallen to 18.5 per cent from 36.4 per cent in 1982-83. In 25 years, the share of agriculture has fallen. As per the *Economic Survey*, 52 per cent of productive employment comes from agriculture. There may be several others who feel that it is close to or more than 60 per cent. Therefore, even if we accept 52 per cent, only 18.5 per cent it contributes to GDP while more than half of the population depends on it. Therefore, agriculture needs a different type of treatment. If we do not make agriculture a profitable enterprise, probably more and more farmers will commit suicide as it is happening now.

In fact, maybe we will have to come with a Loan Waiver Scheme every three or four years, just like we make Five Year Plan, if we do not make agriculture a profitable enterprise. Unfortunately, in this Budget, I do not see any measure which is really aimed to make agriculture a profitable enterprise. Therefore, unless you do that, this is not going to really help the farmers at all.[SS46]

In fact, irrigation is one of the key inputs that go into agriculture, and there is some outlay, which has been provided. India's per capita storage unit is 200 cubic metres whereas in the United States -- where rain and snow is almost there for the whole year as a result of which the availability of water is throughout the year -- it is 5,000 cubic metres. In India, we get water only for 15 days in a year, and that too if good monsoon is there. Therefore, we need to store water for a longer period, but the per capita storage is only 200 cubic metres. So, irrigation has to be increased on a mammoth scale. But we must make sure -- while increasing new irrigation potential -- that the irrigation efficiency of some of the existing infrastructure must also be improved, which is currently operating at a level of 15 per cent to 20 per cent. I do not see any measures in this Budget to improve the irrigation efficiency of the present infrastructure.

If you have given some loan waiver to the farmers, then you must also provide compensation for those farmers who had to commit suicide because this loan waiver scheme did not come earlier. We must give compensation to the widows of those farmers who had to commit suicide because they would not have committed suicide if this scheme was announced earlier. It is our obligation and the obligation of the Parliament to make sure that even those widows are properly compensated.

You have also talked about soil testing labs. It is a very alarming situation in India where soil is becoming totally infertile. In Punjab, which is the food bowl of India, the soil condition is so bad that the people worry that one day Punjab might become

a desert. Therefore, we must launch a major campaign for Soil Security of India to make sure that the soil conditions are properly maintained. The top soil, which really causes the fertility of the land, is the result of millions of years of activity. If it is lost, then it is lost for ever and we are not going to get it back. We really need Soil Security Mission for the country, and that really must happen very soon.

A very major problem was identified by our Prime Minister four years ago when he became Prime Minister for the first time that the major problem of our system is the delivery mechanism. Some of my fellow Members talked about the point as to what was the amount of money that was clipped before it reached the destination during Shri Rajiv Gandhi's time. Therefore, we are saying that delivery mechanism really needs improvement because we are now gauging the success of various Government programmes just by way of finding out how much more money has been provided for those programmes. We are saying that 20 per cent or 25 per cent more has been given to it than the previous year, and that is why this programme is a successful programme. Actually, we must judge the success of a programme by finding out the end use of that programme as to whether it resulted in creation of an asset and whether it really served the purpose or not. This should be the criteria to decide whether the programme is successful or not. This particular Budget does not address the issue of improving the delivery mechanism. We have talked about it, and now we want to forget about it. It is going to be a serious challenge unless we do something about it.

Kindly allow me to give one example. We all unanimously supported the National Rural Employment Guarantee Programme (NREGP) when it was launched, and when the Bill was discussed in the Parliament. I was also speaking on that particular Bill, and I was saying that let us make a provision whereby we can judge the efficacy of this programme by finding out whether the money spent on this is resulting into something that is actually intended to be done. We never did that, and now the Comptroller and Auditor General of India has also pointed out that the scheme has not been delivering all that we really wanted out of it. In spite of that, we have now decided to increase the application of the scheme throughout the country. We welcome it, but the amount of money that is spent on this must be properly evaluated.

As regards delivery mechanism, the Finance Minister in his last Budget speech talked about thinking of finding out an alternative system of dispensing with the fertiliser subsidy. It is a good idea, but today we do not have a system. In fact, I will come to that point as to how much increase in fertiliser subsidy is going to take place now.

The major challenge of the country is energy. We are all concerned that we are now importing more than 70 per cent, and in a few years we will import more than 80 per cent to 90 per cent. Therefore, energy diversification is an important challenge for us. We need more renewable energy, but I do not see any measures taken by this Government in terms of the budgetary provision to cause this energy shift from fossil fuel to cleaner forms of energy.

Power is one of the key infrastructures. The Eleventh Five-Year Plan also talks about increasing investment in the infrastructure to 9 per cent of GDP.[r47]

This is the second Five-Year Plan. In power sector, we have already got a peak level shortage of 14.8 per cent, a base level shortage of 8.4 per cent, and still, despite only mentioning about Ultra Mega Power Projects, you have not talked about how really you are going to make power sector a commercially viable proposition. In fact, transmission and distribution sector, which is the root cause of this, we lose more money, more than 50 per cent, at the end of sub-transmission and distribution. You have not taken any measures. In fact, we have APDRP. In the last Budget, the Finance Minister said that the Government is thinking of revamping it. Rather than doing that, this year we have talked about creating a new national fund.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) : It is not 'instead'; it is 'in addition' to that. Please read it again.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : We do not know what has happened to revamping. My point is that power continues to be a major challenge for us.

SHRI P. CHIDAMBARAM : It was a challenge when you were Power Minister also.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : I am only expressing my concern.

Sir, we are now talking about making education a universal right. We in the Parliament, in 2002, made amendment to the Constitution, the Eighty-eighth Amendment, saying that all those in the age group of six to fourteen will have primary education as a fundamental right. We have still not passed a law. The Government should have brought this law if they are so much concerned about education because this Parliament has made this Constitutional Amendment. We have still not given any legislative provision to this particular Constitution Amendment. Therefore, we really need to now make investment in education in a manner that will result into creation of such individuals who will be able to really be qualified to face the challenges of tomorrow.

We are seeing in many States that the teachers are not available, and teachers need training. When teachers cannot first understand something, then how can they teach? Therefore, the quality of teacher is a major challenge. I think in this education, we really need to focus on primary education. They have now decided to move from primary to little higher education. I think primary education should continue to be our focus in the next few years time under *Sarva Shiksha Abhiyan*. I hope that really continues to happen.

Sir, the other issue that concerns is the income inequality.

SHRI P. CHIDAMBARAM : Please read the entire paragraph 19. We are not moving over. Now that the infrastructure is in place, we are now emphasizing retention, improving quality of learning and then ensuring access to upper primary classes.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : While doing that, which is welcome, you must make sure that the foundation is solid and, therefore, the emphasis on that should continue to be there.

Sir, inequality is a major issue. Coming to naxalism, 160 districts out of 600, as the Home Minister pointed out the other day, as per his report to the Parliament, are naxalite-infected. I was thinking that it is such a major challenge, more than one-fourth of the districts are affected by it, there will be some budgetary provision to tackle naxalism in these districts, and to make sure that naxalism as a challenge can be met by socio-economic development. For that, we need some budgetary provision. I do not see unfortunately anything that is coming out of it. Inequality is now showing its head. The highest number of billionaires in Asia is in India and we are proud of that, but the highest number of poor in the world is also in India. This is the type of inequality. Therefore, we must make sure that this is addressed for which education is important; but more than that, employment is important. I was thinking that now all the budgetary exercises of the future must target employment creation as a major objective. Employment creation of 100 days job under NREGS, is it enough? I would say it is not enough; we really need something more and we should have gone into it.

Sir, coming to the fiscal situation, the Finance Minister has already said that under the FRBM, he has particular targets to meet. One target is reducing current account deficit from 1.4 per cent to 1.0 per cent, and fiscal deficit from 3.3 per cent to 2.5 per cent. When you are notifying the law, FRBM, you have extended the application by one more year. This year you are again saying that you want one more year to attend to these targets of FRBM to reduce the revenue deficit completely. This is a very bad precedent because if you say like that, then all other future Finance Ministers will say that they will swear by the FRBM but they will do it after one year or two years. My request is let us follow it. If you believe in it, if you really want to follow the principles, let us follow it in totality. There are so many hidden liabilities which do not reflect in the fiscal deficit. Oil Pool Account may have a deficit of 1.2 per cent of GDP.[r48]

Pay Commission liability could be as high as 0.6 per cent of GDP as has been stated by the Finance Secretary in a press interview. The Railway Minister provided Rs.500 crore in the Rail Budget for this purpose. If there is no need to provide it at all, why should it be provided in the Rail Budget? And if the Rail Budget is providing it, why is it not being provided in the General Budget? That could also be a hidden liability of at least 0.6 per cent of the GDP.

I was not only Power Minister, I was also Minister of Fertilisers earlier. I was talking to the fertiliser industry representatives who told me that the expected subsidy at the end of 2008-09 would be as high as Rs.50,000 crore. Given the way the price of crude oil is going up, the feedstock that is required to go into fertiliser industry is also going up. Food subsidy provided last year was Rs.31,545 crore. This year we have provided Rs.32,666 crore. Does this mean that the Government is going to increase the issue price of food grains? I do not think so because they are already preparing for the election. So, the Government should have provided a much higher figure because the world food prices are going up. The loan waiver of Rs.60,000 crore should also find a place somewhere in the fiscal deficit and the fiscal deficit figure should be very high. At the same time I congratulate the Finance Minister for reducing the public debt to GDP ratio which is going down. It is a good thing. But these liabilities should have been taken into account.

This year's revenue is Rs.6,02,935 crore, interest is Rs.1,90,807 crores, and debt servicing is Rs.3,35,230 crore. That aggregates to Rs.5,26,038 crore, as against a revenue of Rs.6,02,935 crore. It is in a very worrying zone. We really need to find out how we can go into it. Now you are getting a one-time amount. It is not a recurring receipt. For example, you are auctioning spectrum and you are getting money in lieu of it. That is not your revenue receipt. That is a receipt which should go for repayment of loan and that should not be shown to reduce your revenue deficit. Such receipts should be shown separately.

Inflation has already reached 5.04 per cent last week. It is a very worrying thing. I have just mentioned how the fiscal deficit would increase with an increase in the crude oil price. As a result of that the pressure on interest and commodity prices will rise as they are rising globally. You have also mentioned in your Budget speech, probably we cannot allow the rupee to keep appreciating the way it has appreciated. So, all these cumulatively will have a huge impact on inflation which again is going to hit the common man. Therefore, we really need a proper look into it.

External account is something which we have been talking about for a long time. In fact, for the first time you have shown that cost of carrying these reserves is Rs.8,200 crore. So, we are paying Rs.8,200 crore for carrying these foreign exchange reserves. I would request the Finance Minister to let us know how this has been calculated. You have excess capital flows which you were thinking in the past as a sign of showing confidence in Indian economy. As you yourself have pointed some time ago, they are also causing concern. Therefore, we really need to find out what the cost of this is and how to manage our foreign exchange reserves which are now more than 300 billion. We need a proper strategy for it.

In this Budget, the Finance Minister talked about everybody that he probably could think of, obviously so because they are all voters. But he has not talked about one category and that is of workers who work in the Gulf countries and other places. They sent 28 to 36 billion dollars this year, an amount almost two to three per cent of GDP. That category of people should receive some incentive because they work overtime, they work in adverse conditions and still send money back to their country which they never take away like the FIIs do. So, they need a separate treatment.

Growth is something which has helped the Finance Minister to give lots of benefits to many sections of the society. If growth continues to be there, we can probably look for a better day. But what is worrying now is, as he also mentioned, that it is slowing down. The global economy is slowing down and Indian economy is also not growing as fast as it had grown in the past. As the Economic Survey points out, growth in the last five years is in fact investment driven. Therefore, the savings have to grow. There has been 26 per cent to 34 per cent growth in savings. But what is worrying is the household savings have increased only by one percentage point. So, probably we need to provide incentives for households to save more. That is because they are the sustainable, long-term savers. That in turn will help to have more investment which in turn will have more growth. As you have mentioned, in the last twelve quarters you have got eight per cent growth rate.[KMR49]

Would you think we have the similar growth rate in the next 12 quarters? If not, we really need to provide for it.

SHRI P. CHIDAMBARAM : That depends on who is in the Government!

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : We will be in the Government and we would make sure that happen.

SHRI P. CHIDAMBARAM : In the NDA Government, never had, never. Go and look at the figures. NDA Government had eight per cent growth. We had 13 quarters of over eight per cent growth.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : But, Sir, the NDA Government laid down the foundation, which enabled this UPA Government to have this growth.

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, I agree. NDA laid down the foundation with 5.9 per cent growth and we are now showing 8.8 per cent growth. For NDA, who laid the foundation – Alexander, the Great; Ashoka, the Great; and Akbar, the Great laid the foundation.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : I am very happy that the Finance Minister is getting credit for some foundation that we laid down. So, we look forward to his laying down some good foundation for which he can take some credit. ...(*Interruptions*) That is what I am mentioning.

Regarding science and technology, I compliment the Finance Minister for deciding to give more scholarships for science thinking. We need scientific temperament in the country. I was expecting from the Finance Minister that he must make provisions for research and development into science and technology. I know that we have something but we really need to ensure that four to five per cent of GDP must go into research and development, if we want to reap benefit of that in future. It is the knowledge economy; it is an economy driven by new technologies. How can you not make investment into it?

There are few things on environment. I was also the Minister for Environment. I would like to thank the Finance Minister for providing some money for protection of tigers. In fact, my Party also thanks you because that was the Party symbol. I am very happy that you have given something for our Party symbol. But tiger is something which you have really decided to protect. I am happy that you are also going to protect the tigers. But, Sir, we also need more investment into forest. Forest is something which we wanted one-third of the area to be covered by forest. The report of the Forest Commission has been submitted. There is no provision for increasing the forest cover. Can you protect tigers without forest? Forest is a wild in which tigers live. If you want to protect tigers, increase the tiger cover, automatically tigers will be there. I do not see any provision in this Budget for protecting the forests. â€¦ (*Interruptions*)

Climate change is a very important issue. In fact, the Finance Minister had talked about climate change last time and this time also. But Finance Minister is not an Environment Minister. He is the Minister for Finance. I would have been happy if he had made a provision in this Budget for dealing with issues of climate change. I would really request him that in the

Supplementary Budget to make a huge provision because in climate change, adaptation is going to be a major challenge and adapting to climate change would require huge funds. Therefore, I would request him to do that.

Like we are doing gender budgeting, I hope the Finance Minister would now encourage his colleague, the Minister for Environment to come out with a green budgeting. So, we need a green budgeting to find out all the programmes that we undertake are they really green in nature which would make sure that our environment is not damaged.

The Finance Minister had talked about Economic Survey and that we must encourage public transport as opposed to private transport. What is the budgetary provision? He has not done anything on public transport but he has reduced the duty on private transport like cars. While you want to encourage public transport, the fiscal benefits are going to private transport. This is a dichotomy and I hope he would be able to work on that. About the new tax code.. ...(*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM : Excise duty on buses and chassis has also been reduced. Excise duty on cars is reduced, I believe. But excise duty on buses and chassis of buses has also been reduced.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Public transport is a much wider term.

I, being a Chartered Accountant, waiting for the new tax code. Probably, new tax code would have come. You have promised in the last Budget that it would happen in 2008. I am sure there are nine months left. I hope, Parliament would get an opportunity to look at the new tax code because in this as you mentioned the revenue foregone this year is Rs.38,107 crore as per the Receipt Budget of the Government, and you mentioned somewhere that the new tax code would take care of it. If it is so, I wish it comes sooner.

You have also mentioned in the Budget speech that we have been trying to glorify a concept called demographic dividend. [r50]

It means that we have more working population and more working population would mean that we will work when the rest of the world will not and therefore, we will benefit. That also puts premium in a way on more population. I am really concerned that we really need to take measures to control our population. Your home State has done it very effectively; of course, it lost its seats in the Parliament, in the process. But we need more population control measures; this Budget does not have any of those.

Sir, the *Economic Survey* was presented to us on the 28th of February and the Budget was presented to us – the Finance Minister did it – on 29th of February, one day later. We are thinking that when he has presented two documents in quick succession, whatever has been mentioned in the *Economic Survey* will also find a reflection in the Budget.

I will cite only a few points on which certain things were mentioned in the *Economic Survey,* but there was no mention in the Budget. They are: working hours should be increased from 48 hours to 60 hours per week and that the working hours per day should be increased from 8 hours to 12 hours; coal mines should be privatized, old oil fields should be given to multinational companies; decontrol of sugar, fertilizer, pharmaceuticals; retail and foreign equity should be encouraged to even 100 per cent in branded products; lower fiscal deficits and lower interest rates.

I just mention what is there – constraints in the agriculture modernization should be removed; open access in electricity; bankruptcy laws should be introduced, etc.

I thought, all of these will be mentioned in the Budget, but we will have to wait for a Supplementary Budget to see all this coming. Thank you very much for the opportunity given.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका):

अध्यक्ष महोदय, देश के वित्त मंत्री ने वर्ष 2008-09 के लिए अपना जो बजट पेश किया है और वाह-वाही जुटाने के लिए आम जनता की आंखों में धूल झोंक कर लोगों के भ्रमित करने का जो काम किया है इसके लिए आम आदमी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं मेरे कुछ विचार व्यक्त करना चहाता हूं **:-**

आज अपने देश के गांव टूटते जा रहे हैं। गांव बिखर रहे हैं लोग गांवों को छोड़ कर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। आज गांवों के अंदर लड़का हो या लड़की, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, कोई भी गांव में रहने के लिए तैयार नहीं है। आज ऐसी स्थिति खड़ी क्यों हुई है। कुछ सालों को छोड़ कर अधिकतर वर्षों तक पूरे देश में और राज्यों में कांग्रेस का शासन रहा है। अपना हाथ गरीब के साथ का नारा देन वाली, गरीबों की गरीबी मिटाने की बात करने वाली कांग्रेस की सारी बातें आजादी के 60 सालों के बाद भी खोखली लग रही है। कांग्रेस ने अपने हर बजट में आम जनता को लुभावनी बातों के अलावा और कुछ नहीं दिया तभी तो देश के अंदर जो विकास होना चाहिए, आम जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए, शहर और गांव जितने खुशहाल होने चाहिए उस सबके बदले आज दुख ही देखने को मिलता है और देश के वित्त मंत्री देश के अंदर भिन्न-भिन्न योजनायें बना कर "दिन में आसमान के तारे दिखा " रहे हैं जैसे कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्या गांव के अंदर प्रत्येक परिवार को 100 दिन के लिए रोजगार मिल रहा है? क्या गांव के गरीब मजदूर को सही रोजगार मिल रहा है या बड़ी-बड़ी योजनाओं के घोड़े केवल कागज पर ही दौड़ाये जाते हैं? पिछले बजट में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 100 जिले पसंद किये गये थे और इस बजट में देश के सभी जिलों में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। लेकिन 100 जिलों के

लिए जो धनराशि आवंटित की गई थी उससे पांच गुना धनराशि 500 जिलों के लिए आवंटित करनी चाहिए थी। इस बार 16 हजार करोड़ रूपया आवंटित किया गया है। अगर सही कार्य करना है तो सरकार को एक लाख हजार करोड़ रूपये की आवश्यकता पड़ेगी।

माननीय वित्त मंत्री जी ने 2007-08 के बजट में वायदा किया था कि शहरों में रहने वाले लोगों के लिए हम रोजगार उपलब्ध करायेंगे। क्या शहर में रहने वाले नवयुवकों को रोजगार मिला है। क्या मजदूरी करने वाले मेहनतकश लोगों को मजदूरी मिल रही है। आज भी हजारों की तादात में टर्नर, फिटर, वैल्डर, कारपेंटर, मकान के काम से जुड़े हुए मजदूर रोजी-रोटी की तलाश में नुक्कड़ पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। जब उसे काम नहीं मिलता तो दोपहर को दुखी हो कर वह अपने घर लौटता है। आपने तो अपने बजट में इन मजदूरों को आस बंधाई लेकिन वह आशा सफल नहीं हुई। इसी तरह पूरे देश के अंदर टैक्सटाइल मिलों का बोलबाला था। लाखों मजदूर मिलों में काम करते थे और आज देश की अधिकतर मिलें बन्द हैं और उनमें काम करने वाला मजदूर बेबस हो कर दर-दर की ठोकर खा रहा है और हर रोज उठ कर मिल के सामने देखता है और सोचता है कि कब चिमनी से धुँआ निकलेगा? चिमनी से धुँआ निकलना तो दूर हुआ बल्कि चिमनी को तोड़ कर मिलों को बंद कर उसी जमीन पर बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने के लिए जमीन बेची जा रही है। क्या कभी कांग्रेस सरकार ने सोचा है कि मिल के मजदूरों की हालत क्या होगी? वो किस तरह सुबह और रात अपने बच्चों को पालते होंगें?

आज देश में स्माल स्केल इंडस्ट्री भी धीरे-धीरे बंद होती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन से उसे टिकना मुश्किल हो गया है। बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों के सामने स्केल इंडस्ट्री अपने पाँव नहीं जमा सकती। उसे बचाने के लिए कंपीटेंट बनाने के लिए उसे और अधिक आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है। आज देश के सामने ऑटोमेटिक मशीनरी बढ़ रही है परिणामस्वरूप जहां 100-100 लोग काम कर रहे थे वहां आज पाँच या दस आदमियों से काम चल जाता है इसलिए देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। देश के नवयुवकों को बेकारी से बचाना होगा। उनके लिए नया रोजगार खोजना पड़ेगा। आज का बालक कल का भारत है और कल का भारत समृद्ध, शक्तिशाली एवं विकासशील हो, इसलिए हमें पढ़े-लिखे लोगों का उत्साह बढ़ाना होगा। आज वो नौकरी के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। तो इस तरह से मजदूरों की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। गांव में खेतों में मजदूरी करने वाले खेत मजदूर को भी उचित रोजगार नहीं मिल रहा है। उसका भी शोषण हो रहा है। साहूकार से उसे बड़े ब्याज पर उधारी लेनी पड़ती है और समय पर अपना ऋण अदा न करन पर उसे साहूकारों की मार और अपमान झेलना पड़ता है और एक दिन ऐसा आता है कि वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। परिणामस्वरूप दिन-प्रतिदिन देश में किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जब चिड़िया खेत चुग जाती है तब हमारे वित्त मंत्री जी उनके दुख दूर करने के लिए बड़े-बड़े पैकेज घोषित करते हैं। लेकिन जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, उनका क्या? उसके लिए कौन जिम्मेवार है?

आज देश के अंदर शिक्षा भी मंहगी होती जा रही है। एम.बी.बी.एस., इंजीनियर या एम.बी.ए. के लिए बड़ी-बड़ी फीस देनी पड़ती है। होशियार विद्यार्थियों का बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलता। लाखों का डोनेशन मांगा जाता है। गरीब और आम जनता ये डोनेशन कहां से लायेगी? दूसरी ओर फाइव स्टार जैसी ऐजूकेशन संस्थायें बढ़ रही हैं। बड़े-बड़े लोग अपने बच्चों को वहां एडमिशन दिला कर पढ़ाते हैं और गरीब और अमीर के बीच में पढ़ाई का फासला भी बढ़ रहा है। ये फासला कम करने की आवश्यकता है। हर किसी को एक समान शिक्षा का लाभ मिले, ऐसा प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

आज भी देश में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पीनी का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। आज भी वहां तालाब और कुंओं से पानी पीया जाता है। गुजरात जैसे भाग्यशाली राज्य इस देश में बहुत कम हैं क्योंकि आज गुजरात में नर्मदा योजना के कारण और नहरों के कारण गाँव-गाँव में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां देश के बहुत सारे शहरों में आज भी अंधेरा है वहीं गुजरात के प्रत्येक गांव में बिजी दे कर गांव वालों को बेकारी और अंधेरे से बचाया है। मेरा अनुरोध है कि गुजरात की तरह देश के अन्य सभी राज्यों और गांवों में बिजली की पूर्ति दी जाये।

देश का विकास हुआ है। आबादी बढ़ी है और आबादी के साथ-साथ बहुत सारी परेशानियाँ भी बढ़ी हैं लोग भिन्न-भिन्न रोगों से पीड़ित हैं। आज गांव में अस्पताल नहीं हैं। वे अपनी दवाई के लिए परेशान हैं तो दूसरी ओर शहरों में फाईव स्टार अस्पताल बन रहे हैं। इन अस्पतालों में आम जनता को दवाई के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आम जनता के लिए भी गांव और शहरों में सभी सुविधाओं के साथ अधिक संख्या में अस्पताल बनाये जायें।

अंत में माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि देश में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों और छात्राओं के लिए अधिक से अधिक बोर्डिंग स्कूल खोले जायें। उनको दी जाने वाली स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की जाये। बड़ी-बड़ी संस्थाओं में जो फीस भरी जाती है वह डायरेक्ट सरकार के द्वारा ही इंस्टीट्यूट दी जाये। विदेश में पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता दी जाये। बैंकों से ऋण लेने में जो मुश्किलें पड़ती हैं, उनको दूर किया जाये यानि कि खुद की गारंटी पर लोन दिया जाये एवं सभी बेकार नवयुवकों को उचित भत्ता दिया जाये। शहरीं में झुग्गी-झोंपड़ी की जगह पर अच्छे पक्के और सुविधाजनक मकान बनाये जायें। बहनों के लिए अलग से शिक्षण संस्थायें खोली जायें। सीनियर सिटीजन के लिए अधिक से अधिक ओल्ड होम्स बनाये जायें और अमरीका की तरह सोशल सिक्यूरिटी दी जाये। कानून मे परिवर्तन ला कर उनके अंतिम जीवन तक उन्हें आर्थिक सहायता मिलती रहे, ऐसा प्रावधान किया जाये। अनाथ बालकों के लिए मातरू संस्थायें बनाई जायें। मंद बुद्धि एवं अपाहिज बच्चों के लिए अधिक से अधिक संस्थायें खोली जायें और अगर किसी परिवार के मुखिया का आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसके परिवार को जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता दी जाये। इन सभा व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए बजट में योग्य धनराशि की व्यवस्था की जाये।